CHANGING SOCIOECONOMIC BASE OF HUMAN SETTLEMENT SYSTEM IN PRATAPGARH DISTRICT, U.P.

A THESIS
Submitted to the
University of Allahab
For the Degree of
Doctor of Philosophy
in
Geography

By
POONAM PANDEY

Under the supervision of
Prof. H. N. MISRA

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD

1992

अनुक्रमणिका

आभार

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण के लिये मै अपने निर्देशक परम श्रद्धेय गुरुवर डा0 एस0 एन0 मिश्रा, रीडर भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (सम्प्रति प्रोफेसर एव अध्यक्ष, भूगोल विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला) के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करती हूँ जो शोध की दिशा मे मेरी प्रेरणा के श्रोत रहे है एव जिनके अमूल्य निदेशन, अक्षुण्ण प्रेम, अनवरत प्रयास एव प्रोत्साहन से ही वर्तमान शोध प्रवन्ध का यह स्वरूप सम्भव हो सका है । साथ ही मै भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद नई दिल्ली के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सौजन्य से आर्थिक सहयोग के रूप मे डाक्टोरल फेलोशिप मिली और शोध प्रवन्ध का अन्तिम रूप पूरा हो पाया । मै भूगोल विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो0 आर0 एन0 तिवारी एव वर्तमान अध्यक्ष डा0 एस0 सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की रचना मे विश्व विद्यालयी आर्थिक सहयोग दिलाकर मेरे प्रयास को सफलता प्रदान की है ।

मै शान्ति की प्रतिमूर्ति श्रीमती शान्ती मिश्रा एव उनके बच्चों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से मुझे सदैव प्रोत्साहन दिया एव शोधकार्य की पूर्ति मे अनन्य सहयोगी बनी रही है ।

मै डा0 जसराज शुक्ला, प्रवक्ता साकेत महाविद्यालय फैजाबाद एव कनिष्ठ अनुसधान सहयोगी श्री विनोद तिवारी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य मे अपना सहयोग निरन्तर दिया है। शोध परियोजना के टकण के लिये मो0 राशिद एव मानचित्र आरेखन के लिए मै राजेश श्रीवास्तव एव अनवर को बगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकती जिन्होने शोध प्रबन्ध के वर्तमान स्वरूप को तैयार करने मे अपना सहयोग प्रदान किया है । साथ ही मै अपने अन्य अनुसधान सहयोगियों और मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने शोध प्रबन्ध के समापन मे कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिया है ।

अन्त मे मै अपने पूज्य पिताजी, माताजी, तथा भाईयों एव बहनों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य की लम्बी अवधि मे भी मेरे मनोबल को ऊँचा रखने मे निरन्तर सहयोग प्रदान किया है । साथ ही मै अपने पति श्री दीपक पाण्डेय एव परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ जिनके सहयोग से शोध प्रबन्ध का यह रूप सम्भव हो सका ।

पूनम पाण्डेय

शुक्ल पक्ष, 1992

पूनम पाण्डेय

सारिणी सूची

अध्याय - 2

अध्याय - 3

अध्याय - 4

अध्याय - 5

अध्याय - 6

अध्याय - 7

परिशिष्ठ संख्या

3	प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसख्या मे लिग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर)
4	प्रतापगढ जनपद मे व्यावसायिक वर्गो मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत
5	प्रतापगढ जनपद मे उद्योगों की सख्या

LIST OF ILLUSTRATIONS

CHAPTER - 1

CHAPTER - 2

CHAPTER - 3

CHAPTER - 4

CHAPTER - 5

CHAPTER -6

अध्याय 1

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

मानव अधिवास सास्कृतिक भूदृश्य के सबसे आकर्षक केन्द्र है (हैमड, 1982) तथा स्थानिक सगठन मे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है । विकास की समस्त योजनाओं का प्रभाव मानव अधिवास के क्रोड मे ही प्रस्फुटित होता है । ये मुख्यत प्रादेशिक अर्थव्यवस्था की उपज है और प्रादेशिक अर्थव्यवस्था मे होने वाले परिवर्तन मानव अधिवास के सामाजिक व आर्थिक आधार मे परिवर्तन लाने की क्षमता रखते है । लगभग विगत चार दशको मे मुख्यरूप से पचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ कई सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन हुये है । इस परिवर्तन से क्षेत्रीय सरचना एव सस्था - दोनों की स्थिति मे सुधार हुआ है जिसका अधिवास तत्र पर पर्याप्त प्रभाव पडा है । किन्तु परिवर्तन लाने वाले कारकों एव परिवर्तन से उद्भूत प्रभावों का अध्ययन उचित परिप्रेक्ष्य मे नही किया गया है । वास्तव मे मानव अधिवास के अध्ययन को उस समय समुचित स्थान प्राप्त हुआ जब 1976 मे वैकूवर मे अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिवास सम्मेलन सम्पन्न हुआ और विश्व के 138 देशों ने इस सम्मेलन मे भाग लिया (हरडोय तथा सैटर्थवेट 1981) ।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मानव अधिवास के सामाजिक व आर्थिक आधारों मे होने वाले परिवर्तन की गति, दिशा तथा कारकों का स्थानिक एव कालिक दृष्टि से अध्ययन करना है । अध्ययन के मुख्य लक्ष्य बिन्दु इस प्रकार है -

1 मानव अधिवास तत्र का विश्लेषण करना

2 मानव अधिवास के सामाजिक - आर्थिक आधारों के रूपान्तरण मे लगे हुये प्रक्रमों को स्पष्ट करना ।

3 सामाजिक - आर्थिक रूपान्तरण से उद्भूत विकास विषमता के प्रतिरूप का सीमाकन एव विश्लेषण करना ।

4 मानव अधिवास व क्षेत्रीय सगठन सम्बन्धी कुछ नीतिपरक संस्तुतियों का उल्लेख करना ।

अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध मे अधिवास सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख आवश्यक है क्यों कि इनकी समीक्षा से सकल्पनाओं के विकास एव परीक्षण मे सुविधा होती है ।अधिवास सम्बन्धी कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का यहाँ पर संक्षिप्त अवलोकन किया गया है

(1) वर्गीकरण का सिद्धान्त - अधिवास के वर्गीकरण का आधार अलग अलग है । सामान्यत अधिवासों को ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है किन्तु यह वर्गीकरण अपने आप मे बहुत ही अपर्याप्त है । अधिवासों के वर्गीकरण के लिए कतिपय विद्वानों ने कुछ विधियों का प्रयोग किया है । कुछ विद्वान उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण करते है । बस्तियों के आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है । उदाहरण के लिये पुरवा, लघु ग्राम, दीर्घ ग्राम, कस्बा, नगर, नगरमाल अथवा मेगालोपोलिस इसी प्रकार के वर्गीकरण है । किन्तु यह सभी प्रकार के वर्गीकरण चाहे वह जनसख्या के आधार पर हों अथवा अवस्थिति के आधार पर हों - मुख्य रूप से गुणात्मक प्रकार के वर्गीकरण कहलाते हैं । अधिवासों के वर्गीकरण को परिमाणात्मक आवरण प्रदान करने के लिये वर्गीकरण के कई उपागम प्रयोग मे लाये गये है । यह उपागम वास्तव मे सिद्धान्त के रूप मे स्थापित हो चुके है (हैमण्ड, 1982) । हैरिस (1943) ने व्यवसाय के आँकडों के आधार पर सयुक्त राज्य अमेरिका के अधिवासो का विभाजन किया है । और इसके लिये उन्होने व्यवसाय मे लगी हुई जनसख्या का कुछ प्रतिशत निश्चित किया जो वर्ग विशेष के नगर के लिये आवश्यक था ।किन्तु हैरिस का यह वर्गीकरण कई कारणों से उचित नहीं प्रतीत होता । इससे अधिवासों के कार्यों के महत्व का न तो सही उद्घाटन हो पाता है और न ही सभी प्रकार के नगरीय कार्यों का यथोचित मूल्याकन हो पाता है, क्योंकि यह वर्गीकरण मुख्य रूप से एक समय विशेष के सीमित आकडों पर आधारित है । पावनाल (1953) ने व्यवसास मे लगी हुयी जनसख्या के औसत के आधार पर नगरीय अधिवास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया ।

नेल्सन (1955) ने गणितीय औसत एव प्रामाणिक विचलन के आधार पर एक अन्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो काफी प्रचलित हुआ । किन्तु मोसर तथा स्काट (1961) ने एक अत्यन्त व्यापक स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसमे विविध प्रकार के सामाजिक व आर्थिक आकडों को आधार बनाया गया है । इस वर्गीकरण मे उन्होंने 57 चरों का प्रयोग कर प्रिंसिपल कम्पोनेन्ट विश्लेषण विधि के आधार पर ब्रिटेन के नगरों को 14 वर्गो मे विभाजित किया । नगरीय अधिवासों के अधिकाश कार्यात्मक वर्गीकरण इन्ही मे से किन्ही एक विधि का अनुसरण करते है ।

(2) अधिवास - आकार सिद्धान्त - अधिवास आकार का सिद्धान्त मुख्यत अधिवासों मे रहने वाली जनसख्या पर आधारित है । अधिवासों की जनसख्या एक प्रकार से पदानुक्रम की द्योतक है और इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धान्त महत्वपूर्ण है

(अ) कोटि-आकार नियम - यद्यपि की ओरवास महोदय ने सन् 1913 मे सर्वप्रथम अधिवास की जनसख्या और उस पर आधारित कोटि मे सम्बन्ध देखा, किन्तु इस नियम का विशद प्रतिपादन एव प्रयोग सर्वप्रथम जिफ महोदय (1949) ने किया । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि एक क्षेत्र विशेष के सभी ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों का उनकी जनसख्या के आधार पर कोटिक्रम निर्धारित की जाये तो 'न' कस्बे अथवा अधिवास की जनसख्या उस क्षेत्र मे पाये जाने वाले सबसे बडे अधिवास की जनसख्या का 1/न वॉं भाग होगी । क्षेत्र विशेष के दूसरे महत्वपूर्ण अधिवास की जनसख्या सबसे बडे अधिवास की जनसख्या की आधी होगी । वास्तविकता यह है कि इस पदानुक्रम के ऊपरी सतह पर अधिवासों की सख्या कम होगी और निचली सतह पर यह सख्या बढती जायेगी । यह भी देखा गया कि कभी कभी यह वितरण सीढी के आकार का भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर कई अधिवास हो सकते है । इस सदर्भ मे कोटि-आकार क्रम के कई प्रतिरूप (चित्र 1.1) देखे जा सकते है । वास्तविकता यह है कि यह प्रतिरूप वास्तविक धरातल पर बहुत कम खरे उतरते है । फिर भी यह नियम बहुत उपयोगी है, क्योंकि वास्तविकता एव आदर्श का विचलन इससे स्पष्ट होता है और उसके लिये प्रक्रम एव कारणों का स्पष्टीकरण खोजा जा सकता है (एच0 एन0

HYPOTHETICAL RELATIONS
BETWEEN CITY SIZE AND RANK
A
CITY POPULATION
PRIMATE CITY
RANK
B
100
10
0
10
100
RANK LOG SCALE
C
LOG OF CITY SIZE
BINARY
PATTERN
RANK SIZE PATTERN
PRIMATE
PATTERN
LOG RANK
D
LOG OF CITY SIZE
t3
t2
t1
LOG RANK
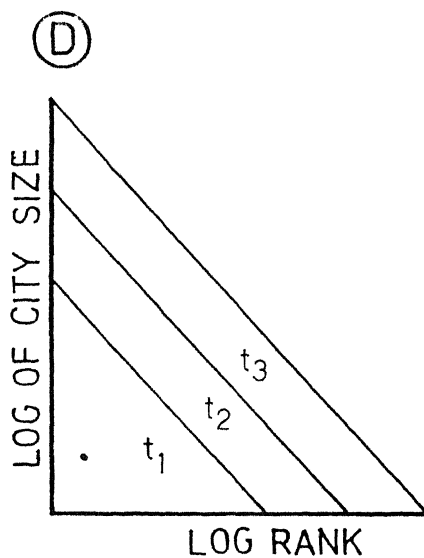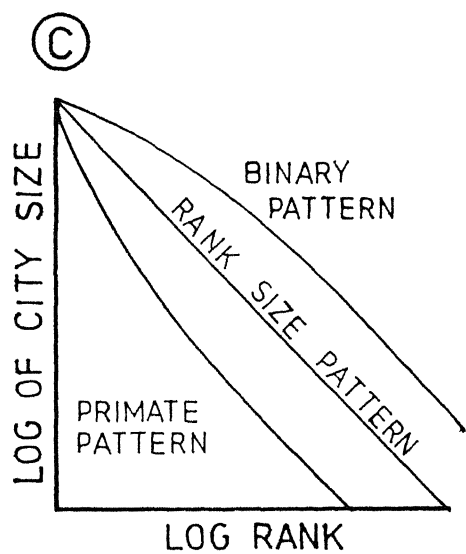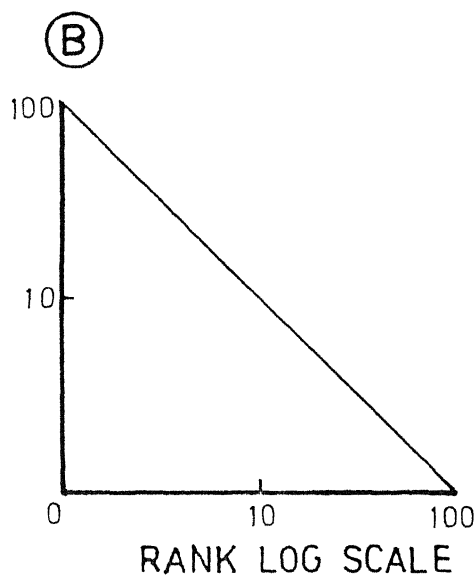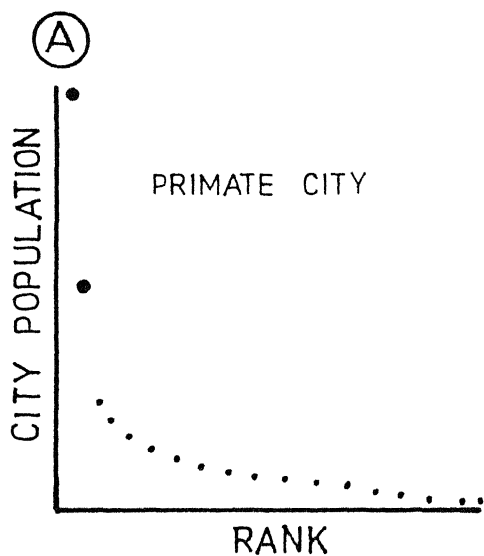
Fig 11

मिश्रा 1975)। कोटि - आकार नियम को प्रदर्शित करने के लिये अधालिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है

$$P_r = \frac{P_1}{r^q}$$

जहा r - जनसख्या कोटि-क्रम ।

P_1 = सबस बडे अधिवास की जनसख्या, तथा

P_r = r क्रम पर अधिवास की जनसख्या

(ब) प्राथमिक नगर का नियम - प्रस्तुत नियम का प्रतिपादन जैफरसन महोदय (1939) ने किया था । इस नियम को स्पष्ट करते हुये उनका विचार था कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक कारकों के फलस्वरूप कोई एक नगर बहुत अधिक बडा हो जाता है । वह इतना अधिक बढ जाता है कि आस पास के अधिवास आकार और कार्य मे उससे बहुत छोटे हो जाते है । यह सबसे बडा नगर ही उस क्षेत्र का प्राथमिक नगर कहलाता है । अनेक विकासशील देशों मे इसी प्रकार का प्रतिरूप दिखाई पडता है । स्वय भारतवर्ष मे और भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों एव औद्योगिक प्रदेशों मे यह प्रतिरूप दिखाई पडता है । कुछ भूगोलविदों मे जिनमे लिन्सकी (हैमन्ड 1982) का नाम प्रमुख है, का विचार है कि विकासोन्मुख देशों मे वाणिज्य एव औद्योगिक विकास के फलस्वरूप कोटि आकार नियम ही लागू होता है । किन्तु कई देशों मे उदाहरणार्थ, ईरान, कोलम्बिया, पेरू, बेनेजुयेला, नाईजीरिया तथा अल्जीरिया मे प्राथमिक नगर की सकल्पना ही अधिक वास्तविक प्रतीत होती है । इन नियमों को कही भी सामान्यीकरण के आधार पर प्रस्तुत करना उचित नहीं है । भिन्न भिन्न क्षेत्रों मे इनके उपयोग का परिणाम भी भिन्न भिन्न होता है ।

(3) अधिवास, अवस्थिति तथा वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त - अधिवास अवस्थिति तथा वितरण सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों मे क्रिस्ट्रालर तथा आगस्ट लॉश महोदय के सिद्धान्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि क्रिस्ट्रालर ने मुख्य रूप से सेवा केन्द्रों के वितरण का सैद्धान्तिक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है तथापि उनका यह सिद्धान्त समस्त अधिवासों के वितरण के

MODEL S OF SETTLEMENT SYSTEM
LOSCH'S MODEL
(A)
(B)
CITY RICH SECTOR
CITY-POOR SECTOR
(C)
CITY-RICH SECTOR
CITY-POOR SECTOR
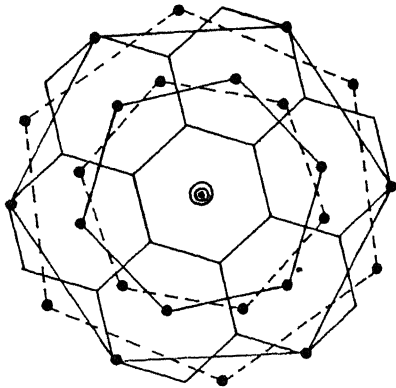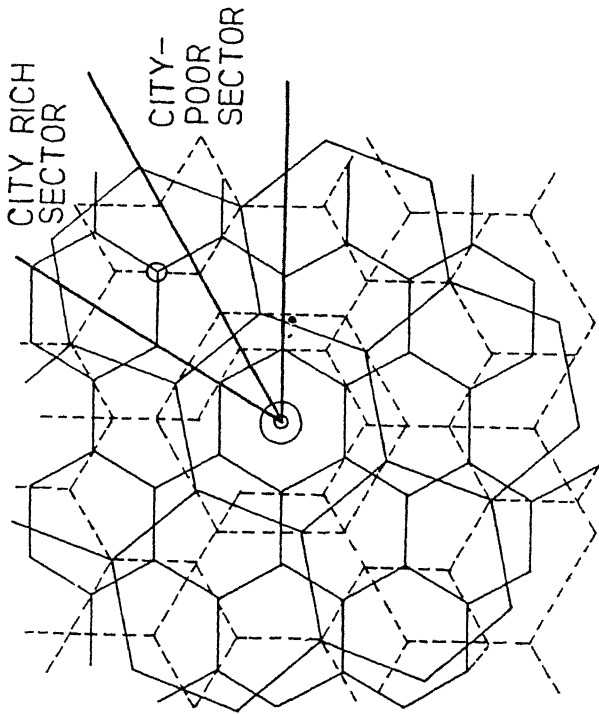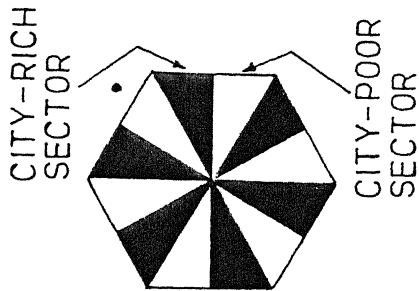
Fig 12

विश्लेषण मे महत्वपूर्ण एव निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है । एक अधिवास जब एक या एक से अधिक सेवाये प्रदान करता है, तो उसे सेवाकेन्द्र कहते है । सेवाकेन्द्र अथवा अधिवास की जनसख्या और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं मे सामान्यत धनात्मक सम्बन्ध होता है । इस प्रकार यदि सेवाकेन्द्र छोटा होता है तो उसमे सेवाये कम होती है और यदि सेवा केन्द्र बडा होता है तो उसमे अधिक सेवाये उपलब्ध होती है । और यह ही पदानुक्रम का प्रतीक है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी सेवा के लिये कुछ निश्चित जनसख्या का होना आवश्यक है । वह जनसख्या जो किसी सेवा को जीवित रखने के लिये आवश्यक है उसे "मिनिमम थ्रेसहोल्ड" के नाम से जाना जाता है ।

क्रिस्टालर महोदय ने दक्षिणी जर्मनी के अनुभव के आधार पर सन् 1933 मे एक सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन किया था जिसे केन्द्रीय स्थल - सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है । यह सिद्धान्त वॉन थ्यूनन (1826) तथा गालपिन (1915) द्वारा प्रतिपादित सकल्पनाओं को अपने मे समाहित किये हुये है । इस सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत करने मे उन्होंने एक ऐसे धरातल की कल्पना की जहाँ की धरातलीय बनाबट, सरचना, ससाधन, मिट्टी, जलवायु तथा जनसख्या इत्यादि सर्वत्र समान है । इस धरातल को उन्होंने 'आइसोट्रापिक' धरातल की सज्ञा दी है । क्रिस्ट्रालर महोदय ने यह भी माना कि इस प्रकार के धरातल पर पाये जाने वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताये, रूचि इत्यादि समान है तथा किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिये वे कम से कम दूरी तय करना चाहेगे । क्रिस्ट्रालर महोदय ने षटभुजीय विपणन क्षेत्र की भी परिकल्पना की है क्योंकि यह सबसे उपयुक्त आकार है, जिसमे धरातल का सम्पूर्ण भाग पूरी तौर पर बिना किसी "ओवरलैप" अथवा "गैप" के अच्छी तरह से सेवा प्राप्त कर सकता है । उनका यह भी विचार है कि अधिवास सेवाकेन्द्र के रूप मे जो वस्तु अथवा सेवाये प्रदान करते है, उनका सेवा क्षेत्र या विपणन क्षेत्र अल्ग-अलग आकार का होता है । छोटी वस्तु का बाजार क्षेत्र छोटा होगा और मूल्यवान वस्तु का बाजार क्षेत्र बडा होगा । अधिवास जितना बडा होगा उसकी सेवाये भी उतनी ही अधिक होंगी । परिणामस्वरूप अधिवासों मे एक प्रकार का सोपानक्रम पाया जाता है एव षटभुजीय सेवा केन्द्र भी इस सोपान

MODEL OF SETTLEMENT SYSTEM

CHRISTALLER'S MODEL

(A) MARKET PRINCIPLE (K=3)

(B) TRAFFIC PRINCIPLE (K=4)

(C) ADMINISTRATIVE PRINCIPLE (K=7)

KEY
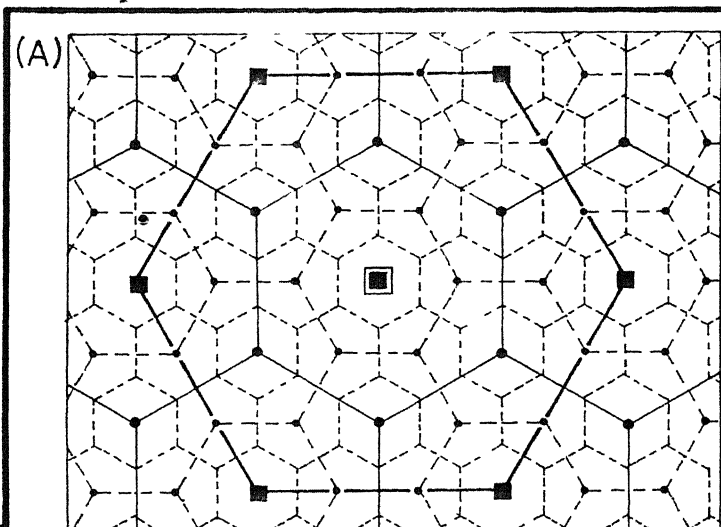
Symbol	Meaning	Line	Meaning
▣	City	———	Boundary of city market area
■	Town	———	Boundary of town market area
•	Village	– – –	Boundary of village trading area
·	Hamlet	- - - - - -	Boundary of hamlet market area

(B)
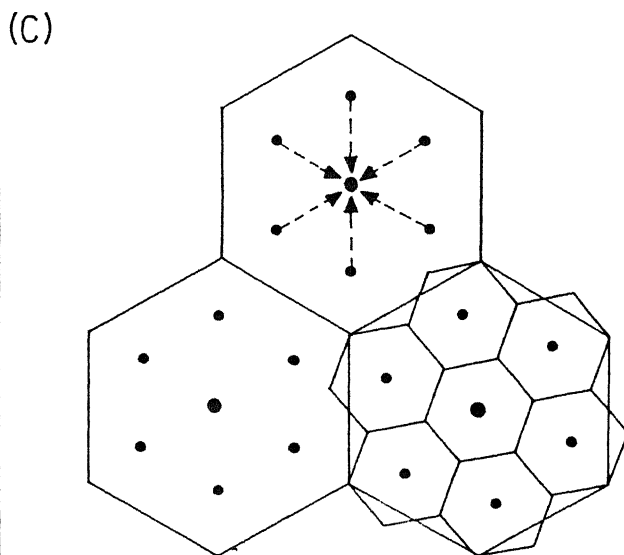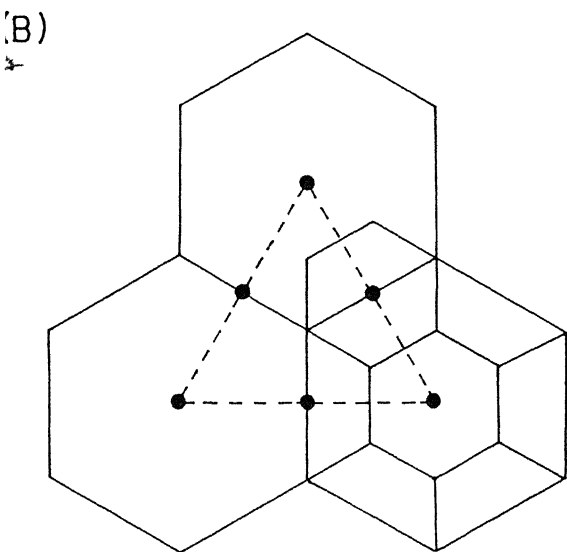
Fig 13

क्रम की प्रक्रिया से प्रभावित होते है । निश्चित प्रकार के अधिवास एक निश्चित प्रकार के कार्य और सेवाये सम्पादित करते है । उनका सेवाकेन्द्र भी समान होता है और उन सेवा क्षेत्रों मे अन्तर भी समान होता है । क्रिस्ट्रालर महोदय ने अधिवासों के सात क्रम निश्चित किये है । उन्होने अधिवासों के सोपानक्रम के **निर्धारण** मे तीन नियम प्रतिपादित किये है (अ) विपणन अथवा बाजार नियम के अन्तर्गत अधिवासों का वितरण क = 3 सिद्धान्त के आधार पर होगा, जिसमे एक क्षेत्र विशेष मे वितरण का क्रम 1,3,9,27 ------होगा । (ब) यातायात नियम जिसे क = 4 से उद्बोधित किया जाता है । इसके अनुसार सोपानक्रम की श्रेणी 1,4,16, 64 ---- होगी , (स) शासकीय नियम जिसे क = 7 भी कहा जाता है, के अनुसार अधिवासों का सोपानक्रम 1,7,49,343 इत्यादि होगा । इन तीनों नियमों के अनुसार अधिवासों का वितरण तथा उनका सेवा क्षेत्र चित्र सख्या 1 2 द्वारा स्पष्ट किया गया है । लॉश (1954) ने क्रिस्ट्रालर की इस सकल्पना को सशोधित और परिमार्जित करने का प्रयत्न किया । यद्यपि उन्होंने षट्भुजीय आकार के सेवाकेन्द्र की परिकल्पना की किन्तु वे जनसख्या के समान वितरण की सकल्पना तथा अधिवासों के वितरण मे क्रिस्ट्रालर द्वारा प्रतिपादित स्थिर सोपानक्रम से सहमत नहीं थे । उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का आर्थिक भूदृश्य प्रस्तुत किया (चित्र 1 3) । क्रिस्ट्रालर और लॉश महोदय के सिद्धान्तों की अनेक आलोचनाये और प्रत्यालोचनाये हुयी, क्योंकि जिस प्रतिरूप की परिकल्पना इन दो विद्वानों ने की है वास्तविक धरातल पर वह खरी नहीं उतरती । किन्तु फिर भी जिस आदर्श प्रतिरूप को इन दो विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, उससे वास्तविक मापन को बहुत महत्वपूर्ण आधार मिलता है । अधिवास सम्बन्धी विभिन्न आयामों को सैद्धान्तिक प्रारूप प्रदान कर इन दोनों विद्वानों ने विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रतिपादित करने का आधार प्रदान किया है ।

क्रिस्ट्रालर द्वारा प्रतिपादित केन्द्र - स्थल सिद्धान्त को कुछ विद्वानों ने परिमार्जित एव सशोधित कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिसमे बेकमैन (1958), बेरी तथा गैरीसन (1958), डेसी (1966), बेकमैन एव मैकफरसन (1970) एव बेगुईन (1972) का विशेष स्थान है । अनेक विद्वानों ने क्रिस्ट्रालर के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों मे आदर्श एव वास्तविक वितरण

प्रतिरूपों के विचलन का अध्ययन करने का सराहनीय कार्य किया है जिनका उल्लेख करना ही अपने आप मे एक शोध प्रबन्ध होगा (मिश्रा, 1984) ।

4 कार्यात्मक-सम्बन्ध सिद्धान्त - यह सिद्धान्त इस सकल्पना पर आधारित है कि कोई भी सेवाकेन्द्र अथवा नगर पृथक रह कर जीवित नही रह सकता है (जेफरसन 1931) । वह किसी क्षेत्र के कार्यात्मक परिधि मे ही रह सकता है और वह अपने चारों ओर विस्तृत क्षेत्र से भौतिक, आर्थिक एव सामाजिक रूप से सम्बन्धित होगा । कृषि,उद्योग, व्यापार तथा यातायात पर आधारित अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध कार्यात्मक प्रदेशों को जन्म देते है । यह कार्यात्मक प्रदेश अमलैण्ड, प्रभाव क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, नगर प्रभाव क्षेत्र इत्यादि जैसे विभिन्न नामों से जाने जाते है । सम्बन्धों के निर्धारण एव सीमाकन मे विद्वानों ने विविध विधियों का प्रयोग किया है । मूलतया इन्हे गुणात्मक एव परिणात्मक उपागमों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । सामान्यतया नगरों के कार्यात्मक प्रदेशों का सीमाकन गुणात्मक विधियों से किया जाता है, किन्तु कुछ परिमाणात्मक विधियाँ भी प्रयोग मे लाई गयी है, जिसमे 'ब्रेकिग प्वाइन्ट समीकरण'एव ' गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त ' पर आधारित 'माडल' विशेष रूप से उल्लेखनीय है (मिश्रा, 1971 तथा 1984) । यह उल्लेखनीय है कि क्रिस्ट्रालर तथा लॉश द्वारा प्रतिपादित षटभुजीय क्षेत्र ही कार्यात्मक क्षेत्र नहीं हो सकते, बल्कि उनका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है । नगर अधिवासों के कार्यात्मक क्षेत्र का आकार वहाँ पर पाई जाने वाली सुविधाओं, व्यावसायिक सरचना, प्रदेश अथवा प्रभाव क्षेत्र की जनसख्या के घनत्व की विशेषताओं पर आधारित होता है । अधिवासों के कार्यात्मक प्रदेश के सम्बन्ध मे बेसिक तथा नानबेसिक सकल्पना का उल्लेख आवश्यक है क्योंकि किसी भी नगर की बेसिक जनसख्या पर ही उसका कार्यात्मक प्रदेश आधारित होता है । यदि बेसिक जनसख्या अधिक होगी तो कार्यात्मक प्रदेश बडा होगा और यदि बेसिक जनसख्या छोटी होगी तो कार्यात्मक प्रदेश छोटा होगा । बेसिक तथा नानबेसिक सकल्पना मुख्य रूप से नगर की व्यावसायिक सरचना मे लगी हुयी जनसख्या पर आधारित होती है । इस सकल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख अलैक्जैण्डरसन (1956) तथा उलमैन व डेसी (1960) ने किया । इसका सविस्तार उल्लेख एच0 एन0 मिश्रा

(1986) ने अपने एक लेख मे किया है । इस सकल्पना के अनुसार किसी भी व्यावसायिक नगर मे मुख्य रूप से दो तत्वों का विश्लेषण होता है -

(अ) बेसिक जनसख्या व्यावसायिक जनसख्या का भाग है जिसे आधारभूत जनसख्या कहते है । यह वह जनसख्या है जो वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात मे लगी हुयी है तथा जिसके फलस्वरूप आस पास के क्षेत्र से नगर को आर्थिक आधार प्राप्त होता है ।

(ब) नानबेसिक जनसख्या - व्यावसायिक सरचना का दूसरा वर्ग होता है जो कि केवल नगर मे रहने वाली जनसख्या को ही सेवाये प्रदान करता है । नगर के विकास एव वृद्धि मे इस जनसख्या की भूमिका अधिक नहीं होती है । अत इसे नानबेसिक जनसख्या कहा जाता है ।

5 विकास केन्द्र सिद्धान्त - अधिवास तत्र एव प्रादेशिक विकास मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इसी पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखकर विकास केन्द्र सकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ है । यद्यपि इस सकल्पना की कठोर आलोचना हुयी है, किन्तु फिर भी तृतीय विश्व के विकास की विचार धारा मे विकास केन्द्र की सकल्पना सबसे महत्वपूर्ण एव शक्तिशाली सकल्पना है । पेराउक्स महोदय (1950, 1955) द्वारा प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धान्त मुख्य रूप से आर्थिक सिद्धान्त है और अस्थानिक है । किन्तु सन् 1966 मे वोल्डविली ने इस सकल्पना का न केवल अनुवाद किया अपितु भौगोलिक सकल्पना के रूप मे प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया । कालान्तर मे इस विचारधारा को नियोजको मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला । भारतवर्ष जैसे देशों मे तो इसे एक वैचारिक दर्शन और क्रियात्मक भूमिका के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध मे कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसमे जानसन (1970), आर0 पी0 मिश्रा (1974, 1978), हरमनसेन (1971), कुकलिन्सकी (1971), मोसली (1971) इत्यादि के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस सिद्धान्त की मुख्य विचार धारा यह है कि केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से विकास सम्भव है । यदि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र मे विकास केन्द्र होंगे तो अपने द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक, सुविधाओं के द्वारा आस पास के क्षेत्रों के विकसित करने मे महत्वपूर्ण योगदान करेगे । अन्तर - प्रादेशिक एव ग्रामीण -

नगरीय विषमता को दूर करने मे इस सिद्धान्त को अनेक भूगोलवेत्ताओं ने बिल्कुल रामबाण के रूप मे प्रस्तुत किया है । ऐसा समझा जाता है कि विकास - ध्रुव, विकास केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा बाजार केन्द्र का पदानुक्रम मिलकर विकास की एक ऐसी श्रृखला उत्पन्न करेगा जिससे कि प्रादेशिक विकास को गति मिलेगी (मिश्रा, 1984) । किन्तु इस सिद्धान्त की कटु आलोचना हुयी । विभिन्न स्तर पर अधिवास केन्द्रों की स्थापना मे लगने वाला धन कहाँ से मिलेगा ? यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है । यह भी मूल प्रश्न है कि यदि इस प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता है तो वह केन्द्र स्वय क्यों नहीं उत्पन्न होंगे । अधिवासों का विकास क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक एव राजनैतिक सरचना पर आधारित है, और जब तक उस प्रदेश मे रहने वाली जनसख्या की आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं होगी कि वह इन केन्द्रों मे स्थित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आश्रय दे सके, इस प्रकार के सेवाकेन्द्र कभी भी विकसित नही होंगे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के केन्द्रों की उत्पत्ति एव विकास माग और आपूर्ति पर आधारित है । इसके अतिरिक्त विकास ध्रुव सिद्धान्त "टाप डाऊन उपागम" को प्रश्रय देता है जिसमे विकास की सकल्पना ऊपर से नीचे की ओर की गयी है ।

विकास केन्द्र से मिलती जुलती कई अन्य सकल्पनाये भी है जिनमे की छोटे एव मध्यम श्रेणी के नगर पर आधारित विकास तथा झुरमुट अथवा एग्रोपोलिटिन सकल्पनाये मुख्य है । छोटे एव मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास के सन्दर्भ मे दत्ता (1981), रान्डेनली (1983) तथा मिश्रा (1986) के कार्य उल्लेखनीय है । इस सकल्पना के अनुसार प्रादेशिक विकास के लिये छोटे नगरों का विकास यदि किया जाय तो विकास की गति तीव्र होगी ।

साहित्य सामग्री की संक्षिप्त समीक्षा

ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों का अध्ययन, वर्णन की दृष्टि से तो नवीन नहीं है, किन्तु भूगोल मे इनका क्रमबद्ध अध्ययन मुख्य रूप से 20वी शताब्दी के प्रथम चरण से ही प्रारम्भ हुआ । जहाँ पहले ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन को विशेष बल दिया जाता था वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् नगरीय बस्तियों के अध्ययन को विशेष महत्व मिलने लगा (जानसन 1987, मिश्रा 1989) । अधिवासों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध

से पूर्व अध्ययन का आधार केवल वर्णनात्मक था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मात्रात्मक एव विश्लेषणात्मक आधार अधिक महत्वपूर्ण हो गये है । किन्तु सन् 1960 और 1970 के बीच आचरणात्मक अध्ययन को अधिक बल मिला । वास्तव मे भूगोल के विकास का यह निर्णायक दौर था, जबकि पहली बार यह आवश्यकता समझी गयी कि अधिवासों का अध्ययन एव वर्णन ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उनकी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का उल्लेख भी परम आवश्यक है । डेविड स्मिथ (1977) के "सामाजिक कल्याण क्षेत्र उपागम" तथा प्रादेशिक समस्याओं के चित्राकन ने एक नये भूगोल को जन्म दिया जिसे "लिबरल भूगोल" के नाम से जाना जाता है । सन् 1970 के आस पास साम्यवादी भूगोल (मार्क्सवादी) को प्रोत्साहन मिला । मार्क्स का सिद्धान्त ही प्रादेशिक, मानवीय तथा अधिवासी समस्याओं के निराकरण का मुख्य आधार हो गया । डेविड हार्वे (1976) ने इसे "रैडिकल ज्योग्राफी" की सज्ञा दी है । वर्तमान मे "सरचनात्मक उपागम" को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके विभिन्न पहलुओं पर डेरिक ग्रेगरी महोदय (1978) ने विस्तार पूर्वक विचार किया है । भूगोल की इस विधा मे मानवीय निर्णय को निश्चित करने वाले कारकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है । तात्पर्य यह है कि वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन ही नहीं अपितु वितरण प्रतिरूप को जन्म देने वाले कारकों का अध्ययन होना चाहिये । वर्तमान सदर्भो मे अधिवासों के अध्ययन मे नीतिपरक आयामों पर विशेष बल दिया जा रहा है । यद्यपि कि यहाँ पर सविस्तार समीक्षा प्रस्तुत करना कठिन है तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि अधिवासों के अध्ययन मे पाश्चात्य भूगोलविदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि पृष्ठभूमि के रूप मे उल्लिखित सैद्धान्तिक योगदानों से स्पष्ट है ।

भारतीय भूगोलविदों के अधिवास सम्बन्धी अध्ययन को अधोलिखित वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है

1 उत्पत्ति एव विकास सम्बन्धी अध्ययन - प्रारम्भ मे अधिवासों की उत्पत्ति एव विकास का अध्ययन अनेक विद्वानों ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे किया । कुछ विद्वानों ने एक ही नगर अथवा ग्राम को केन्द्र मान कर उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे देखा है, किन्तु अधिकाश विद्वानों

ने अधिवासों की उत्पत्ति एव विकास का अध्ययन क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक परिवेश मे किया है और उसके आधार पर यथासम्भव भौगोलिक, सामाजिक एव आर्थिक कारकों का उल्लेख भी करने का पयत्न किया है । किन्तु इस प्रकार के अध्ययन मे मूलतया स्थान एव स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है ।

2 सेवाकेन्द्र सम्बन्धी अध्ययन - इस प्रकार के शोध अथवा अधिवास सम्बन्धी अध्ययन मुख्य रूप से क्रिस्ट्रालर के "केन्द्र स्थल सिद्धान्त" पर आधारित है । इस प्रकार के अधिवास सम्बन्धी अध्ययन मे नगरों अथवा ग्रामों को उनके द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न प्रकार की सामाजिक एव आर्थिक सेवाओं के आधार पर मूल्याकित किया गया है । अधिवासों के वर्गीकरण, वितरण, पदानुक्रम, कोटि - आकार सम्बन्ध, सेवा क्षेत्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पक्षों का उद्घाटन इसके अन्तर्गत किया गया है ।

3 प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी अध्ययन -
इस प्रकार का अध्ययन मुख्य रूप से प्रदेश अथवा क्षेत्र विशेष के योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से किया गया है । किन्तु इस प्रकार के अध्ययन मे ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों को महत्वपूर्ण इकाई के रूप मे देखा गया है । इस प्रकार के अध्ययन मुख्य रूप से ध्रुव विकास सिद्धान्त समन्वित ग्रामीण विकास तथा समन्वित क्षेत्र विकास द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एव नियमों को ध्यान मे रखकर किये गये हैं ।

4 अधिवास समस्या सम्बन्धी अध्ययन - अधिवासों के अध्ययन मे कुछ ऐसे भी अध्ययन आते है जो ग्रामीण अथवा नगरीय अधिवासों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को उजागर करते है । गन्दी बस्तियों का अध्ययन, स्वास्थ्य एव आवास का अध्ययन तथा स्वास्थ्य एव पोषक तत्व सम्बन्धी अध्ययन इसके अन्तर्गत आते है । वर्तमान मे इस प्रकार के अध्ययन का महत्व बढता जा रहा है, क्योंकि अधिवासों के सम्यक विकास के लिये इन पक्षों का विश्लेषण परम आवश्यक है । ग्राम एव नगरों का परिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय अध्ययन भी अत्यत महत्वपूर्ण एव उपयोगी हो गया है । इस प्रकार के अध्ययन नीति निर्धारण मे महत्वपूर्ण

आयाम का कार्य कर सकते है ।

भारत के जिन भूगोलविदों ने अधिवास एव प्रादेशिक विकास सम्बन्धी अध्ययन को आगे बढाने तथा नयी दिशा देने मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है उनमे मन्जूर आलम (1965), इनायत अहमद (1956), बी0 एल0 एस0 पी0 राव (1981, 84), आर0 एल0 सिह (1975), आर0 पी0 मिश्रा (1974,1978 1979, 1980), आर0 एल0 द्विवेदी (1963, 65), एस0 एल0 कायस्था (1978,1980,1981), ए0 रमेश (1964), उजागिर सिह (1961), पी0 डी0 महादेव (1980), के0 एन0 सिह (1981), के0 वी0 सुन्दरम् (1977), एल0 आर0 सिह (1958), ए0 के0 तिवारी (1982), जगदीश सिंह (1971), एच0 एन0 मिश्रा (1981, 1984, 1987, 1988), वी0 के0 कुमरा (1980) का कार्य उल्लेखनीय एव विशेष रूप से सराहनीय है ।

प्रमुख संकल्पनाएं -

अधिवास सम्बन्धी सिद्धान्तों व शोधों की प्रवृत्ति की समीक्षा तथा पर्यवेक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन मे कई सकल्पनाओं का विश्लेषण एव परीक्षण किया गया है । किन्तु उनमे से कुछ मुख्य इस प्रकार है -

1 प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मे परिवर्तन के साथ अधिवासों के सामाजिक-आर्थिक आधार मे भी परिवर्तन हो रहा है ।
2 अधिवासों का आकार और उनके सामाजिक-आर्थिक कार्यों मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ।
3 अधिवासों की सामाजिक-आर्थिक सरचना की विषमता प्रादेशिक विषमता को जन्म देती है ।

अनुसन्धान विधि एवं तकनीक

प्रस्तुत अध्ययन मे ऐतिहासिक तथा स्थानिक उपागामो का प्रयोग किया गया है । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे तथ्यों का स्थानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है । इस कार्य मे प्राथमिक एव गौण प्रकार के ऑकडों को प्रयोग मे लाया गया है । इन आकडों को गुणात्मक व

परिमाणात्क विधियों से विश्लेषित किया गया है । कई स्थलों पर कुछ विशिष्ट तकनीकों का भी उपयोग किया गया है । इनमे समीपस्थ पडोसी तकनीक, कोटि-आकार नियम तथा सह-सम्बन्ध गुणाक विधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिये अधिवास सूचकाक का उपयोग किया गया है । कई चरों के आचरण को देखने के लिये सह सम्बन्ध गुणाक का परिकलन किया गया है । खण्ड विकास स्तर पर चरों का चुनाव कर उन्हे स्कैटर डायग्राम तथा रिग्रेशन माडल द्वारा प्रदर्शित किया गया है।इसके लिये कम्प्यूटर के एस0 पी0 एस0 एस0 प्रोग्राम का उपयोग भी किया गया है । आँकडों के मुख्य श्रोत इस प्रकार है (1) जिला गजेटियर (2) जिला जनगणना पुस्तिका (3) जिला साख्यकीय पत्रिका (4) जिला वार्षिक योजना (5) जनपद की औद्योगिक प्रगति आख्या ।

विभन्न आकडों को समुचित रूप मे परिवर्तित कर उन्हे मानचित्रों एव आरेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ।

शोध प्रबंध सगठन

प्रस्तुत शोध प्रबध 7 अध्याायों मे सगठित किया गया है । प्रथम अध्याय मे अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया हे । मुख्यतया उन सिद्धान्तों का पुनरावलोकन किया गया है जो अधिवास तत्र विश्लेषण से सम्बन्धित है । द्वितीय अध्ययन मे अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत भौगोलिक बनावट, प्रवाह प्रणाली जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज मिट्टी तथा जनसख्या के वितरण का उल्लेख किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण व नगरीय अधिवास तत्र का विश्लेषण तृतीय अध्याय मे किया गया है । अधिवासों मे सामाजिक व आर्थिक परिव्र्तन देखने के लिये सेवाकेन्द्रों का चुनाव किया गया है और उनके विविध पक्षो का विवर्णन चतुर्थ अध्याय मे किया गया है । अधिवास तत्र मे होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख करने के लिये उन्हे क्षेत्रीय परिवेष मे विश्लेषित किया गया है और यह विश्लेषण पचम अध्याय मे सविस्तार प्रस्तुत किया गया है । इस विश्लेषण मे कई सकल्पनाये सह-सम्बन्धों के माध्यम

से टेस्ट की गयी है । अध्याय षष्ठम् मे सामाजिक-आर्थिक विषमताओ का स्थानिक वितरण प्रतिरूप 22 चरों के माध्यम से किया गया है । इन 22 चरों का एक मापकीय रैखिक रूपान्तरण करने के लिये "जी स्कोर विधि" का प्रयोग किया गया है । इन समस्त विश्लेषणों के आधार पर सप्तम् अध्याय मे निष्कर्ष एव नीतिपरक सस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी है जो अध्ययन क्षेत्र तथा अधिवास के समन्वीकृत विकास मे सहायक हो सकती है ।

REFERENCES

Ahmad, E.(1956), Origin and Evolution of Towns of Uttar Pradesh, **Geographical Outlook**, 1, 38-58

Alam, S.M. (1965),**Hyderabad-Secunderabad : A Study in Urban Geography**, Bombay : Allied publishers.

Alexanderson, G (1956), **The Industrial Structure of American Cities**, Nebraska, Lincoln.

Beguin. H (1979), Urban Heirarchy and the Rank-Size Distribution, **Geographical Analysis** 2.

Beckman, M J. (1958), City Heirarchies and the Distribution of City size, **Eco-Development and Cultural Change**, 6.

Boudeville, J.R. (1966), **Problems of Regional Economic Planning**, Edinburgh : University Press

Berry. B.J.L., and Garrison, W.L (1958), A Note on Central Place Theory and Range of goods, **Eco.Geog.,34**

Christaller, W (1966), **Central Place in Southern Germany** (Translated by C.W Baskin), Englewood Cliffs, New Jersey.

Dacey, M F (1966), Population of places in a Central place Heirarchy, **Jl. of Reg. Science**,6

Dwivedi, R.L. (1963), Origin and Growth of Allahabad **Ind. Geog.Jl.** 38, 16 -32

11. Dwivedi, R.L (1965), Demographic Features of Allahabad City, **Geog. Rev. Ind,** 27, 163-188

12. Dutt, S S. (1981), India's Urban feature : Role of Small and medium towns, **Jl. of the Institute of Town Planners,India,** 106, 1-7

13. Gregory, D., (1978), **Ideology,Science and Human Geography** London : Hutchinson.

14 Galpin, G.J. (1915), The Social Anatomy of an Agricultural Community, Research **Bulletin of Agricultural Experiment Station,** University of Wisconsin, Madison, vol 34

15. Hammond, C.W. (1982), **Elements of Human Geography,** Allen & unwin : London.

16 Harris, C.D. (1943), A Functional Classification of Cities in United States, **Geog. Rev**, 33, 86-99.

17 Harvey, D (1976), The Marxist Theory of the State, **Antipode,** 8 (2)

18. Hermansen, Tormod (1971) **Spatial Organization and Economic Development,** Mysore : Int. of Dev. Studies

19. Jefferson, M.,(1931) Distribution of the World's City Folks · A Study in Comparative Civilization, **Geog. Rev.**, 21, 446-454

20 Jefferson M (1939), The Law of Primate City, **Geog. Rev.,** 29, 226-232

21 Johnston, E A J (1970), **The Organization of Space in Developing Countries** Cambridge, Mass. Harvard University Press

22 Johnston, R J. (1987), **Geography and Geographers,** London : Edward Annold

23 Kumara, V K. (1980), Environmental Pollution and Human Health A Geographical Study of Kanpur City, **N.G.J.I.** 26, 1 & 2

24. Kayastha, S L and Prasad, J (1978), Approach to Area planning and Development Strategy : A Case study of Phulpur Block, Allahabad District, **N.G.J.I.,** 4

25 Kayastha, S L. and Singh, B N. (1981), Spatial Strategy for Integrated Rural Area Development A case study of Ghazipur Tahsil (U.P), India, **N.G.J.I.,** 27, 1 & 2

26 Kayastha, S.L. and Singh R B (1980), Emerging Dynamics of Integrated Rural Development, **N.G.J.I.,** 26, 3 & 4.

27 Kuklinski, A. and Petrella, R. (eds) (1971), **Growth Poles and Regional Policies,** The Hague . Mouton

28. Losch A (1954), **The Economics of Location,** (Translated by W.H. Waglam & W F. Stolper), New Haven

29 Mahadev, P.D (1978), Bangalore · A Garden city of Metropolitan Dimension in Misra, R.P. (edit) **Million Cities of India**, New Delhi · **Vikas**

30 Misra, H N (1989) Traditional and Contemporary Paradigms of Urban Geography, **Annal NAGI,** 9, 1

31 Misra, H N. (1988), The Popular Settlements of Allahabad City **CITIES - The International Quarterly on Urban Policy**, 5. No 2

32 Misra, H N. (1987), Habitat and Health in an Indian Village, in Misra, H N (ed) **Rural Geography**, New Delhi Heritage Publishers

33 Misra, H N (1986), A Model of Economic Base and its Application to the Towns of Uttar Pradesh, in Mahadev, P.D. (ed) **Urban Geography**, New Delhi : Heritage

34 Misra, H N (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed), **Small and Intermediate Urban Centres, Their role in national and regional Development in the third world,** London : Hodder and Stoughton

35 Misra, H.N (1984), Human Settlement System and Regional Development in Developing Economy, in Kammeir, H D et al (edit) **Equity with Growth, Planning Perspective for Small Towns in Developing Countries**, Bangkok AIT, 233-241

36 Misra, H N (1984) **Urban System of a Developing Economy,** Alllahabad : IIDR . and also in 1988 New Delhi : Heritage Publishers

37 Misra, H N (1981), Rural Roots of Urban Poor · A Case Study of Informal Sector in an Indian City, in Misra, R P (edit) **Rural Development and National Policies and Experiences,** Singapore : Maruzen Asia, 211-229

38 Misra, H N. (1980), **Towards Alternative Settlement Policy : The case of India,** Nagoya : UNCRD

39 Misra, H N (1975), The Size and Spacing of Towns in the Umland of Allahabad, **The Geogr.** 22, 44-55

40. Misra, R.P. et al (1980),**Multi-level Planning and Integrated Rural Area Development in India,**New Delhi : Heritage

41 Misra, R P (ed)(1979),**Habitat Asia : Issues and Responses,**1-3, New Delhi . Concept

42 Misra, R P et al (1978) Regional planning and National Development, New Delhi · Vikas

43 Misra, R.P. et al (1974)**Regional Development Planning in India : A New Strategy,** New Delhi : Vikas

44 Moser, C A & Scott, W (1961),**British Towns : A Statistical Study of their Social and Economic differences,** London : Oliver & Boyd

45 Moseley, M J A ,(1974),**Growth Centres in Spatial Planning,** Oxford : Pergman Press

46. Nelson, H J , (1955), A Service Classification of American Cities, Econ. Geogr. 31, 189-210

47. Perroux, F., (1955) La Nation de Croissance, Economique Applique Nos 1 & 2.

48 Perroux, F.,(1950) Economic Space : Theory and Application, Quarterly Jl. of Economics.

49 Pownall, L.L , (1953) The Functions of New-Zealand Towns, A.A.A.G., 43, 332-850

50 Rao, V L.S P ,(1964), Towns of Mysore State, Bombay: Asia Publishing House.

51 Ramesh, A.. (1964), Origin and Evolution of Ootaccamond, N.G.J.I. 10, 16-28

52 Rondinelli, D A., (1983), Secondary Cities in Developing Countries : Policies for Diffusing Urbanization, Beverly Hill: Sage Publication.

53. Singh, J., (1971), Rural Settlement Types and Patterns in Baghelkhand, MadhyaPradesh, India, N.G.J.I., 17, No , 4

54. Singh, K.N. (1981), Spatial Analysis of Rural Settlements and their types in Lower Ganga-Ghagra Doab, N.G.J.I. 27, No. 3 & 4

55 Singh, U, (1961), Allahabad : A Study on its Planning and Development, **N.G.J.I.,** 7

56. Singh, L R.. (1958), Rural Settlements in the Tarai Region, **Nat. Geogr.,** 3,

57. Singh, R L etal (ed) (1975), **Readings in Rural Settlement Geography,** Varanasi.**N.G.J.I.**

58 Smith, D M. (1977), **Human Geography** : A Welfare Approach, London . Edward Arnold.

59 Sundaram, K.V (1977),**Urban and Regional Planning in India, New Delhi** : Vikas.

60 Tiwari, A.K., (1982), Spatial Aspects of Rural Development in Indian Desert, **The Geographer,** 29, 26-35

61 Ullman, Edward, L and Machael F. Dacey (1960), The Minimum Requirement Approach to the Urban Economic Base, **Reg.Sci. Assn. papers and Proceedings** 175-194

62 Von Thunen, H .(1826), **Deriso-lierte State in Bezichug Hug landurirts Chaft and National Konomic, Rostak** Translated by Warteburgh C.M As von Thuman's **Isolated State,** London : Oxford university Press

63 Zipf. G.K. (1949), **Human Behaviour and Principle of least effort,** New York · Addison - Wesley.

अध्याय 2

अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय पृष्ठभूमि

विगत अध्याय मे प्रस्तुत शोध विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि का पुनरावलोकन किया गया है । यह विवेचन ही आधारभूमि की रचना करता है । प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है । इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की स्थिति, भौगोलिक परिच्छेदिका, जलवायु, खनिज, वन सम्पत्ति एव मिट्टी तथा जनसख्या वितरण प्रतिरूप का रेखाकन किया गया है ।

भौगोलिक परिच्छेदिका

स्थिति तथा विस्तार - उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी अचल मे स्थित प्रतापगढ जनपद (25^0 24' से 26^0 11' उत्तर अक्षाश तथा 81^0 19' से 82^0 27' पूर्वी देशान्तर) उत्तर मे सुल्तानपुर, पूर्व मे जौनपुर, दक्षिण मे इलाहाबाद, पश्चिम मे रायबरेली तथा फतेहपुर जनपदों की सीमाओं से आवृत्त है । पूर्व-पश्चिम 115 किलोमीटर लम्बा तथा उत्तर-दक्षिण 40 किलोमीटर चौडा यह अध्ययन क्षेत्र 3730 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है । प्रशासकीय दृष्टि से यह चार तहसीलों एव पन्द्रह सामुदायिक विकास खण्डों मे विभक्त किया गया है (चित्र सख्या 2 1 तथा 2 2) ।

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसख्या 1981 मे 18,06,833 थी जो 1991 मे बढकर 22,11,253 हो गयी है । जनसख्या का घनत्व 1981 मे 484 मनुष्य प्रतिवर्ग कि मी तथा लिग अनुपात 1016 था जो 1991 मे क्रमश 595 तथा 929 हो गया है । जनसख्या का अधिकाश भाग ग्रामीण (97 3) है । नगरीय जनसख्या केवल 2 7 प्रतिशत है । जिले मे नगरीय अधिवास की सख्या 7 है । कुल आबाद ग्रामीण अधिवास 2185 है जो 171 न्याय पचायतों तथा 1530 ग्राम सभाओं मे विभक्त है ।

धरातलीय रचना भूगर्भिक रचना की दृष्टि से यह भारत के वृहद् मैदानी भाग का उपाश है जिसका निर्माण हिम युग और उसके बाद मे गगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये निक्षेप से हुआ है (शफी, 1959 तथा नेविल, 1904) । अध्ययन क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है । इस मैदान का समतल स्वरूप गगा, सई, गोमती व

उनकी सहायक नदियों तथा नालों के कटाव से विकृत हो गया है । यह विकृति सई तथा गगा नदी के निकटवर्ती भागों मे सर्वाधिक है । बहुत से भाग इतने अधिक असमतल हो गये है कि इन पर कृषि कार्य सभव नहीं है । इन असमतल भागों मे जगल पाये जाते है । सई नदी अध्ययन-क्षेत्र को दो भागों मे विभाजित करती है । इस नदी के तटवर्ती भाग मे बलुई दुमट मिट्टी की एक पतली पट्टी है जो अधिक उपजाऊ है । इसके बाद बागर भूमि की निचली पट्टी है । रचना की दृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र को तीन प्राकृतिक प्रदेशों मे विभक्त किया जा सकता है (चित्र सख्या 2 4)

(अ) खादर क्षेत्र - खादर क्षेत्र के अन्तर्गत गगा, सई तथा गोमती नदियों का तटवर्ती भाग सम्मिलित है ।

(ब) समतल बागर क्षेत्र - सई तथा गगा के तटवर्ती खादर क्षेत्र के उपरान्त यह समतल बागर क्षेत्र तीन पेटियों मे फैला है । इस क्षेत्र की मिट्टी दुमट है जिसमे बालू के सूक्ष्म कणों के साथ उपजाऊ चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है । इस उपजाऊ मिट्टी मे स्थान स्थान पर ककड का भी मिश्रण मिलता है । साधारणतया इस ककड का उपयोग कच्ची सडकों के निर्माण मे किया जाता है । इस क्षेत्र मे आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद, कटहल, नीम आदि वृक्ष पाये जाते है ।

(स) निचला बागर क्षेत्र - यह क्षेत्र दो भागों मे विभक्त है प्रथम भाग मे सई तथा गगा नदी का मध्यवर्ती भाग है जो सई के दक्षिण तथा गगा के उत्तर मे स्थित है ।द्वितीय भाग सई के उत्तर में एक पतली पट्टी के आकार मे पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है । निचली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र मे तालाब व झीलों की अधिकता है । इस क्षेत्र मे जहा कहीं ऊची भूमि का क्षेत्र है वह मुख्यत ऊसर तथा अनुपजाऊ है निचले भाग की मिट्टी चिकनी तथा मटियार है जिसकी उर्वरता सामान्य से अधिक है ।

जल प्रवाह - अध्ययन क्षेत्र के प्रवाह प्रणाली का मुख्य श्रोत गगा, सई तथा गोमती व उनकी सहायक नदिया है (चित्र 2 5) । गगा नदी जनपद के दक्षिणी सीमा पर लगभग 56 कि मी

DISTRICT PRATAPGARH
CATEGORIES OF SOIL
N
RIVER GANGA
5 0 5 10
KM
SANDY LOAM SOIL
CLAYEY LOAM SOIL
LOAMY SOIL
SILTY CLAY LOAM SOIL
SANDY CLAY SOIL

Fig 2.3

DISTRICT PRATAPGARH
PHYSIOGRAPHIC DIVISIONS
N
RIVER SAI
R GOMTI
RIVER GANGA
5 0 5 10
KM
SAI-GANGA KHADAR TRACT
BANGAR LEVEL PLAIN TRACT
BANGAR LOWLYING TRACT

Fig 2.4
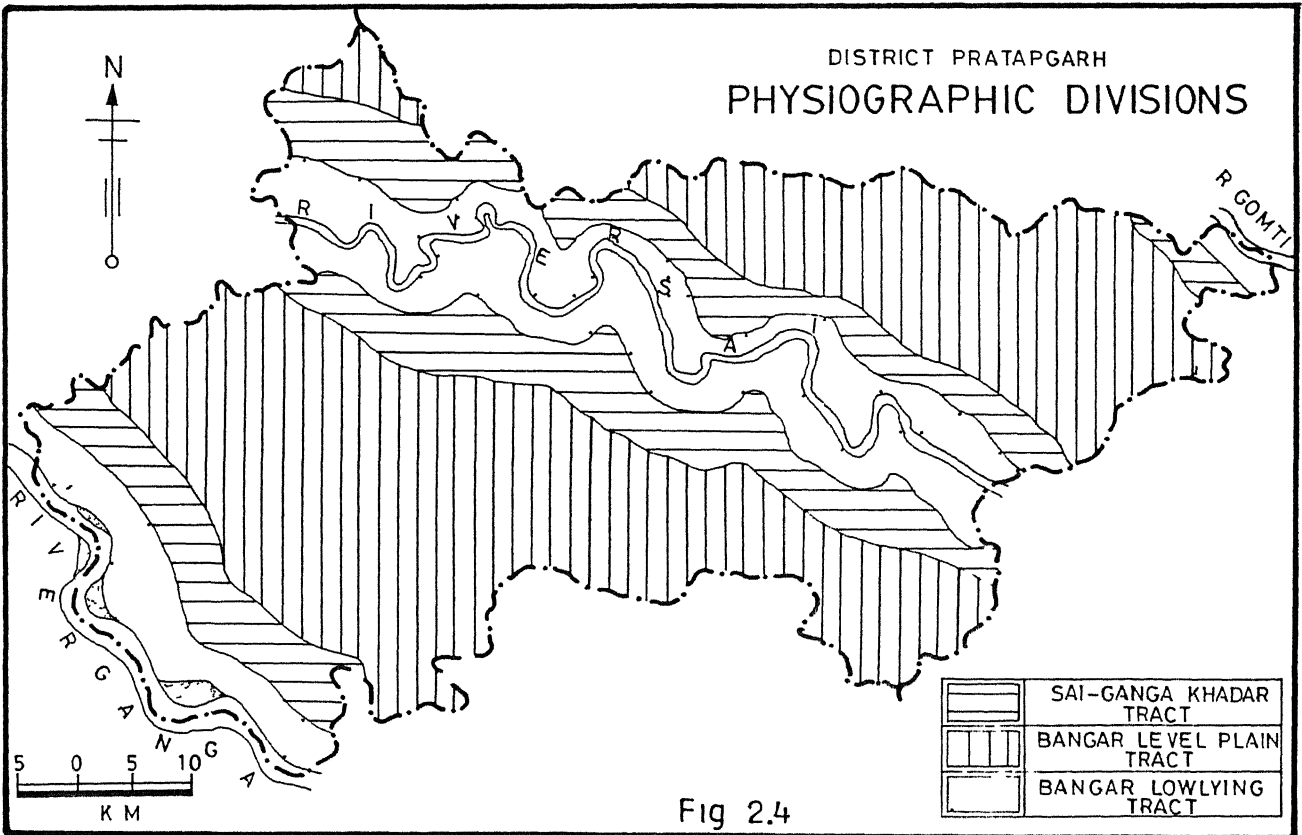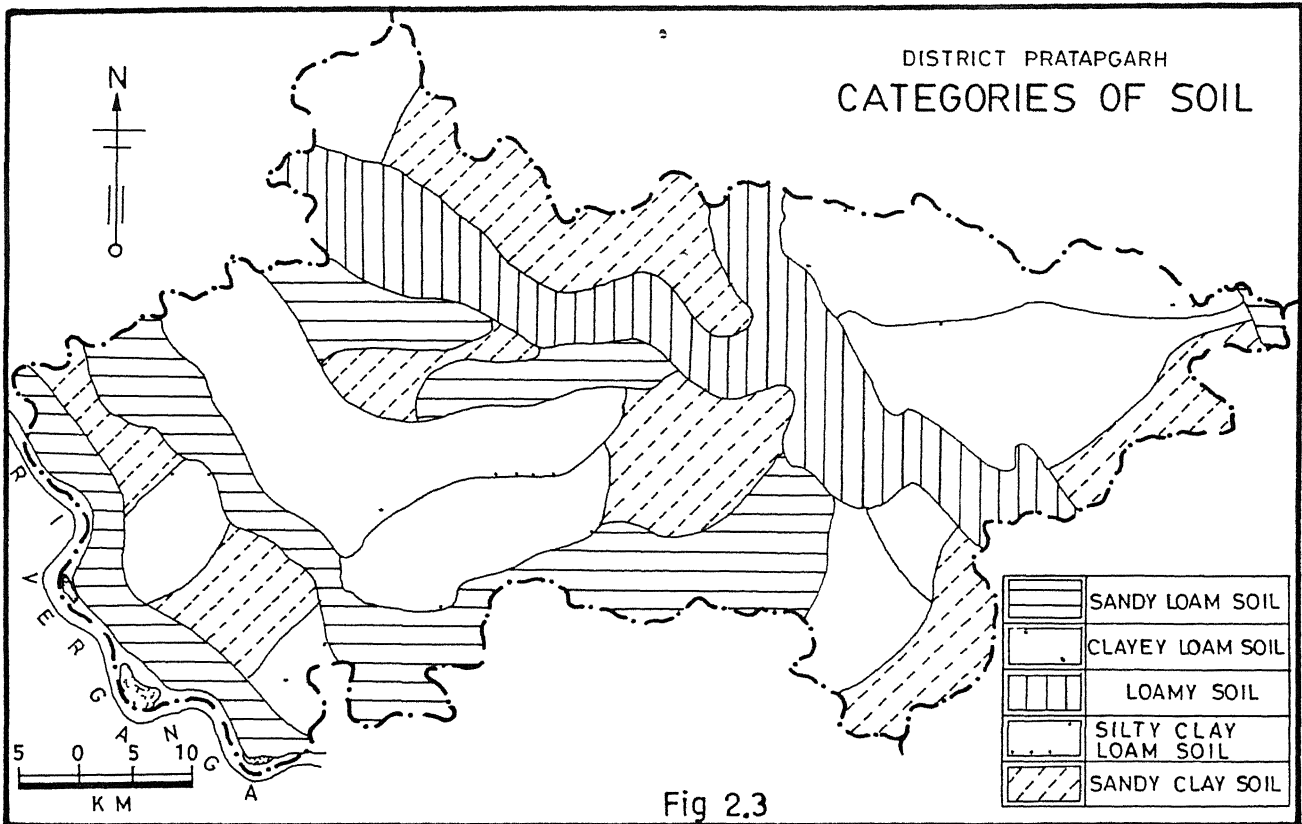
की दूरी तक बहती है । इसकी सहायक नदी दौर है जो गगा के समानान्तर बहती हुई जहानाबाद के निकट गगा से मिल जाती है । सई नदी जनपद के मध्यवर्ती भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 175 कि मी की दूरी मे बहती है । यह नदी हरदोई, उन्नाव, लखनऊ तथा रायबरेली जनपद से बहती हुई अध्ययन क्षेत्र के अठेहा परगना के मुसतफाबाद क्षेत्र मे प्रवेश करती है । यह जनपद को उत्तरी तथा दक्षिणी दो भागों मे विभक्त करती है । इसके दोनों किनारे पर कई छोटी छोटी नदिया आकर मिलती है जिसमे चमरौरा, परैया, नैया छोइया, लोनी, सकरनी तथा बकुलाही मुख्य है । गोमती नदी अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी सीमा पर लगभग 8 कि मी की दूरी पर बहती है । गगा, सई तथा गोमती नदियों मे वर्ष भर पर्याप्त पानी रहता है परन्तु इनकी सहायक नदियों मे वर्षा ऋतु के बाद पानी सूख जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे कई झील तथा ताल पाये जाते है जिनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ है । इन झीलों तथा तालों का पानी रबी की फसल की सिचाई के लिये प्रयोग मे लाया जाता है।

जलवायु - मौसम सम्बन्धी आँकडे स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है । जलवायु का विवेचन बमरौली इलाहाबाद की वेधशाला से उपलब्ध आँकडे पर आधारित है । अध्ययन क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान 26^0 से0 ग्रे0 है परन्तु मासिक औसत तापमान जनवरी मे 17 2^0 से0 ग्रे0 तथा मई मे 34 5^0 से0 ग्रे0 हो जाता है । मई व जून के महीने मे पश्चिम से आने वाली गर्म तथा तेज हवाए तापमान को बढाने के साथ साथ स्थिति को असह्य बना देती है (चित्र 2 6) ।जून से सितम्बर तक पूर्व से आने वाली पुरवा हवाओं का तथा वर्ष के शेष महीनों मे पश्चिम अथवा दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली पछुवा हवाओं का प्रभाव रहता है ।अक्टूबर व नवम्बर के महीने मे वायु का वेग परिवर्तनशील रहता है ।वर्षा का मुख्य स्रोत ग्रीष्म मानसून है ।वार्षिक वर्षा का औसत 108 से0 मी0 है जिसका 85 प्रतिशत जून से अक्टूबर के महीने मे प्राप्त होती है ।फरवरी व मार्च तथा अप्रैल मे होने वाली वर्षा के साथ कभी कभी उपल वृष्टि हो जाती है, जिससे रबी की फसल को व्यापक हानि पहुचती है । जाडे की ऋतु मे पाला व तुषारपात भी होता है जो आलू, तिलहन तथा दलहन की फसलों को हानि पहुचाता है । वार्षिक वर्षा के वितरण प्रतिरूप से स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढती जाती है ।

DISTRICT PRATAPGARH
DRAINAGE
N
R GOMTI
R PILI
ATARSON NALA
ATARSON TAL
R PARIYA
SARAI JAMUARI TAL
ITWA TAL
PATTI NALA
DAUTPUR TAL
R CHAMRAURA
R SAI
AMRAI TAL
UMRAO TAL
CHANWA TAL
KATRAULI TAL
RIVER SAI
KAITHOLA TAL
JHABAR TAL
R LONI
HUSAINPUR TAL
BARA TAL
MALAHAR TAL
KONORA TAL
DHINGWAS TAL
RINI TAL
GUJRAI TAL
KATAN TAL
RIVER BAKULAHI
R DUAR
RIVER GANGA
0 6
km
RIVER
TANK
DISTRICT BOUNDARY
Fig 25
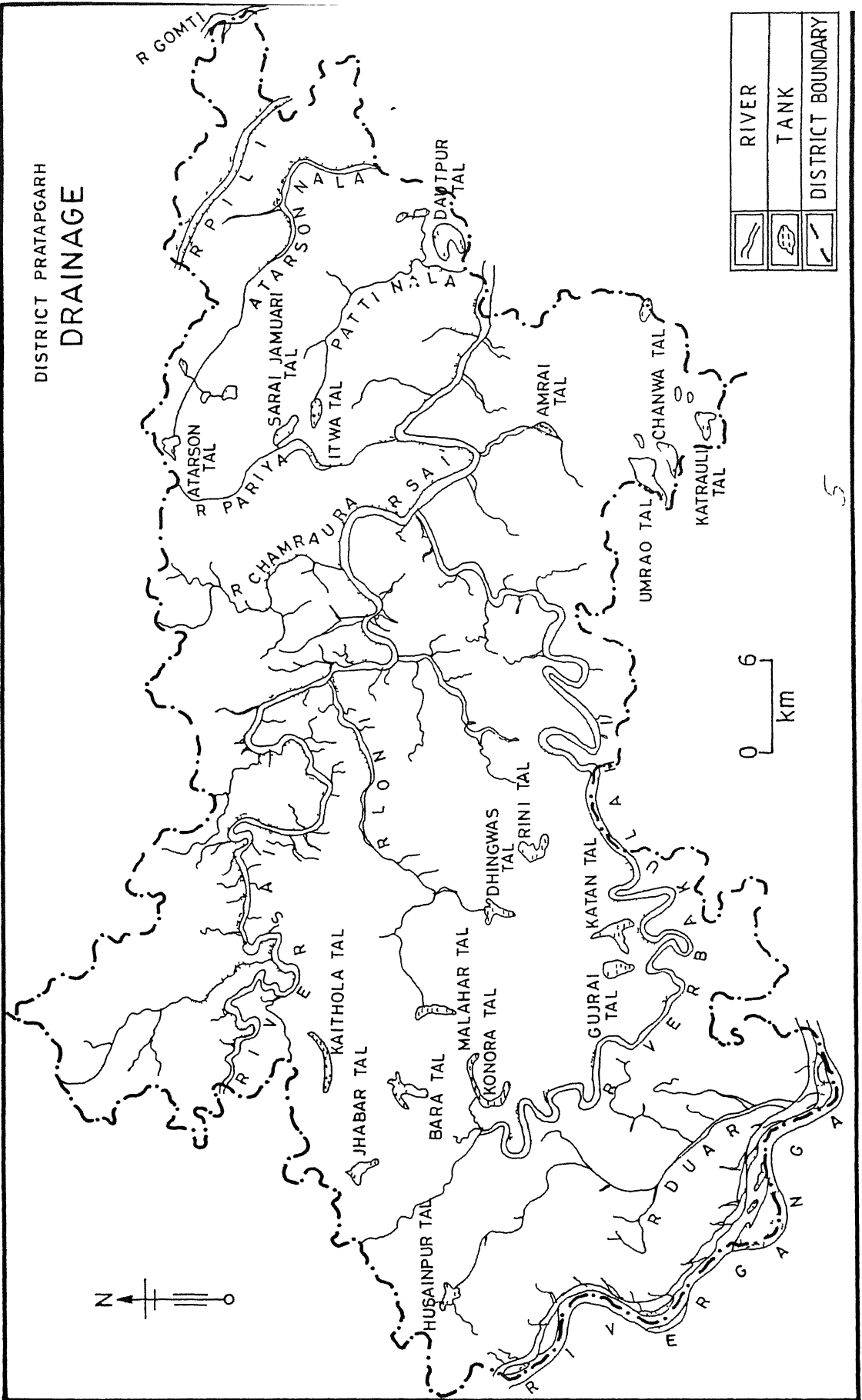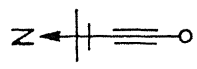
CLIMATIC CHARACTERISTICS
A
TEMPERATURE IN °C
RAINFALL IN cm
MONTHS
J F M A M J J A S O N D
B
CLIMOGRAPH
WET BULB TEMPERATURE IN °F
RELATIVE HUMIDITY IN PERCENT
C
N
DISTRICT PRATAPGARH
DISTRIBUTION OF ANNUAL RAINFALL
RIVER GANGA
5 0 5 10
KM
RAINFALL IN cm
< 98
102 - 105
>105 - 108
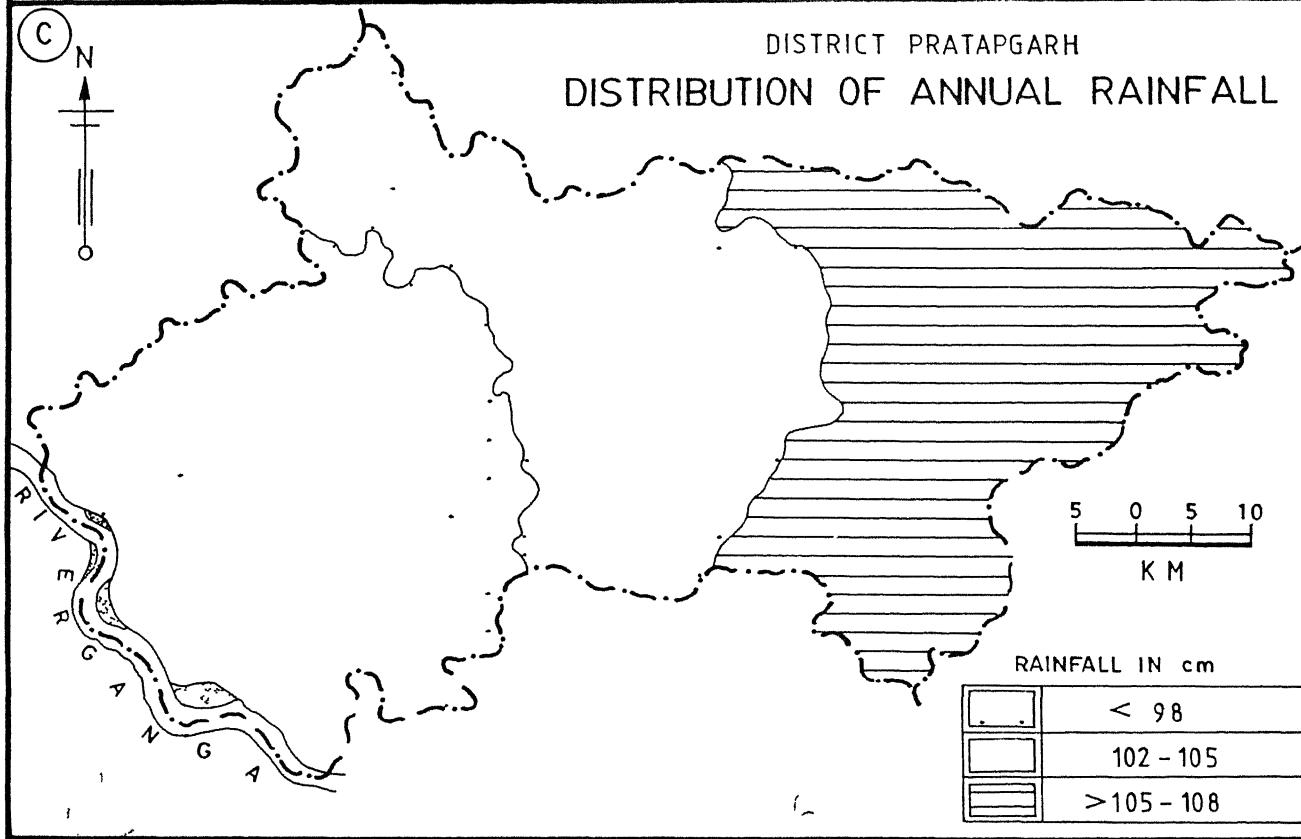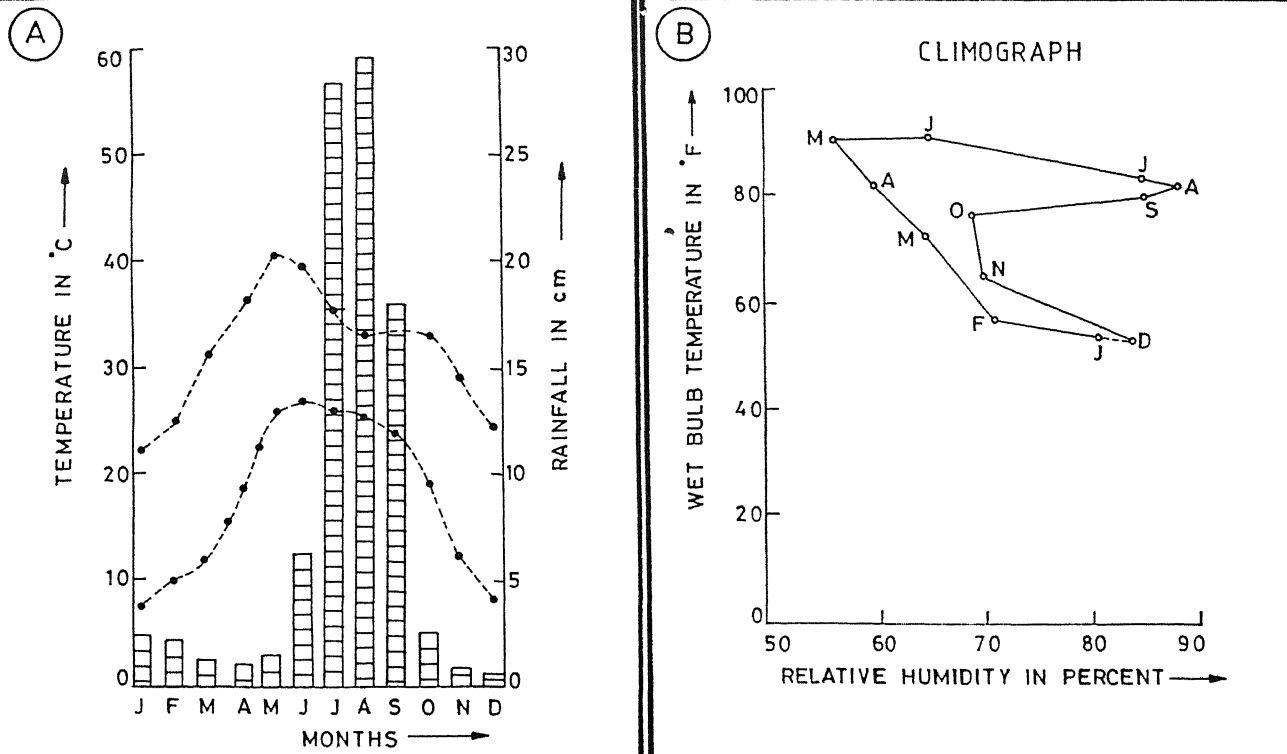
Fig 2.6

प्राकृतिक संसाधन

खनिज सम्पत्ति - खनिजों की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र महत्वहीन है । यहा की मिट्टी मे चिकनी मिट्टी, रेत तथा ककड की जो मात्रा उपलब्ध है वह खनिज की गुणवत्ता की दृष्टि स निम्न कोटि की है । अत आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नही है । चिकनी मिट्टी का यद्यपि यहा पर्याप्त भण्डार है परन्तु इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन, इमारती ईंटों तथा छाजन के लिये खपडों के निर्माण तक सीमित है । रेह, जो सोडियम कारबोनेट व सल्फेट के साथ आशिक मात्रा मे कैल्शियम व मैग्नेशियम लवणो का मिश्रण होता है, इस क्षेत्र मे व्यापक रूप से उपलब्ध है । इसका उपयोग कपडा धोने के लिये किया जाता है । बागर क्षेत्र मे मिट्टी मे स्थान स्थान पर चूने की पर्याप्त मात्रा तथा अधोस्तरीय जल के उच्च स्तर के कारण मिट्टी की निचली तहों पर ककड बहुलता से पाया जाता है ।

वनस्पति अध्ययन क्षेत्र जगल व वन के वितरण की दृष्टि से महत्वहीन है क्योंकि समस्त क्षेत्रफल के 0 । प्रतिशत भाग पर नैसर्गिक वनों का विस्तार है । ये वन मुख्यत नदियों के कटे फटे भूभागों मे फैले हुये है । इनमे विभिन्न प्रकार के मानसूनी वृक्ष पाये जाते है । विगत कुछ वर्षों मे सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वृक्षों को लगाने के साथ साथ वनों की सुरक्षा के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

मिट्टी कृषि प्रधान क्षेत्र मे उपयोगिता की दृष्टि से मिट्टी का विशेष महत्व है । जनपद की अधिकाश मिट्टी क्षारीय है जिसका पी0 एच0 मान 7 से अधिक है ।रचना के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण दो भागों मे किया जा सकता है । प्रथम प्रकार की मिट्टी चिकनी मटियार है जो कुण्डा, कालाकाकर, बाबागज, विहार, रामपुर, लक्ष्मणपुर, मान्धाता, सदर, गौरा तथा शिवगढ मे पाई जाती है । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है । द्वितीय प्रकार की मिट्टी बालू व उसके मिश्रण से बनी दुमट मिट्टी है जो सागीपुर, स0 चन्द्रिका तथा आसपुर देवसरा मे मिलती है । प्रथम प्रकार की मिट्टी मे आर्द्रता बनाये रखने की क्षमता अधिक होती है । जबकि बालू मिश्रित दुमट मे आर्द्रता बनाये रखने की क्षमता नहीं होती है । कण रचना तथा

उनके तत्वों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी को पुन पाच भागों मे विभक्त किया गया है (चित्र 2 3) -

1 बलुई दुमट

2 चिकनी दुमट

3 बादामी दुमट

4 भूरी तलहटी चिकनी दुमट

5 भूरी बादामी चिकनी बलुई दुमट

बालू प्रधान क्षेत्र मे चिकनी मिट्टी के हल्के मिश्रण से युक्त बादामी रग की मिट्टी की प्रधानता होती है । इसमे मिश्रित बारीक कणों मे बालू का अश 30 से 60 प्रतिशत तक तथा चिकनी मिट्टी मे 10 से 20 प्रतिशत के बीच होता है । हल्की भूरी चिकनी दुमट का क्षेत्र मुख्यत जनपद के दक्षिणी पूर्वी भागों मे पाया जाता है जो धान की खेती का सर्वोत्तम क्षेत्र है । हल्की बादामी बलुई दुमट मिट्टी गोमती नदी के तटवर्ती भागों मे पाई जाती है । गोमती नदी के दक्षिण मे सीमित क्षेत्र मे बलुही चिकनी दुमट मिट्टी का मिश्रण है । उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास सीमित क्षेत्र मे बारीक बलुई दुमट मिट्टी की प्रधानता है ।

मानव ससाधन वितरण प्रतिरूप

जनसख्या के वितरण प्रतिरूप और आर्थिक ससाधनों के वितरण प्रतिरूप मे गहरा सम्बन्ध है । अत जनसख्या के वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण आवश्यक है । यदि हम बिन्दु विधि से प्रदर्शित मानचित्र (सख्या 2 7) पर दृष्टिपात करे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त सघन बसा हुआ है । किन्तु जनसख्या के घनत्व के प्रतिरूप से जनसख्या के वितरण की विषमता स्पष्ट प्रतीत होती है । जनसख्या का घनत्व क्षेत्रफल एव जनसख्या का अनुपात है ।

प्रतापगढ जनपद की जनसख्या का घनत्व 1901 तथा 1981 के बीच 248 मनुष्य प्रति वर्ग

सारिणी संख्या 2 । अध्ययन क्षेत्र का तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व
(व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0)

वर्ष	प्रतापगढ जनपद	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	248	165	72
1951	297	215	111
1961	341	251	134
1971	381	300	173
1981	484	377	216
1991	595	472	267

स्रोत भारतीय जनगणना, 1951-91

सारिणी सं0 2 2 जनपद के विकास खण्ड स्तर पर कुल जनसंख्या का घनत्व
(मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0)

विकास खण्ड का नाम	1961	1971	1981
सदर	453	844	848
लक्ष्मणपुर	357	395	497
मानधाता	377	434	573
सडवा चन्द्रिका	355	391	475
सागीपुर	313	343	423
कुन्डा	365	452	520
कालाकाकर	288	328	486
बाबागज	297	330	427
बिहार	320	367	478
रामपुरखास	298	326	422
पट्टी	278	320	456
गौरा	327	377	458
शिवगढ	246	388	512
मगरौरा	358	403	422
आसपुरदेवसरा	291	332	484

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961-81

कि0 मी0 से बढकर 484 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 हो गया है । इसकी तुलना मे प्रदेश एव राष्ट्र की जनसख्या का घनत्व काफी कम है । उत्तर प्रदेश की जनसख्या का घनत्व विगत् 80 वर्षो मे 165 से बढकर 377 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 तथा राष्ट्र की जनसख्या का घनत्व 72 से बढकर 216 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 हो गया है (सारिणी 2 1) । अत स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र एक सघन जनसख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ कि प्रति वर्ग कि0 मी0 उपलब्ध भूमि पर जनसख्या का भार निरन्तर बढता जा रहा है । जनसख्या के घनत्व का विकास खण्ड स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है उसे सारिणी सख्या 2 2 तथा 2 3 से देखा जा सकता है । सारणी सख्या 2 2 कुल जनसख्या के घनत्व (ग्रामीण एव नगरीय) का प्रदर्शन करती है जबकि सारणी सख्या 2 3 केवल ग्रामीण जनसख्या के घनत्व को प्रदर्शित करती है। इन दो सारणियों से स्पष्ट है कि वे विकास खण्ड जहाँ कि नगरीय अधिवास पाये जाते है (उदाहरण के लिये सदर, कुण्डा, कालाकाकर, सडवा चन्द्रिका तथा पट्टी) उनकी जनसख्या का घनत्व अधिक है । किन्तु यदि केवल ग्रामीण जनसख्या के घनत्व पर विचार किया जाय तो मानधाता, शिवगढ तथा सदर विकास खण्ड अपेक्षाकृत सघन रूप से बसे हुये है । विकास खण्ड स्तर पर 1961 और 1981 के बीच जनसख्या के घनत्व के वितरण का प्रदर्शन किया गया है (चित्रसख्या 2 8) । वर्ष 1981 के आकडों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को पाच भागों मे विभक्त किया जा सकता है

1 अत्यधिक घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत सदर विकास खण्ड आता है जहाँ पर जनसख्या का घनत्व 848 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 है ।

2 अधिक घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत मानधाता विकास खण्ड आता है जहाँ पर जनसख्या का घनत्व 573 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 है ।

3 मध्यम घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत कुण्डा (520) तथा शिवगढ (512) विकास खण्ड आते है ।

4 निम्न घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत लक्ष्मणपुर (497) कालाकाकर

सारिणी 2.3 जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व
(मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0)

विकासखण्ड का नाम	1961	1971	1981
सदर	434	482	539
लक्ष्मणपुर	357	395	497
मानधाता	377	434	573
सडवा चन्द्रिका	355	391	455
सागीपुर	313	343	423
कुन्डा	365	452	480
कालाकार	288	328	452
बाबागंज	297	330	427
बिहार	320	367	478
रामपुरखास	298	326	422
पट्टी	278	320	428
गौरा	327	377	458
शिवगढ	246	388	512
मगरौरा	358	403	422
आसपुर देवसरा	291	332	484

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

(486), आसपुर देवसरा (484), बिहार (478), गौरा (456), बाबागज (427), तथा सागीपुर (423) विकास खण्ड है ।

5 निम्नतम घनत्व वाले विकास खण्ड इसके अन्तर्गत रामपुर खास (422) तथा मगरोरा (422) विकास खण्ड है । इस निम्न घनत्व का मुख्य कारण अनुपजाऊ भूमि की अधिकता है ।

ग्रामीण जनसख्या के घनत्व के वितरण के आधार पर (मानचित्र 2 8) अध्ययन क्षेत्र मे चार भाग देखे जा सकते है -

1 अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र - यह वह विकास खण्ड है जहाँ जनसख्या घनत्व 555 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 से अधिक है । इसके अन्तर्गत मानधाता विकासखण्ड (573 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0) आता है ।

2 अधिक घनत्व वाले क्षेत्र - यह वे विकासखण्ड है जहाँ जनसख्या घनत्व 498 से 554 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 है । इसके अन्तर्गत सदर विकासखण्ड (539) तथा शिवगढ विकासखण्ड (512) है ।

3 मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र - यह वह विकासखण्ड है जहाँ जनसख्या घनत्व 423से 497 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 है । इसके अन्तर्गत कालाकाकर (452), बाबागज (427), विहार (478), लक्ष्मणपुर (497), गौरा (458), पट्टी (428), आसपुर देवसरा (484), स0 चन्द्रिका (455) तथा सागीपुर (423) है ।

4 निम्न घनत्व वाले क्षेत्र - इस श्रेणी मे मगरौरा तथा रामपुर खास विकास खण्ड है जिनकी जनसख्या का घनत्व 422 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 है । जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है यह वे क्षेत्र है जहाँ ऊसर युक्त अनुपजाऊ भूमि अधिक है ।

बढती हुई जनसख्या तथा जनसख्या के घनत्व का मानव अधिवास संरचना पर पर्याप्त प्रभाव

पडा है जिसका उल्लेख अगले अध्याय मे किया गया है ।

लिग अनुपात - जनसख्या के विश्लेषण मे स्त्री - पुरुष अनुपात का विशेष महत्व है क्योंकि इससे जनसख्या के महत्वपूर्ण गुण का उद्घाटन होता है । स्त्री - पुरुष का अनुपात लिग अनुपात के रूप मे जाना जाता है जो कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की सख्या के रूप मे प्रदर्शित किया जाता है । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र मे कुल जनसख्या तथा ग्रामीण जनसख्या मे पुरुषों की तुलना मे स्त्रियों की सख्या अधिक है । यह अनुपात उत्तर प्रदेश एव भारत की तुलना मे अधिक है । अध्ययन क्षेत्र मे इसका वितरण अत्यन्त असतुलित एव विषम है । यद्यपि कि वर्ष 1901 - 81 मे असतुलन मे कमी आयी है । वर्ष 1901 मे प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की सख्या 1045 थी जबकि वर्ष 1981 मे यह सख्या घट कर 1016 हो गयी है (सारिणी सख्या 2 4) । यदि हम कुल जनसख्या के लिग अनुपात के वितरण को विकासखण्ड स्तर पर देखें (परिशिष्ट) तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मे सदर, कालाकाकर, बिहार, आसपुर देवसरा तथा कुण्डा को छोड कर शेष अन्य विकासखण्डों मे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की सख्या अधिक रही है । यह तथ्य ग्रामीण जनसख्या के लिग अनुपात के विश्लेषण से भी स्पष्ट होता है । ये इस बात का द्योतक है कि अध्ययन क्षेत्र मूलत आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा हुआ क्षेत्र है जहाँ रोजगार के अवसर बहुत ही कम है तथा जोतों के असमान वितरण के कारण कृषि उत्पादन क्षमता बहुत कम है । फलस्वरूप पुरुषों का एक बहुत बडा समूह नगरों की ओर पलायन कर गया है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण - नगरीय प्रवास का बहुत ही विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है । प्रवास की यह प्रवृत्ति नगरीय जनसख्या के लिग अनुपात के विश्लेषण से और अधिक स्पष्ट होती है । उदाहरण स्वरूप नगरीय जनसख्या मे प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की सख्या वर्ष 1901 मे 900 थी किन्तु वर्ष 1981 मे स्त्रियों की सख्या घट कर 856 हो गयी । ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों मे आव्रजन के कारण नगरीय क्षेत्रों मे पुरुषों की सख्या मे वृद्धि हुई है क्योंकि अधिकाश लोग सामाजिक व आर्थिक कारणों से नगरों मे प्रवास करते समय अपने परिवार के साथ प्रवास नहीं कर पाते है। यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसख्या मे पुरुषों की सख्या स्त्रियों की तुलना मे

सारिणी सख्या 2 4   प्रतापगढ जनपद मे लिग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की सख्या)

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	जनपद
1901	1049	900	1045
1951	1044	873	1039
1961	1066	839	1062
1971	1022	847	1016
1981	1019	856	1016

स्रोत   प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1951-81

बढती जा रही है । डेविस किग्सले (1951) का यह विचार कि भारतीय नगर पुरुष प्रधान है, अध्ययन क्षेत्र के लिये भी पूर्णत सत्य है ।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिवेश मानव अधिवास की सरचना को पूर्णतया प्रभावित करता है। मानव अधिवास - सरचना का विश्लेषण अगले अध्याय मे किया गया है ।

REFERENCES

1. Davis, K. (1951), The Population of India and Pakistan, Princeton . New Jersey

2 Nevill, H.R. (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad : Government Press

3. Shafi, M. (1959), Land Utilization in Eastern Uttar Pradesh, Published Ph.D Thesis, Aligarh Muslim University, Aligarh

अध्याय 3

मानव अधिवास तंत्र

विगत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है । यह मानव अधिवास के उद्भव, विकास तथा वितरण को प्रभावित करता है । प्रस्तुत अध्याय मे ग्रामीण एव नगरीय अधिवास तत्र के इन्ही पक्षों का विश्लेषण किया गया है ।

अधिवासों की उत्पत्ति

जैसा कि विगत अध्याय से स्पष्ट है, अध्ययन क्षेत्र गगा-यमुना के मैदानी भाग का एक समतल धरातलीय एव मुख्यतया बलुई दुमट मिट्टी वाला भाग है । तथा इस भाग मे अनेक छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है । इन्हीं नदियों एव झीलों के किनारे उपजाऊ मिट्टी वाले भूभाग पर अनेक अधिवासों का प्रादुर्भाव हुआ है ।' अनेक अन्त साक्ष्य एव वहिर्साक्ष्यों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे अधिवासों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । कनिघम (1872), फहरेर (1867) तथा नेविल (1904) द्वारा प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व भी मानव अधिवास विद्यमान थे । कई ऐसे अधिवास है जिनका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । सराय नाहर, हडोर, राकी, अठेहा, मुस्तफाबाद, बेलखडी, बिहार, गोंडा, शकरदहा, मानिकपुर, कालाकाकर, करेटी, रामपुर, भदरी, अल्हापुर, देवीगज, धारूपुर तथा अरोल आदि कुछ ऐसे अधिवास है (चित्र सख्या 3 ।) जो प्राचीनतम जनपुज के ऐतिहासिक उदाहरण है । ऐसा अनुमान है कि ये वे अधिवास है जो मुख्य रूप से बौद्ध - बिहार, स्तूप, मन्दिर अथवा किसी प्रमुख राजा या उनके आमात्य द्वारा निर्मित किला अथवा प्रशासनिक इकाई के केन्द्र रहे है । प्रारम्भ मे नदियाँ ही मुख्य रूप से यातायात का साधन थी । अत उनका विकास भी नदियों के तट पर हुआ । अधिवास सम्बन्धी उत्पत्ति के एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार अधिवासों की उत्पत्ति मुख्य रूप से उन भागों मे हुई थी जो कि खाद्यान्न - बाहुल्य क्षेत्र थे (स्मैल्स 1967) । बारहवीं से 17हवी शताब्दी के बीच जिन मानव अधिवासों का जन्म हुआ उनका उल्लेख जिला गजेटियर मे किया गया है । गगा नदी के किनारे कुण्डा तहसील मे स्थित मानिकपुर कस्बा बारहवीं शताब्दी मे एक ऐतिहासिक नगर था जो प्रादेशिक नियत्रण केन्द्र रूप मे हिन्दू तथा मुसलमान राजाओं द्वारा विकसित किया गया था । अनेक छोटे छोटे राजाओं एव जमीदारों का क्षेत्र होने के कारण प्रतापगढ मे कई महत्वपूर्ण अधिवास विकसित

सारिणी संख्या 3 । प्रतापगढ जनपद में जनसख्या के अनुसार ग्रामीण अधिवासों का प्रतिशत

जनसख्या आकार	1901	1951	1961	1971	1981
0-499	73 4	64 4	59 4	54 7	44 8
500-999	19 5	25 0	26 5	27 3	28 8
1000-1999	6 0	8 7	11 4	14 2	20 6
2000-4999	1 1	1 9	2 7	3 8	5 6
5000-9999	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस बुक 1961, 1971, 1981

हुये । इनमे कालाकाकर, कैथौला, राजापुर, राकी तथा सुजाखर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

अधिवासों का वास्तविक विकास आधुनिक काल मे मुख्य रूप से अग्रेजी शासन काल मे हुआ । क्योंकि वे समस्त केन्द्र जहाँ अग्रेजों की छावनियाँ थी, प्रमुख अधिवास के रूप मे स्थापित हुये। बेला प्रतापगढ, जो प्रतापगढ सिटी से लगभग 6 कि0 मी0 दूर पर स्थित है तथा जिला मुख्यालय का केन्द्र भी है, का विकास उस समय हुआ जब सन् 1858 मे जिलों का पुनर्गठन किया गया । सडक यातायात के विकसित होने से भी अधिवास विकसित हुये । सडक यातायात का विकास मुख्य रूप से तीन चरणों मे हुआ । सर्वप्रथम 1857 मे प्रमुख केन्द्रों को सडकों से जोडने के लिये ब्रिटिश शासन ने आदेश दिया और सन् 1858 मे जब बेला प्रतापगढ जिला मुख्यालय के रूप मे स्थापित हुआ तो इस स्थान को इलाहाबाद, फैजाबाद, रायबरेली, गौरीगज, कटरा गुलाब सिह तथा कालाकाकर से जोड दिया गया । इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटे छोटे मार्ग भी रेलवे स्टेशनों को जोडने के लिये निर्मित किये गये । इसमे गौरा तथा दाँदूपुर रेलवे स्टेशनों को जोडने वाली सडके मुख्य थी । सन् 1870 मे 5472 कि0 मी0 लम्बी सडक का निर्माण सम्पन्न हो चुका था । इनमे पक्की सडकों की लम्बाई 100 8 कि0 मी0 थी । सन् 1904 तथा 1914 के बीच पश्चिम मे राय बरेली तथा पूर्व मे बादशाहपुर को जोडने वाली सडके पक्की हो चुकी थीं । किन्तु सडकों का वास्तविक विकास स्वतत्रता के पश्चात् हुआ । इन सडकों के विकास के साथ अधिवास तन्त्रों का न केवल विकास हुआ, अपितु कई नये अधिवास बाजार अथवा सेवा केन्द्र के रूप मे विकसित हुये । सडक की भाति ही रेलमार्ग के विकास से भी अधिवास तत्र प्रभावित हुआ । यद्यपि कि अध्ययन क्षेत्र का रेलमार्ग मुख्य रूप से स्वतत्रता से पूर्व का ही है, किन्तु अध्ययन क्षेत्र के वाह्य सम्पर्क बढ जाने के कारण न केवल यातायात की सुविधा मे वृद्धि हुई, अपितु विभिन्न वस्तुओं के आयात, निर्यात को बल प्राप्त हुआ जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पडा । इसके अतिरिक्त स्कूल, कालेज, बैंक, पोस्ट आफिस जैसी सुविधाओं के फलस्वरूप भी अनेक बाजार तथा सेवा केन्द्र उभरे । प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को तीन तहसीलों तथा 15 विकास

खण्डों की इकाइयों मे बाटने के कारण कई महत्वपूर्ण अधिवास विकसित हुये । इनमे कुन्डा, पट्टी, प्रतापगढ और लालगज मुख्य है ।

अधिवासों के उद्भव एव विकास के सम्बन्ध मे मिश्रा एव मिश्रा (1987) ने एक माडल विकसित किया (चित्र सख्या 3 2) है । इस माडल के अनुसार प्रारम्भ मे मानव अधिवास का विकास एक ग्राम के रूप मे होता है । गाव की आवश्यकता बढने पर कुछ सेवाये बढ जाती है जिससे गाव, बाजार अथवा कस्बे के रूप मे विकसित हो जाता है । यातायात सुविधाओं एव उच्च स्तर की सेवाओं के बढने के साथ साथ यह कस्बे नगर का रूप धारण कर लेते है । विकास के इस प्रक्रम को तीन कालों - पूर्व उपनिवेश काल (सत्रहवी शताब्दी के पूर्व का समय), उपनिवेश काल (सत्रहवीं शताब्दी से 1947 तक का समय) तथा स्वातत्र्योत्तर काल (1947 के पश्चात् का काल) में विभक्त किया गया है ।

पूर्व उपनिवेश काल मे मुख्य रूप से कुछ विशेष अभिजात्य आवास, किला, धार्मिक स्थल, प्रशासनिक केन्द्र, हाट अथवा बाजार के रूप मे अधिवासों का विकास हुआ तथा पगडडी, बैलगाडी एव केवल कुछ कच्चे मार्ग सम्पर्क का कार्य करते थे । औपनिवेशिक काल मे सेवा सरचना तथा यातायात के साधनों मे पर्याप्त परिवर्तन हुआ तथा प्रशासनिक, वाणिज्यिक एव यातायात सम्बन्धी सुविधाओं मे वृद्धि के कारण अधिवासों का विकास हुआ । कच्चे मार्गो के अतिरिक्त पक्की सडके तथा रेलवे लाइने भी बिछायी गयी । स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजित एव अनियोजित सेवाओं मे वृद्धि हुई तथा यातायात साधनों मे और अधिक विकास हुआ, जिससे अधिवासों के आन्तरिक एव बाह्य सरचना पर अनुकूल प्रभाव पडा । अधिवास विकास का यह माडल प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मे भी लागू होता है ।

अधिवास संरचना

ग्रामीण अधिवास - जैसा कि सारिणी सख्या 3 1 तथा 3 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे 2185 ग्रामीण अधिवास है जिसमे से 978 (44 8 प्रतिशत) अधिवास ऐसे है जिनकी जनसख्या 500 से कम है । 638 (28 8 प्रतिशत) अधिवास 500 - 1000 आबादी के

सारिणी संख्या 3.2 . प्रतापगढ जनपद में जनसंख्या वर्ग के अनुसार ग्रामीण अधिवासों में वृद्धि

जनसख्या आकार	1901	1951	1961	1971	1981
0-499	1591	1402	1303	1201	978
	-	(-11 9)	(-7 1)	(-7 8)	(-18 6)
500-999	420	546	581	600	638
	-	(30 2)	(6 4)	(3 3)	(6 3)
1000-1999	132	195	251	312	440
	-	(47 7)	(28 7)	(24 3)	(41 0)
2000-4999	24	45	60	82	124
	-	(87 5)	(33 3)	36 7	(51 2)
5000 से अधिक	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
जनपद का योग	2167	2188	2195	2195	2185

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1901 1951,1961,1971,1981
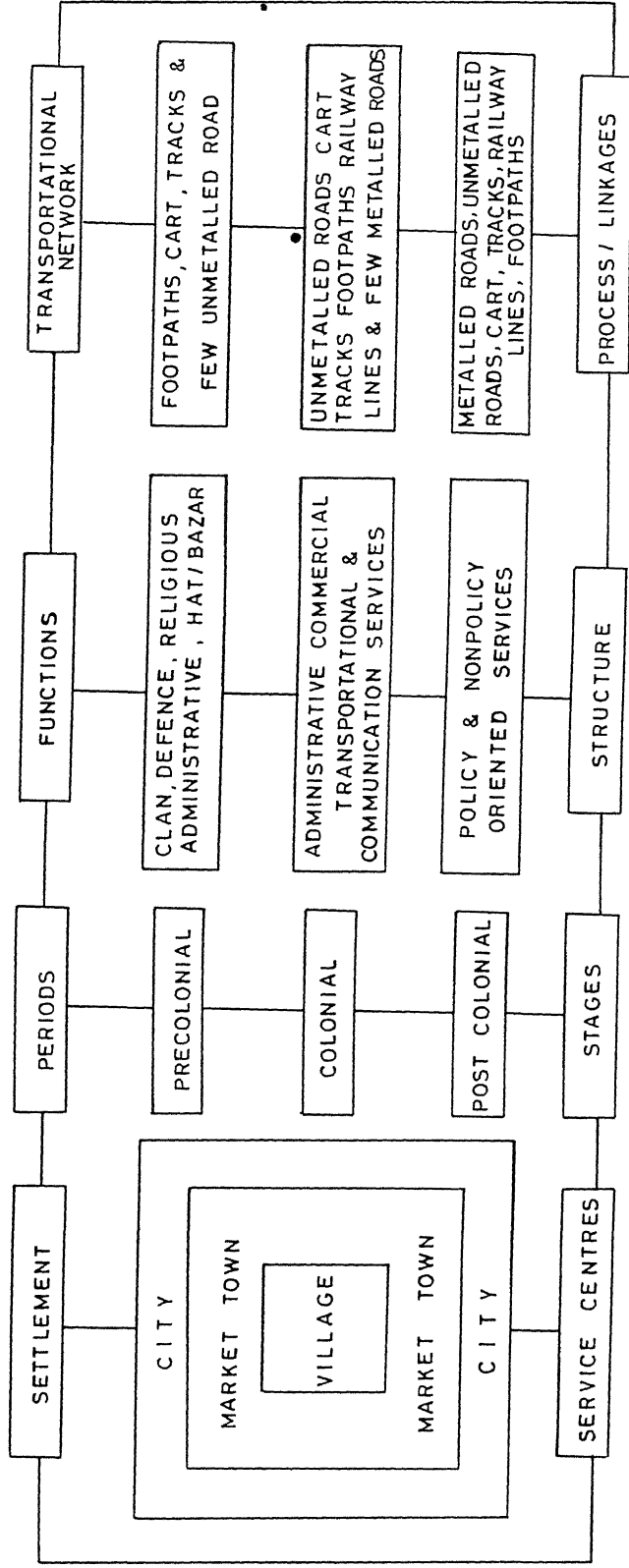
SOURCE ' MISHRA H N et al EVOLUTIONARY MODEL OF SERVICE CENTRES IN SLOW GROWING ECONOMY. IN MISRA H N (ed) (1987) RURAL GEOGRAPHY, NEW DELHI HERITAGE PUBLISHERS

Fig 3.2

बीच,440 (20 6 प्रतिशत) अधिवास 1000 - 2000 की आबादी वाले तथा 124 (5 6 प्रतिशत) अधिवास 2000 से 5000 आबादी वाले है तथा पाँच अधिवास (0 2 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी जनसख्या 5000 से अधिक है । इन दोनों सारिणियों से यह स्पष्ट होता है कि 500 से कम जनसख्या वाले अधिवासों की सख्या मे पर्याप्त ह्रास हुआ है । इनकी सख्या सन् 1901 मे 1591, 1951 मे 1402, 1961 मे 1303, तथा 1971 मे 1201 थी । 1981 मे ऐसे अधिवासों की सख्या केवल 978 ही रह गयी । विगत् दो दशकों (1971 - 81) मे इस प्रकार के अधिवासों की सख्या मे 18 6 प्रतिशत का ह्रास हुआ । किन्तु 500 - 1000 की आबादी वाले ग्रामीण अधिवासों की सख्या मे वृद्धि हुई है । विगत् आठ दशकों (1901 - 81) मे इस वर्ग के अधिवासों की सख्या 420 से बढकर 638 हो गई । इस प्रकार इस वर्ग मे 6 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ठीक इसी प्रकार 1000 - 2000 एव 2000 - 5000 की आबादी वाले ग्रामीण अधिवासों की सख्या मे भी वृद्धि हुई । इनकी सख्या सन् 1901 मे क्रमश 132 तथा 24 थी जबकि 1981 मे यह बढकर 440 तथा 124 हो गयी । इस प्रकार विगत दो दशकों मे 1000 - 2000 की आबादी वाले अधिवासों मे 41 0 प्रतिशत तथा 2000 - 5000 की आबादी वाले अधिवासों मे 51 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । छोटे अधिवास बडे अधिवासों के वर्ग मे सम्मिलित हो रहे है क्योंकि उनकी जनसख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । सन् 1901 - 71 के मध्य 5000 की आबादी वाले अधिवासों का अभाव था किन्तु 1981 मे 5 अधिवास इस श्रेणी मे भी आ गये । विगत दो दशको मे गाँवों की सख्या मे जो ह्रास हुआ है उसका मुख्य कारण नगरीकरण है । कुछ ग्राम उदाहरण के लिये कुन्डा, पट्टी, अन्तू, मानिकपुर, बेला प्रतापगढ तथा कटरा मेदनीगज कस्बा अथवा नगर की श्रेणी मे आ गये है ।

उत्तर प्रदेश तथा प्रतापगढ जनपद मे गावों की सख्या तथा उनमे निवास करने वाली जनसख्या का तुलनात्मक प्रारूप सारिणी सख्या 3 3 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य एव अध्ययन क्षेत्र मे लगभग पूर्ण समानता है । यह भी स्पष्ट है कि जनसख्या का अधिकाश भाग 500 से 1000 तथा 1000 - 2000 के आबादी वाले अधिवासों मे है ।

सारणी संख्या 3.3 जनसख्या वर्ग के अनुसार गाँवों की सख्या एवं उनमें निवास करने वालों की जनसंख्या

राज्य	वर्ष	0 - 500		500 - 999		1,000 -1,999		2,000 - 4,999		5,000 - 9,999		10,000 से अधिक	
1	2	$3^{\times}$	4^{0}	$5^{\times}$	6^{0}	$7^{\times}$	8^{0}	$9^{\times}$	10^{0}	$11^{\times}$	12^{0}	$13^{\times}$	14^{0}
उत्तर प्रदेश	1901	75 1	37 2	17 1	29 9	6 3	21 8	1 5	10 4	0 0	0 7	0 0	0 0
	1921	76 2	40 3	16 6	30 0	6 0	21 2	1 2	8 1	0 0	0 3	0 0	0 1
	1951	67 5	30 0	20 8	29 8	9 2	25 3	2 4	13 5	0 1	1 4	0 0	0 0
	1961	61 8	24 5	23 1	28 5	11 4	26 9	3 4	16 6	0 3	3 1	0 0	0 4
	1971	55 5	19 2	25 1	26 5	14 3	29 0	4 8	20 0	0 5	4 4	0 0	0 9
	1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतापगढ जनपद	1901	73 4	41 0	19 5	32 2	6 2	20 0	1	6 8	0 0	-	-	-
	1951	64 4	31 5	25 0	35 2	8 7	24 3	1 9	9 0	0 0	-	-	-
	1961	59 4	26 7	26 5	33 0	11 4	26 7	2 7	13 6	0 0	-	-	-
	1971	54 7	23 5	27 3	29 9	14 2	30 0	3 8	16 6	0 1	-	-	-
	1981	44 8	-	28 8	-	20 1	-	5 1	-	0 2	-	-	-

स्रोत उत्तर प्रदेश जनगणना 1961 - 81
जनपद जनगणना पुस्तिका 1961 - 81
× गाँवों का प्रतिशत, 0 ग्रामीण जनसख्या का प्रतिशत

ग्रामीण अधिवासों की बढती हुई आबादी इस बात का द्योतक है कि ये अधिवास विविध प्रकार की समस्याओं से [illegible] हो रहे है । उदाहरण के लिये कृषि योग्य भूमि पर अधिक दबाव पड रहा है । परती एव बजर भूमि जो वातावरण के सतुलन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, घट रही है । साथ ही साथ जल, आवास एव पर्यावरण समस्याये भी बढ रही है ।

ग्रमीण अधिवास वितरण प्रतिरूप - धरातल पर अधिवासों के वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी क्षेत्र के नियोजन के लिये अधिवासों के वितरण प्रतिरूप को समझना परम आवश्यक है । प्रारम्भ मे जब मात्रात्मक विधियों का प्रयोग भूगोल मे नहीं होता था, उस समय केवल मानचित्र प्रेक्षण विधि द्वारा गुणात्मक शैली मे वितरण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था । मात्रात्मक विधि के प्रयोग के साथ ही साथ वितरण को स्पष्ट करने के लिये "समीपस्थ पडोसी तकनीक " का प्रयोग सर्वप्रथम एल0 जे0 किग (1962) ने किया था । ततृपश्चात् इस विधि का प्रयोग अनेक भारतीय भूगोल विदों ने भी किया है । इसके लिये जिस सूत्र का प्रयोग किग महोदय ने किया, वह इस प्रकार है -

$$R_n = \frac{\bar{d}o}{de}$$

R_n = पडोसी तकनीक का अनुपात
$\bar{d}o$ = धरातल पर पडोसी दूरी का औसत
de = अपेक्षित दूरी का औसत

किन्तु यहाँ पर मिश्रा (1984) द्वारा प्रयुक्त अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है --

$$R_n = 2\bar{D}\sqrt{\frac{N}{A}}$$

R_n= पडोसी विधि का अनुपात
$\bar{D}$ = विभिन्न अधिवासों के बीच की औसत दूरी

N = अधिवासों की सख्या

A = क्षेत्रफल

इस विधि के अन्तर्गत यदि पडोसी विधि का अनुपात । से कम है तो उस प्रतिरूप को केन्द्रित प्रतिरूप कहा जाता है । यदि अनुपात । हो तो उसे रैन्डम कहा जायगा तथा यदि । से अधिक हो किन्तु 2 ।5 के बराबर या कम हो, तो उसे समान प्रकार का वितरण प्रतिरूप माना जाता है ।

प्रस्तुत अध्ययन मे समीपस्थ पडोसी तकनीक के आधार पर परिकलन के लिये तीन न्यादर्श क्षेत्रों का चुनाव किया गया । यह न्यादर्श क्षेत्र तीनों तहसीलों के मुख्यालय के चारों ओर 7 कि0 मी0 त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया गया है । प्रत्येक न्यादर्श का क्षेत्रफल ।54 वर्ग कि0 मी0 (चित्र सख्या 3 3) है । तीनों तहसीलों के तीन न्यादर्श क्षेत्र से प्राप्त परिणामों को सारिणी (सख्या 3 4) मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि तीनों तहसीलों मे ।000 से 5000 आबादी वाले अधवासों का वितरण प्रतिरूप समान है । ठीक इसी प्रकार 500 - ।000 आबादी वाले अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कुन्डा एव पट्टी मे समान प्रकार का है किन्तु प्रतापगढ मे केन्द्रित प्रकार का है । 200 - 500 आबादी वाले अधिवासों का वितरण कुन्डा एव पट्टी मे "रैन्डम" प्रकार का है किन्तु प्रतापगढ मे समान प्रकार का दृष्टिगोचर होता है । 200 से कम आबादी वाले अधिवासों का वितरण कुन्डा एव प्रतापगढ मे रैन्डम प्रकार का है जबकि पट्टी मे समान प्रकार का दृष्टिगोचर होता है । समीपस्थ पडोसी तकनीकी विधि से जो परिणाम प्राप्त हुये है, किंचित् संदिग्ध है । अत इनका पुन परीक्षण किया गया है । रैन्डम प्रतिरूप के परीक्षण के लिए अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है (स्मिथ, ।977) ।

$$Sde = \frac{0.26132}{\sqrt{N(N/A)}}$$

Sde = प्रमाणिक त्रुटि

N = अधिवास सख्या

A = क्षेत्रफल

इस सूत्र के प्रयोग से प्राप्त परिणाम सारिणी 3 4 मे प्रस्तुत किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अधिकाश परिणाम विश्वसनीय है और उनकी प्रमाणिकता 95 प्रतिशत तक है ।

नगरीय अधिवासों की संरचना एव वितरण प्रणाली

अध्ययन क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी तथा अन्य शासकों के प्रभाव के चिन्ह आज भी देखने को मिलते है (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1904) । यहाँ अनेक ऐसे अधिवास पाये जाते है जो अपनी ऐतिहासिकता का सकेत देते है । इनमे मानिकपुर सबसे प्राचीन नगरीय अधिवास था । किन्तु अन्य कस्बों का उद्भव एव विकास आधुनिक है । वास्तविकता यह है कि अध्ययन क्षेत्र मे नगरीकरण की प्रवृति ब्रिटिश काल की देन है । वर्तमान मे सन् 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र मे कुल 7 नगरीय अधिवास है । इन अधिवासों को जनसख्या वर्ग के अनुसार वितरण सारिणी सख्या 3 5 मे प्रदर्शित किया गया है । यदि हम सन् 1901-1991 के बीच नगरीय अधिवास की सख्या (सारिणी सख्या 3 6) पर विचार करे तो स्पष्ट होगा कि सन् 1961 मे एकाएक इनकी सख्या 4 से घट कर एक हो गयी है । जो तीन अधिवास प्रभावित हुये, वे मानिकपुर, कटरा मेदनीगज तथा कस्बा प्रतापगढ थे । इसका मुख्य कारण यह था कि 1961 की जनगणना मे नगरीय अधिवासों की परिभाषा मे आमूल परिवर्तन हो गया । सन् 1901-51 तक वे समस्त अधिवास जो प्रशासनिक एव ऐतिहासिक दृष्टि से अथवा वाणिज्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाते थे, उन्हे नगरीय अधिवासों का दर्जा दे दिया गया था ।

सन् 1961 मे नगरीय अधिवासों की परिभाषा को बहुत वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया । इस परिभाषा के अनुसार टाऊन एरिया, नोटीफाइड ऐरिया, कैन्टूनमेन्ट एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को नगरीय अधिवास के अन्तर्गत रखा गया । इसके अतिरिक्त वे अधिवास भी जिनकी आबादी 5000 थी, तथा जहाँ की जनसख्या का घनत्व 386 मनुष्य प्रति वर्ग कि0

सारिणी सख्या 3 4 प्रतापगढ़ जनपद मे अधिवासों का तिवरण प्रतिरूप

अधिवास आकार	कुन्डा	पट्टी	प्रतापगढ
0 - 200	0 99*	1 4*	1 0*
200 - 499	1 0*	1 1*	1 9*
500 - 999	1 4*	1 3*	0 8*
1000 - 4999	1 4*	1 2*	1 5

* 95% पर प्रमाणित

स्श्रोत समीपस्थ पडोसी तकनीक के आधार

सारिणी सख्या 3 5 जनसख्या वर्ग के अनुसार प्रतापगढ जनपद में नगरीय अधिवासों का वितरण प्रतिरूप

वर्ग	आकार	नगरीय अधिवास
I	100,000 से अधिक	-
II	50,000 - 99,999	1
III	20,000 - 49,000	-
I	10,000 - 19,999	1
	05,000 - 09,999	5
	05,000 से कम	-

स्रोत जनगणना, 1991

सारिणी सख्या 3 6 प्रतापगढ़ जनपद मे नगरीय अधिवासों की सख्या

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
नगरीय अधिवासों की सख्या	04	04	04	04	04	04	01	01	07	07

स्रोत जिला जनगणना पुस्तिका 1951-91

मी0 था और जहाँ की कुल आबादी का 75 प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो, मे लगा था, उसे भी नगरीय अधिवास का दर्जा, दिया गया । इस नयी परिभाषा के कारण नगरीय अधिवास की सख्या सन् 1951-61 मे 4 से घट कर केवल 1 रह गयी थी । यह परिभाषा सन् 1971 मे भी मान्य थी और कुछ सशोधन के साथ यही परिभाषा सन् 1981 की जनगणना मे भी मान्य रही । सन् 1981 की परिभाषा के अनुसार वे समस्त अधिवास जो टाऊन ऐरिया, नोटीफाइड एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड, कैन्टूनमेन्ट अथवा म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन हों अथवा वे समस्त अधिवास जिनकी कुल जनसख्या 5 हजार या उससे अधिक हो और कुल पुरुष जनसख्या का 3/4 कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों, मे लगा हो, एव जनसख्या का घनत्व 400 मनुष्य प्रति वर्ग कि0 मी0 हो, उसे नगरीय अधिवास माना गया है । कुछ ऐसे भी स्थान है जिनकी आबादी 5 हजार से कम है, उन्हे "सेन्सस टाउन" माना गया है । इस प्रकार के नगर मुख्य रूप से पहाडी क्षेत्र मे पाये जाते है । एक अन्य परिवर्तन यह हुआ कि बागाती, बागबानी, व मत्स्य पालन क्रियाओं को कृषि कार्यो, के अन्तर्गत नही रखा गया । सन् 1981 मे मानिकपुर, कटरामेदनीगज, कस्बा प्रतापगढ पुन नगरीय अधिवास की श्रेणी मे आय गये । इसके अतिरिक्त कुन्डा, पट्टी तथा अन्तू भी पहली बार नगरीय आधिवास के रूप मे उभर कर आये है । कुन्डा तथा पट्टी तहसील हेडक्वाटर होने के कारण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एव अन्य सुविधाओं के कारण विकसित हो रहे है । अन्तू एक प्रमुख बाजार एव रेलवे स्टेशन तथा ब्लाक हेडक्वार्टर की सुविधा के कारण तेजी से विकसित हो रहा है (चित्र सख्या 3 4 अ, ब, स, द) ।

नगरीय अधिवास जनसंख्या गत्यात्मकता

जनसख्या वृद्धि तथा लिग अनुपात - अध्ययन क्षेत्र के सात नगरीय अधिवासों की जनसख्या वृद्धि सारिणी सख्या 3 7 द्वारा प्रदर्शित की गयी है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ न केवल जिला मुख्यालय है, अपितु जनसख्या की दृष्टि से सबसे बडा अधिवास है । यह सन् 1921 से लगातार अध्ययन क्षेत्र के मुख्य नगरीय केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहा है । सन् 1951-81 के बीच इसकी जनसख्या मे तीन गुने से अधिक (234 प्रतिशत) वृद्धि

सारिणी सख्या 3 7 प्रतापगढ जनपद मे नगरीय जनसख्या एव लिग अनुपात

क्रम सख्या		1951	1961	1971	1981	1991	लिग अनुपात 1981	लिग अनुपात 1991
1	बेला पगतापगढ	15,026	21,400	27,909	49,932	66,845	818	853
		-	(42 4)	(30 4)	(78 9)	(33 87)		
2	कुन्डा	-	03,112*	04,134 *	11,626	16,480	896	901
				(32 8)	(181 2)	(41 75)		
3	मानिकपुर	04 712	05,413 *	06,666 *	08,773	11,640	917	848
			(14 8)	(23 0)	(31 6)	(27 6)		
4	प्रतापगढ	04,596	04,711*	04,714 *	06,565	09,265	895	849
			(2 5)	(0 1)	(39 9)	(41 06)		
5	पट्टी	-	02,546 *	02,663 *	05457	06,750	865	867
			-	(4 5)	(104 5)	(23 69)		
6	अन्तू	-	03,724 *	04,524 *	04,489	06,343	912	943
			-	(21 4)	(-0 8)	(41 36)		
7	कटरा मेदिनीगज	02,109	01,570 *	02,026 *	04,067	05,575	958	909
		-	(25 3)	(29 0)	(100 7)	(34 55)		

* यह कस्बे सेन्सस के अनुसार टाऊन नहीं थे । कोष्ठक मे जनसख्या वृद्धि प्रतिशत दिखाया गया है ।

स्रोत जिला जगगणना पुस्तिका 1951, 1961, 1971, 1981, 1991

(A)
N
DISTRICT PRATAPCARH
DISTRIBUTIONAL PATTERN OF
URBAN CENTRES
1901
5 0 5 10 15
KM
(B)
N
DISTRICT PRATAPGARH
DISTRIBUTIONAL PATTERN OF
URBAN CENTRES
1951
5 0 5 10 15
K M
(C)
N
DISTRICT I RATAPCARH
DISTRIBUTIONAL PATTERN OF
URBAN CENTRES
1961
5 0 5 10 15
K M
DECLASSIFIED
(D)
N
DISTRICT PRATAPGARH
DISTRIBUTIONAL PATTERN OF
URBAN CENTRES
1981
5 0 5 10 15
60000
15000
10000
5000

Fi 3 4
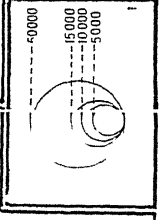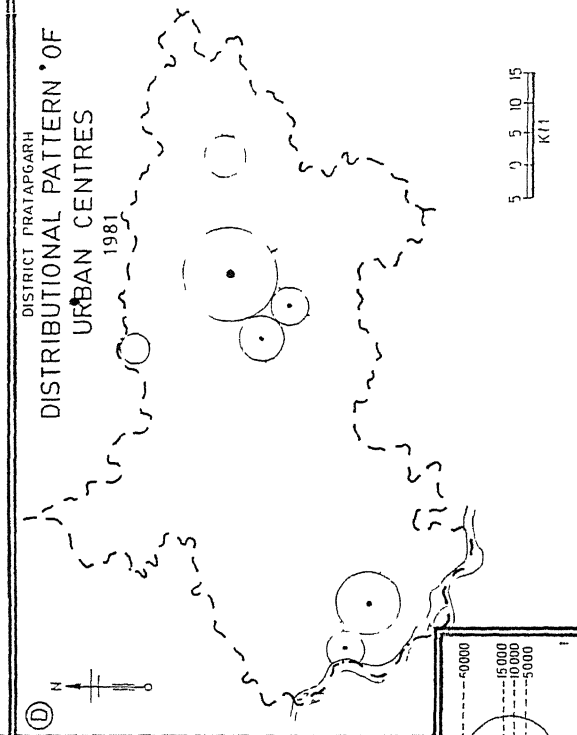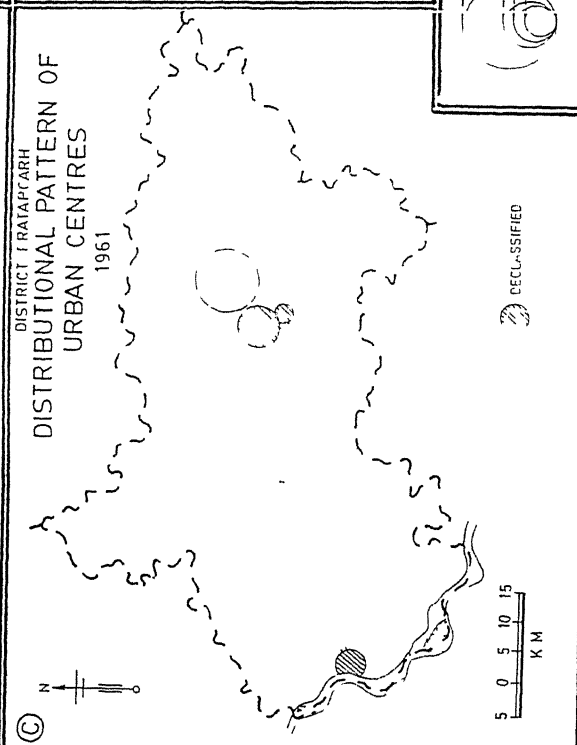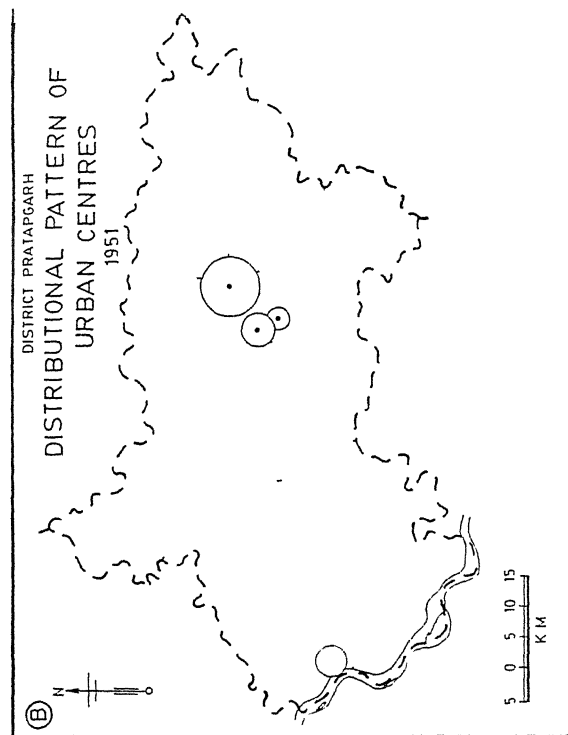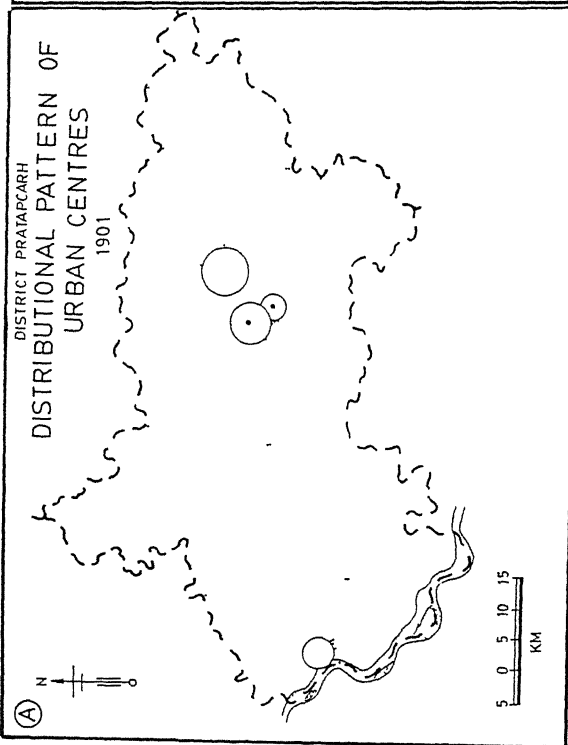
हुई है । सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि 1971 - 81 मे हुई । न केवल बेला प्रतापगढ मे, अपितु अन्य नगरीय अधिवासों मे भी इस दशक मे जनसख्या मे वृद्धि हुई है । जिन कस्बों मे 1981 - 91 मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई उनमे कुडा (41 75), अन्तू (41 36) तथा प्रतापगढ (41 06) है । कटरा (34 55), बेला प्रतापगढ (33 87), मानिकपुर (27 6) तथा पट्टी (23 69%) की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है ।

यदि हम सन् 1981 के लिग अनुपात (प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की सख्या) पर दृष्टिपात करे तो यह स्पष्ट होगा कि लिग अनुपात तथा नगरों की जनसख्या वृद्धि मे सीधा सह सम्बन्ध है । जिनका लिग अनुपात कम है, वहाँ जनसख्या वृद्धि अधिक तीव्रता से हुई है । इससे स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ, कुन्डा, पट्टी जैसे कस्बों मे जनसख्या वृद्धि का मुख्य कारण जनसख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास है । ग्रामीण क्षेत्रो से प्रवास के कारण ही इन कस्बों की जनसख्या मे वृद्धि हो रही है । प्रवासी जनसख्या मे महिलाओं का अनुपात कम है क्योंकि अधिकाश लोग इन कस्बों मे रोजगार का अवसर तलाश करने आते है । सामाजिक एव आर्थिक प्रतिबधों के कारण ये लोग महिलाओं को अपने साथ नही ला पाते (मिश्रा, 1982) । यह भी उल्लेखानीय है कि इन नगरीय अधिवासों के विकास के मुख्य आर्थिक आधार टरशियरी प्रकार के कार्य है जिनमे वाणिज्य, व्यापार तथा सेवा सम्बन्धी इकाइयों का बाहुल्य है । ये इकाइया मुख्य रूप से उत्पादक इकाई न होकर उपभोक्ता इकाइया है (मिश्रा 1990) । इस प्रकार की इकाइयों की वृद्धि का मुख्य कारण अध्ययन क्षेत्र की पिछडी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन है (मिश्रा, 1990) ।

कोटि- आकार नियम तथा नगरीय अधिवास - जैसा कि पूर्व वर्णित है, कोटि आकार नियम एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, जो अधिवास तत्र विश्लेषण का महत्वपूर्ण, सैद्धान्तिक आकार प्रस्तुत करती है, सारिणी सख्या 3 8 मे अध्ययन क्षेत्र के नगरीय अधिवासों का कोटि आकार नियम पर आधारित परिकल्पना ब्राउनिग (1961) तथा मिश्रा (1984) द्वारा प्रतिपादित तथा प्रयोग किये गये नियम पर आधारित है । इस परिकल्पना से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के नगरीय अधिवासों मे कोटि-आकार सकल्पना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती है । बेला प्रतापगढ

सारिणी सख्या 3 8 कोटि आकार नियम के अनुसार प्रतापगढ जनपद के नगरीय अधिवासों की जनसंख्या व वास्तविकता से विचलन

क्रम स0	नगरीय सेवाकेन्द्र	कोटि का रेसिप्रोकल	वास्तविक जनसख्या	अनुमानित जनसख्या	वास्तविक एव अनुमानित जन-सख्या के मध्य अन्तर	वास्तविक जनसख्या के आकार के अन्तर का प्रतिशत	अनुमानित जनसख्या के आकार के अन्तर का प्रतिशत
1	बेला प्रतापगढ	1 00	49,932	35086	+14846	29 7	70 3
2	कुन्डा	0 500	11,626	17543	-5917	50 9	150 9
3	मानिकपुर	0 333	8,883	11695	-2922	33 3	133 3
4	प्रतापगढ सिटी	0 250		8772	-2207	33 6	133 6
5	पट्टी	0 200	5,457	7017	-1530	28 0	128 6
6	अन्तू	0 166	4,489	5848	-1361	30 3	130 3
7	कटरा मेदिनीगज	0 142	4,067	5012	-945	23 2	123 2
	योग	2 591	90907	90973	29728	229	870 2
	औसत	37	12986 7	12996 1	4246 8	32 7	124 3

को छोड कर शेष अन्य 6 अधिवासों की जनसख्या नियम पर आधारित जनसख्या (अनुमानित जनसख्या) से कम है । वास्तविक एव अनुमानित जनसख्या का अन्तर एव उस पर आधारित प्रतिशत को सारिणी के वर्ग सख्या 7, 8 व 9 मे देखा जा सकता है । बेला प्रतापगढ ही एक ऐसा नगर है जिसकी वास्तविक जनसख्या अनुमानित जनसख्या से अधिक है । स्पष्ट है कि यह क्षेत्र का सबसे बडा प्रशासनिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक नगर है । यदि कोटि - आकार नियम के अनुसार नगरीय अधिवासों का वितरण होता तो बेला प्रतापगढ की वास्तविक तथा अनुमानित जनसख्या का अन्तराल (14,846) अन्य 6 अधिवासों मे वितरित होना चाहिये था । वास्तव मे अध्ययन क्षेत्र मे जेफरसन (1939) महोदय का प्राथमिक नगर सिद्धान्त अधिक तर्क सगत लगता है । क्योंकि यदि हम जनसख्या क्रम पर आधारित प्रथम दो (बेला प्रतापगढ तथा कुन्डा) नगरों की तुलना करे तो उन दोनों के बीच 1 4 अनुपात है तथा प्रथम एव अन्तिम (बेला प्रतापगढ व मानिकपुर) का अनुपात 1 123 है । स्पष्टतया अध्ययन क्षेत्र एक अविकसित क्षेत्र है, जहाँ पर एक सबसे बडा नगर होता है, शेष उससे छोटे होते है ।इससे यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे अधिवासों का सतुलित विकास अभी तक नहीं हो पाया है । सतुलित विकास के लिए उपयुक्त मानव अधिवास नीति की प्रासगिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

REFERENCES

1. Browning, L H & Gibbs, J P (1961), Some Measures of Demographic and Spatial Relationships among cities, in Gibbs, J.P. (ed.) Urban Research Methods, New Delhi : East West Press

2 Cunningham, A (1872), Archaeological Survey of India, XI. (Simla)

3. Fuhrer, A (1969), The Monumental Antiquities and Inscriptions in the North-Western Provinces and Oudh, Varanasi.

4. Jefferson, M. (1939), The Law of Primate city, Geog Rev 29, PP 226-232

5 King, L.J. (1962), A Quantitative Expression of the Pattern of urban settlement in Selected Area of the United States, Tijdschrift Voor Economischeen Sociate Geografie, 53

6 Misra, H.N. (1986), Rae Bareili, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, Northern India, in Hardoy, J.E. et al (ed.) Role of Small and Intermediate Urban Centres, London : Hodder and Stoughton

7 Misra, H.N (1984), Urban System of a Developing

Economy, Allahabad . II DR

8 Misra, H N. (1984) Human Settlement System and Regional Development in Developing Economy in Karnmeir, H D et al (edit) Equity with Growth : Planning Perspective for Small Towns in Developing Countries, Bangkok : AIT, 223-241

9. Misra, H.N and Misra, K K (1987), An Evolutionary Model of Service Centres' in a slow growing Economy, in Misra H N (Edit), Rural Geography, New Delhi Heritage Publishers

10. Misra, H N (1990), Tertiarisation in Indian Towns : A study of the Urban Growth Process in a Developing Region, I.G.U Regional Symposium on Asian-Pacific Countries, Beizing, China

11 Nevill, H.R (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad : Government Press

12 Smith, D.M. (1980) Patterns in Human Geography, London · Penguin

13. Smailes, A.W (1967), The Geography of Towns, London : Hutchinson

अध्याय 4

सेवाकेन्द्रों का स्थानिक विश्लेषण

विगत अध्याय मे अधिवास तत्र के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है । प्रस्तुत अध्याय मे अधिवासों मे होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनो का विश्लेषण किया गया है । इसके लिए सर्वपथम अध्ययन क्षेत्र मे सेवा केन्द्रों का चुनाव किया गया है और इन सेवा केन्द्रों मे ही परिवर्तनों को देखने का प्रयत्न किया गया है ।

सेवा केन्द्र सकल्पना एव चुनाव -

कोई भी अधिवास जब अपने आस पास के क्षेत्रों को एक या एक से अधिक सुविधाएँ अथवा सेवाए प्रदान करता है तो उसे सेवा केन्द्र कहा जाता है । इस प्रकार सेवा केन्द्र तथा सेवा केन्द्र से बाहर उसके आस पास रहने वाली जनसख्या मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । सेवा केन्द्र सम्बन्धी सकल्पना के प्रादुर्भाव का श्रेय कूले (1894), वान् थ्यूनेन (1826), गालपिन (1915) तथा क्रिस्ट्रालर (1933) को है । क्रिस्ट्रालर का योगदान इस दिशा मे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने सन् 1933 मे **केन्द्र - स्थल सिद्धान्त** को प्रतिपादित कर सेवा केन्द्रों की सकल्पना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया । अनेक अन्य पश्चिमी विद्वानों ने भी अपने शोध के द्वारा समय समय पर सेवा केन्द्रों से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। इनमे जेफरसन (1939), डिकिसन (1932), ब्रेसी (1963), ब्रश (1953), स्मेल्स (1944), बी0 जे0 एल0 बेरी (1958), फोल्के (1968) तथा मैफील्ड (1967) का विशेष योगदान है । कई भारतीय विद्वानों ने भी इस दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य किये है जिनका समीक्षात्मक विश्लेषण गुरूभाग सिह (1973) तथा के0 के0 मिश्रा (1981) ने विस्तार पूर्वक किया है ।

सेवा केन्द्रों के चुनाव मे विभिन्न प्रकार के आधारों तथा सूचकाको का प्रयोग किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन मे अधोलिखित सेवाओं पर विचार किया गया है

शैक्षिक सेवाए - प्राइमरी स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कालेज, डिग्री कालेज ।

2 चिकित्सा सम्बन्धी सेवाए - औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र ।

3 डाक एव सचार सम्बन्धी सेवाए - डाक घर एव तार घर ।

4 यातायात सेवाए - बस स्टेशन, बस स्टाप, रेलवे स्टेशन ।

5 वाणिज्य समबन्धी सेवाए - साप्ताहिक अथवा दैनिक बाजार केन्द्र ।

उपरोक्त पाँच प्रकार की सुविधाओं मे से यदि कोई भी चार सुविधाये उपलब्ध है तो उसे सेवा केन्द्र का दर्जा दिया गया है । इस प्रकार कुल 76 सेवा केन्द्र चुने गये है जिनमे 23 कुन्डा तहसील मे, 26 प्रतापगढ तहसील मे तथा 27 पट्टी तहसील मे है । इन सेवा केन्द्रों मे पायी जाने वाली विविध सुविधाओं को सारिणी सख्या 4 । मे प्रस्तुत किया गया है ।

सेवा केन्द्रों का सोपानक्रम

सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम अथवा सोपान क्रम निर्धारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानिक सगठन मे सेवा केन्द्रों के महत्व का पता चलता है । बडे सेवा केन्द्र का सेवा क्षेत्र बडा तथा छोटे सेवा केन्द्र का सेवा क्षेत्र छोटा होता है । सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम अथवा सोपानक्रम कई विधियों से ज्ञात किया जा सकता है । इनमे कोटि आकार विधि, यातायात अधिगम्यता पर आधारित केन्द्रियता तथा सेवा कार्यो के आधार पर निर्धारण की विधियाँ मुख्य है ।

सेवा केन्द्रों का कोटि - क्रम तत्र - ग्रामीण एव नगरीय सेवा केन्द्रों का सामूहिक तत्र विश्लेषण करने के लिए सेवा केन्द्रों को उनके जनसख्या क्रम के अनुसार लाग ग्राफ पर अकित किया गया है । "य" अक्ष पर जनसख्या कोटिक्रम "र" अक्ष पर अधिवासों की जनसख्या दिखायी गयी है । इस प्रकार कुल चार रेखाचित्र (चित्र सख्या 4 । तथा 4 2) प्रस्तुत किये गये है । यह रेखाचित्र अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों का जनसख्या के आधार पर तीन दशकों का (1961, 1971, 1981) पदानुक्रम प्रस्तुत करते है । इससे स्पष्ट है कि उच्च स्तर पर केवल एक सबसे बडा सेवा केन्द्र है और फिर एकाएक सेवाकेन्द्रों का आकार छोटा हो गया है । निम्न स्तर के कई सेवाकेन्द्र एक साथ पुजीभूत हो गये है । रेखा चित्र का आकार तीन

सारिणी सख्या 4 । प्रतापगढ जनपद के सेवाकेन्द्रों में उपलब्ध सेवाये (1961-81), अधिवास सूचकांक

क्रमाक	सेवाकेन्द्र	कार्यात्मक इकाई		कार्यात्मक प्रकार	
		1961	1981	1961	1981
01	बेला प्रतापगढ	16	143	6	16
02	कुण्डा	4	59	4	14
03	मानिकपुर	2	44	2	11
4	प्रतापगढ सिटी	1	15	1	8
05	कन्धई मधुपुर	-	4	-	4
06	पट्टी	5	35	5	13
07	ऐधा	-	4	5	4
08	अन्तू	2	13	2	9
09	कटरा मेदिनीगज	1	9	1	7
10	लरून	-	5	-	5
11	रेहुआ लालगज	3	10	3	7
12	अन्तसुन्ड	1	7	1	7
13	परियावा	2	8	2	7
14	सराय इनायत	1	8	1	7
15	स0 चन्द्रिका	4	8	2	8
16	राहाटीकर	1	6	1	4
17	सबलगढ	1	9	1	8
18	जामताली	4	8	3	7
19	डीहमेहदी	1	7	1	5
20	रामजीतपुर चिलबिला	4	5	3	5
21	धारूपुर	2	8	1	7

22	अजगरा	-	8	-	7
23	सग्रामगढ	5	10	3	9
24	दलीपपुर	4	8	4	7
25	ताला	-	7	-	6
26	भादयूँ	-	9	-	8
27	रामापुर	2	5	1	4
28	रामगज	2	11	1	11
29	उदईशाहपुर	1	11	1	10
30	मानधाता	3	11	3	11
31	मझिलगो	1	6	1	6
32	आसपुरदेवसरा	2	6	2	6
33	भदई	4	12	4	9
34	सरायभूपत	-	10	-	9
35	शीतलामऊ	1	8	1	7
36	आधारपुर	-	5	-	5
37	कालाकाकर	1	12	1	12
38	राजगढ	1	7	1	6
39	रामनगर भोजपुर	-	7	-	6
40	भूपियामऊ	2	7	2	6
41	सहरूआ	-	8	-	7
42	नारी	-	6	-	6
43	कोंहडौर	1	8	1	8
44	डडहियाडीह	1	8	1	6
45	गडवारा	4	7	4	5
46	कजासरायगुलामी	1	7	1	6

47	नरई		7	-	5
48	सेफाबाद	1	7	1	6
49	मेहरूआ मलकिन	-	6	-	5
50	भदोही	-	5	-	5
51	अठेहा	1	5	1	5
52	बासी	-	7	-	7
53	पिचूरा	-	6	-	6
54	सदहा	-	5	-	4
55	भोजपुर	-	6	-	6
56	भगसेरा	-	9	-	8
57	पूरेगोलिया	1	8	1	6
58	उतरास	-	6	-	5
59	हरचेनपुर	-	8	-	7
60	कन्धारपुर	-	6	-	5
61	बिन्द	-	6	-	5
62	धरौली	-	5	-	4
63	कलयानपुर	-	7	-	6
64	महुली	-	7	-	7
65	उगापुर	-	7	-	7
66	सागीपुर	3	11	3	11
67	आमापुर	-	8	-	7
68	नेवादाखुर्द	1	8	1	7
69	दशरथपुर	-	8	-	9

70	नरहरपुर	-	10	-	8
71	लक्ष्मणपुर	4	9	3	9
72	रूकैयापुर	1	6	1	5
73	सवैया	-	5	-	5
74	सरायभीमसेन	-	5	-	5
75	गुलामीपुर	-	6	-	6
76	रघुनाथपुर	-	6	-	5

स्रोत टाऊन विलेज डाइरेक्टरी, भारतीय जनगणना, 1961 - 81

Fig 41

Ⓐ
PRATAPGARH TAHSIL
50,000
20,000
10,000
5000
2000
1000
500
300
200
POPULATION
1981
1971
1961
0
2
4
8
20
30
RANK
Ⓑ
KUNDA TAHSIL
10,000
6000
4000
2000
1000
700
200
POPULATION
1981
1971
1961
0
2
4
8
20
30
RANK
Ⓒ
PATTI TAHSIL
6000
3000
1000
500
300
200
POPULATION
1971
1961
1981
0
2
4
8
20
30
RANK
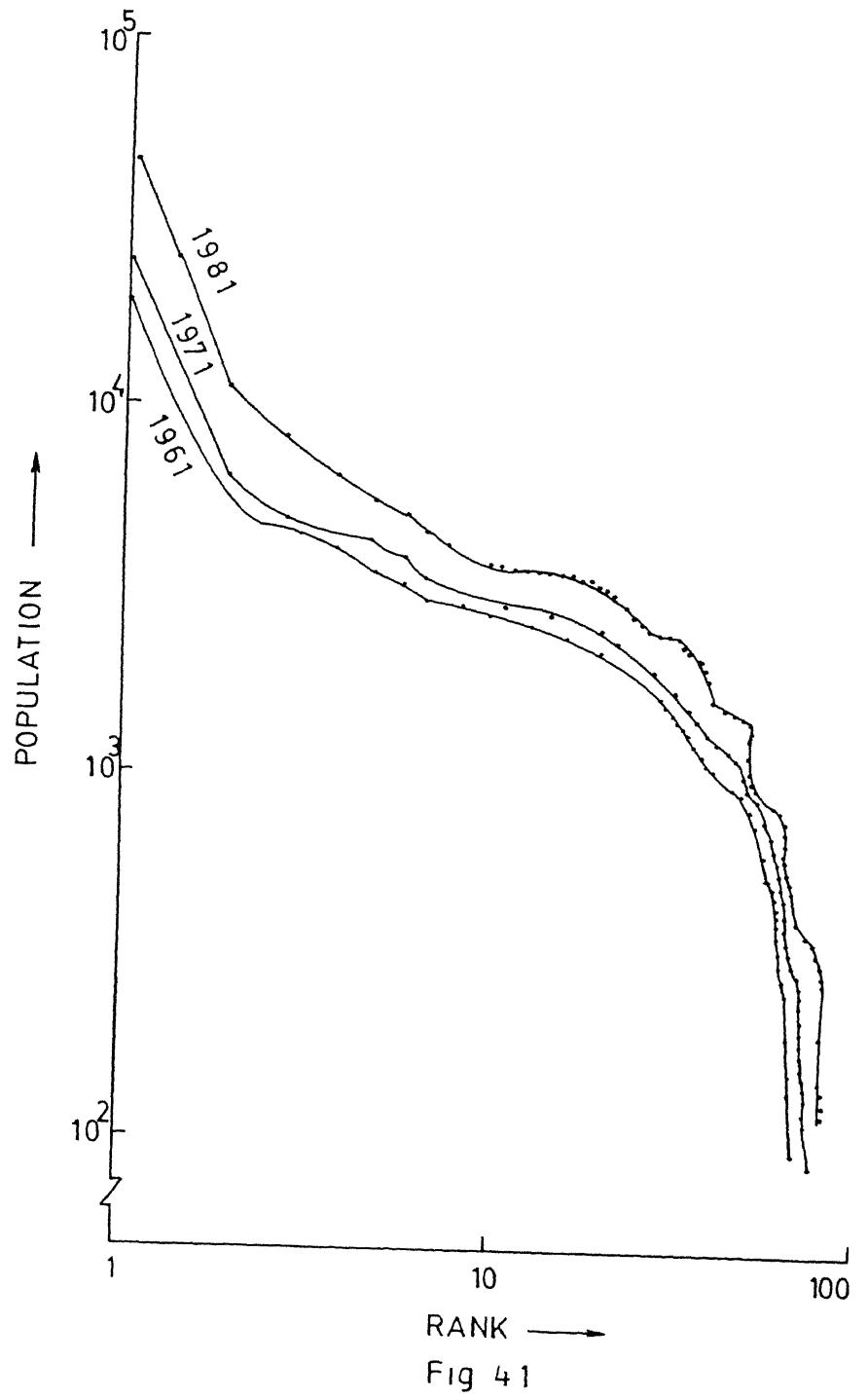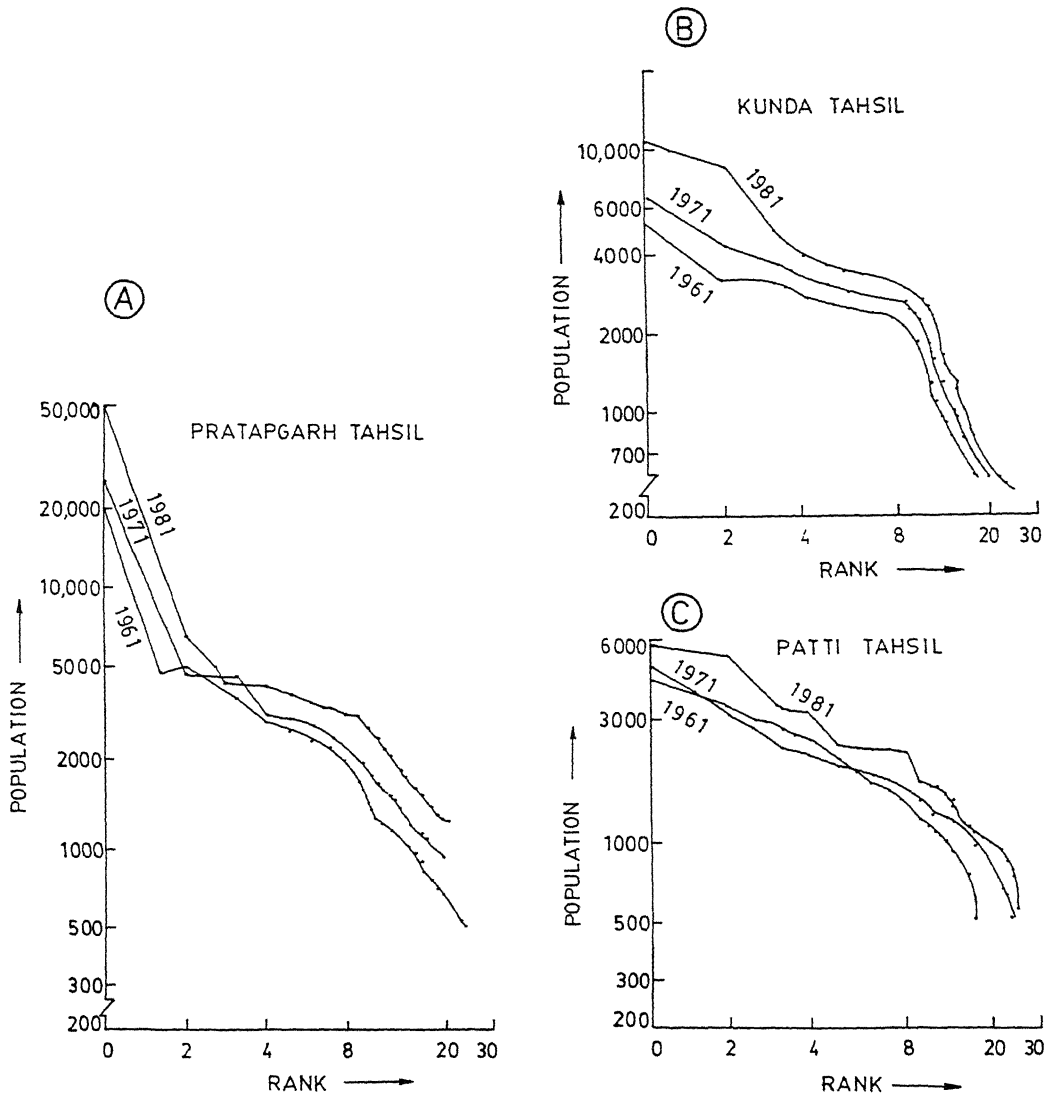
Fig 4.2

दशकों (1961, 1971, 1981) मे एक ही जैसा रहा है, किन्तु मध्यवर्ती भाग मे इस रेखाचित्र का आकार उन्नतोदर प्रकार का हो गया है । इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तीव्रता से बढ रही है । इससे यह भी स्पष्ट है कि सेवाकेन्द्रों का सोपानक्रम समुचित रूप से सगठित नहीं है । यह प्रतिरूप विषमता का द्योतक है । यही तथ्य तहसील स्तर पर भी परिलक्षित होते है ।

सेवा केन्द्रों का कार्यात्मक सोपान क्रम - सेवा केन्द्रों को कार्यात्मक सोपान क्रम के अनुसार वर्गीकृत करने के लिये अधिवास सूचकाक ज्ञात किया गया है । अधिवास सूचकाक को ज्ञात करने के लिये उडकाक तथा वेली (1979) द्वारा प्रदर्शित विधि का प्रयोग किया गया है । सर्वप्रथम कार्यात्मक भार निर्धारित करने मे अधोलिखित सूत्र प्रयोग मे लाया गया है

$$FCV = \frac{1 \times 100}{f}$$

FCV = Functional Centrality value
f = Frequency of a Function in all Service Centres

इस सूत्र के आधार पर परिकलित सेवाओं का कार्यात्मक भार सारिणी सख्या 4 2 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी के आधार पर प्रत्येक सेवा केन्द्र का अधिवास सूचकाक परिकलित किया गया है जिसके लिए अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है ।

$$SI = FCV \times Cf$$

SI = Settlement Index
FCV = Functional Centrality value
Cf = Occurrence of Functions in a Service centre

इस सूत्र के आधार पर परिकलित प्रत्येक सेवा केन्द्र का सूचकाक सारिणी सख्या 4 3 मे प्रस्तुत किया गया है । इसके आधार पर सेवा केन्द्रों को पदानुक्रम मे वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया

सारिणी सख्या 4 2 अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न सेवाओं का कार्यात्मक भार

क्रम स0	सेवाये	कार्यात्मक भार
	शिक्षा सेवायें	
1	प्राइमरी स्कूल	2 0
2	जूनियर बेसिक स्कूल	0 9
3	सीनियर बेसिक स्कूल	2 4
4	हाईस्कूल	3 4
5	इन्टरमीडियेट कालेज	10 0
6	डिग्री कालेज	16 6
	स्वास्थ्य सेवायें	
7	चिकित्सालय	2 8
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5 6
9	परिवाण कल्याण केन्द्र	5 0
10	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	3 6
11	औषधालय	3 3
	डाक व तार सेवाये	
12	डाकघर	1 2
13	तारघर एव फोन	2 7
	बस एवं रेलवे स्टेशन सेवायें	
14	बस स्टाप व स्टेशन	1 8
15	रेलवे स्टेशन	16 7
	बाजार सेवायें	
16	बाजार के दिन	0 5
17	बैंक सेवाये	4 6
18	पुलिस स्टेशन सेवा	10 0

स्रोत सूत्र के आधार पर परिकलित

सारिणी सख्या 4 3 प्रतापगढ जनपद के सेवाकेन्द्रों मे उपलब्ध सेवायें (1961-81)

अधिवास सूचकाक

क्रम स0	सेवाकेन्द्र	अधिवास सूचकाक	
01	बेला प्रतापगढ	243 8	306 9
02	कुण्डा	61 0	112 6
03	मानिकपुर	22 8	69 0
04	प्रतापगढ सिटी	3 2	73 5
05	कन्धई मधुपुर	-	7 3
06	पट्टी	73 1	102 4
07	ऐधा	-	5 3
08	अन्तू	7 2	47 8
09	कटरा मेदिनीगज	3 2	18 7
10	लरून	-	9 1
11	रेहुआ लालगज	22 3	30 9
12	अन्तसुन्ड	3 2	19 4
13	परियावा	7 2	14 7
14	सराय इनायत	3 2	17 6
15	सडवा चन्द्रिका	11 1	22 7
16	राहाटीकर	3 2	8 5
17	सबलगढ	4 0	24 3
18	जामताली	13 5	14 4
19	डीहमेहदी	3 2	12 4
20	रामजीतपुर चिलबिला	23 8	10 6

21	धारूपुर	11 4	17 1
22	अजगरा	-	13 6
23	सग्रामगढ	37 0	19 5
24	दलीपपुर	24 0	24 5
25	ताला	-	13 2
26	भादर्यू	-	21 5
27	रामापुर	6 3	4 9
28	रामगज	7 3	23 1
29	उदईशाहपुर	4 0	25 9
30	मानधाता	13 5	26 8
31	मझिलागो	3 2	10 9
32	आसपुर देवसरा	9 5	10 6
33	भदरी	30 3	35 7
34	सराय भूपत	-	23 1
35	शीतलामऊ	4 0	14 6
36	आधारपुर	-	10 4
37	कालाकाकर	4 0	54 3
38	राजगढ	3 2	14 8
39	रामनगर भोजपुर	-	10 1
40	भूपियामऊ	20 6	26 4
41	सहेरूआ	-	16 2
42	नरी	-	10 9
43	कोंहडौर	14 3	16 8
44	डडैयाडीह	4 0	13 7

45	गडवारा	16 0	11 3
46	कजासरायगुलामी	3 2	14 6
47	नरई	-	9 3
48	सैफाबाद	5 3	12 7
49	मेहलवा मलकिन	-	11 0
50	भदोही	-	11 2
51	अठेहा	6 3	10 9
52	बासी	-	15 5
53	पिचूरा	-	14 1
54	सदहा	12 5	6 0
55	भोजपुर	-	13 4
56	भगेसरा	-	18 0
57	पूरेगोलिया	4 0	13 6
58	उतरास	-	10 9
59	हरचेनपुर	-	13 9
60	कन्धारपुर	-	8 5
61	बीन्द	-	11 0
62	धरौली	-	6 0
63	कल्याणपुर	-	9 7
64	महुली	-	14 8
65	उगापुर	-	17 0
66	सागीपुर	22 8	31 4
67	आयापुर		15 5

68	नेवादाखुर्द	4 0	26 8
69	दशरथपुर	-	7 3
70	नरहरपुर	-	19 7
71	लक्ष्मणपुर	23 6	24 0
72	रूकैयापुर	4 3	6 3
73	सवैया	-	8 3
74	सरायभीमसेन	-	11 5
75	गुलामीपुर	-	16 7
76	रघुनाथपुर	-	10 5

स्रोत परिकलित

गया है । सोपानक्रम समूह ज्ञात करने के लिये एक वितरण आरेख (चित्र सख्या 4 3) की रचना की गयी है जिसके "य" अक्ष पर सेवा केन्द्रों के जनसख्या का क्रम दिखाया गया है तथा "र" अक्ष पर सेवा केन्द्रों के अधिवास सूचकाक को प्रदर्शित किया गया है । इस वितरण आरेख के आधार पर सेवा केन्द्रों को तीन भागों मे विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है

। प्रथम सेवा केन्द्र बेला प्रतापगढ जो जनपद का मुख्यालय है, अध्ययन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र है तथा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक सस्थाए एव सेवाए उपलब्ध है । बेला प्रतापगढ का अधिवास सूचकाक 306 9 है और इसे प्राथमिक केन्द्र की सज्ञा दी जा सकती है ।

2 द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्र - इसके अन्तर्गत कुन्डा (112 6), पट्टी (102 4), प्रतापगढ सिटी (73 5), मानिकपुर (69 0) तथा कालाकाकर (54 3) है । यह सभी सेवा केन्द्र 1981 की जनगणना के अनुसार नगरीय अधिवास भी है ।

3 तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्र - यह सेवा केन्द्रों का सबसे बडा समूह है जिसके अन्तर्गत 70 सेवा केन्द्र आते है जो इस प्रकार है अन्तू (47 8), भदरी (35 7), सागीपुर (31 4), रेहुआलालगज (30 9), नेवादाखुर्द (26 8), मानधाता (26 8), भोपियामऊ (26 4), उदईशाहपुर (25 91), दलीपपुर (24 5), सबलगढ (24 3), लक्ष्मणपुर (24 0), रामगढ (23 1), सरायभूपत (23 1), सडवा चन्द्रिका (22 7), भादयूँ (21 5), नरहरपुर (19 7), सग्रामगढ (19 5), परियावाँ (19 4), कटरामेदनीगज (18 7), भगसेरा (18 0), सराय इन्द्रावत (17 6), धारूपुर (17 1), उगापुर (17 0), कोहडौर (16 8), गुलामीपुर (16 7), सहेरुआ (16 2), बासी (15 5), आमापुर (15 5), महुली राजगढ (14 8), शीतलामऊ (14 6), कजासरायगुलामी (14 6), परियाँवा (14 5), जामताली (14 4), पिचूरा (14 1), हरचेनपुर (13 9), उडैयाडीह (13 7), पूरेगोलिया (13 6), अजगरा (13 6), भोजपुर (13 4), ताला (13 2), सैफाबाद (12 7), डीहमेहदी (12 4), सरायभीमसेन (11 5), गडवारा (11 3), भदोही (11 2), महेलवा मलकिन (11 0), बिन्द (11 0), उतरास (10 9), अठेहा

(10 9),नरी (10 9), मझिलेगा (10 9), आसपुरदेवसरा (10 6), रामजीतपुर चिलबिला (10 6,), रघुनाथपुर (10 5), आधारपुर (10 5), कल्यानपुर (9 7), नरई (9 3), लरून (9 1), राहाटीकर (8 5), कन्धारपुर (8 5), सवैया (8 3), दशरथपुर (7 3), कन्धईमधुपुर (7 3), रोकैयापुर (6 3), धरौली (6 0), सदहा (6 0), ऐधा (5 3), रामापुर (4 9) ।

सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरूप - इन सेवा केन्द्रों के वितरण प्रतिरूप (चित्र सख्या 4 4) से स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों का वितरण रैन्डम प्रकार का है । इस मानचित्र से यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे कई ऐसे भाग है जो सेवा केन्द्र विहीन है । सेवा केन्द्रों के समान वितरण के अभाव मे स्थानिक, सगठन का अभाव है जो पिछडेपन का द्योतक है । ठीक इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के सेवाकेन्द्र भी सख्या मे कम तथा अनियमित रूप से वितरित है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम का भाग ऐसा है जहाँ पर द्वितीय श्रेणी के कोई भी सेवा केन्द्र नहीं पाये जाते है । इससे स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों एव द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों मे सम्बन्ध का अभाव है । सभी स्तर के सेवा केन्द्र बेला प्रतापगढ पर ही आश्रित है । यह ही इसकी प्राथमिकता का मुख्य कारण है ।

सेवाकेन्द्रों के परिवर्तन की दिशा - यदि हम विगत् 20 वर्षो मे हुये परिवर्तनों पर दृष्टिपात करे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 1961 और 1981 के मध्य सेवा केन्द्रों की सरचना मे पर्याप्त अन्तर आया है । सन् 1961 तथा 1981 के मध्य सेवा केन्द्रों मे उनकी कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक प्रकार तथा अधिवास सूचकाको का तुलनात्मक अध्ययन सारिणी (सख्या 4 3) से किया जा सकता है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि अधिकाश सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाई मे विगत दो दशकों मे दुगुने से अधिक वृद्धि हुई । इस सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि 34 ऐसे अधिवास है, जो सन् 1981 मे पहली बार सेवा केन्द्र के रूप मे उभर कर आये है । ठीक इसी तरह कार्यात्मक प्रकार मे भी वृद्धि हुई है । इनके आधार पर परिकलित अधिवास सूचकाक मे भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । परिवर्तन की दिशा सकारात्मक है क्योंकि सभी सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाईयों एव प्रकारों मे वृद्धि हुई है । सन् 1961 की स्थिति के आधार पर वितरण आरेख (चित्र सख्या 4 3) की रचना की गयी है जिसमे सेवा

केन्द्रों के सूचकाक तथा उनकी जनसख्या को प्रदर्शित किया गया है । इस आरेख से स्पष्ट है कि बेला प्रतापगढ उस समय भी प्रथम श्रेणी का सेवा केन्द्र था किन्तु द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों की सख्या केवल दो थी । इन द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रों(पट्टी एव मानिकपुर) का स्थान सन् 1981 मे जहाँ सुरक्षित है, वहीं दूसरी ओर तीन अन्य सेवा केन्द्र आ जुडे है । सबसे अधिक परिवर्तन तृतीय स्तर के सेवा केन्द्रों मे हुआ है । इनकी सख्या सन् 1961 मे केवल 31 थी जबकि सन् 1981 मे इस वर्ग के अन्तर्गत 70 सेवा केन्द्र हो गये है । इस प्रकार इस वर्ग मे सेवा केन्द्रों की सख्या बढी है ।

सेवा केन्द्रों का कार्य - आकार सम्बन्ध - बेरी तथी गैरीसन (1958) का विचार है कि सेवा केन्द्रों की जनसख्या तथा उनके द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य मे सीधा सह सम्बन्ध है । सामान्य परीक्षण मे भी यह देखा गया है कि जनसख्या जैसे जैसे बढती है, वैसे वैसे सेवाकेन्द्र की सेवाओं तथा सेवा की इकाईयों मे वृद्धि होती है क्योंकि जनसख्या वृद्धि से वस्तुओं की माग मे भी वृद्धि होती है । इस दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों की जनसख्या तथा उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाली सेवाओं को आधार मान कर अधोलिखित सकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है ।

1 सेवा केन्द्रों की जनसख्या एव उनमे केन्द्रित कार्यात्मक इकाईयों मे धनात्मक सह सम्बन्ध है ।
2 सेवा केन्द्रों की जनसख्या अथवा आकार एव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो मे धनात्मक सह - सम्बन्ध है ।
3 सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाईयों एव उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं (कार्यात्मक प्रकार) मे धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

उपरोक्त तीनों सकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए छ आरेखों (चित्र सख्या 4 5, अ, ब, स, द, य, फ) की रचना की गयी है । इन आरेखों से स्पष्ट है कि एक निश्चित जनसख्या तक सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाईयों मे कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं दृष्टि गोचर होता है ।

उदाहरण के लिए 100 से 300 जनसख्या वाले सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाई की सख्या मे कोई अन्तर नहीं है । पुन 300 से 1000 की आबादी तक और 1000 से 4000 आबादी तक, कार्यात्मक इकाईयों की सख्या मे कोई विशेष अन्तर नहीं है किन्तु 4000 के ऊपर वाले सेवा केन्द्र, मुख्य रूप से जिनकी आबादी 5000 से 50,000 के बीच है, उनकी कार्यात्मक इकाईयों मे बहुत ही उल्लेखनीय अन्तर पाया जाता है । 5000 से 11,000 के बीच वाले सेवा केन्द्रों की इकाईयों मे पर्याप्त अन्तर आया है । 5000 से 11000 के बीच वाले सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाईयों की सख्या मे आबादी बढने के साथ वृद्धि होती गयी है । किन्तु 11000 के ऊपर आबादी वाले सेवा केन्द्र (प्रस्तुत अध्ययन मे बेला प्रतापगढ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है) मे कार्यात्मक इकाईयों की सख्या सहसा बहुत अधिक हो गयी है । 5000 से 11000 आबादी वाले सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाईयों की सख्या 20 से 60 के बीच है । जबकि 50,000 इकाई वाले सेवा केन्द्र की कार्यात्मक इकाई की सख्या 150 है । इस प्रकार इतना तो स्पष्ट है कि जनसख्या बढने के साथ कार्यात्मक इकाईयों मे वृद्धि होती है । किन्तु कम आबादी वाले छोटे सेवा केन्द्रों मे यह बात स्पष्ट नहीं होती है । अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश सेवा केन्द्र 4000 से कम आबादी वाले है । अत रैन्क - आर्डर जिका सूत्र इस प्रकार है

पर आधारित सह - सम्बन्ध धनात्मक नहीं प्रतीत होता है । इस तथ्य की पुष्टि के लिये सेवा केन्द्रों को उनकी जनसख्या तथा कार्यात्मक इकाईयों के क्रम के आधार पर तहसील स्तर पर सह सम्बन्ध गुणाक उक्त सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है । सेवा केन्द्रों की जनसख्या एव कार्यात्मक इकाईयों मे तहसील स्तर पर जो सह - सम्बन्ध प्राप्त किये गये है वे ऋणात्मक है । कुन्डा, पट्टी तथा प्रतापगढ तहसीलों के परिकलित सह - सम्बन्ध क्रमश - 0 3, - 0 3, तथा - 0 4 है (सारिणी सख्या 4 4) । वर्ष 1961 पर आधारित आकडों के आधार पर परिकलित

सारिणी सख्या 4 4 प्रतापगढ जनपद मे तहसील स्तर पर सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक प्रकार, अधिवास सूचकांक तथा उनकी जनसख्या का सह-सम्बन्ध गुणाक

(1961-81)

चर	1961			1981		
	कुन्डा	प्रतापगढ	पट्टी	कुन्डा	प्रतापगढ	पट्टी
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा कार्यात्मक इकाई	-0 3	-0 1	+0 9	-0 3	-0 4	-0 3
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा कार्यात्मक प्रकार	-0 9	-0 2	-0 5	-0 3	-0 2	-0 2
सेवाकेन्द्रों की जनसख्या तथा अधिवास सूचकाक	-0 1	-0 1	-0 1	-0 2	-0 3	-0 4

स्रोत परिकलित

सह सम्बन्ध भी ऋणात्मक है । सेवा केन्द्रों की जनसख्या तथा उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के प्रकार म सम्बन्ध देखने के लिये भी रेखा चित्र तैयार किया गया है । इससे भी पहले जैसी स्थिति उभर कर सामने आती है । इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 1000 तक की आबादी वाले सेवा केन्द्रों की सेवाएँ 4 से 8 प्रकार की है । 1000 आबादी वाले सेवा केन्द्रों मे भी सेवाओं की सख्या सामान्यत 4 से 10 के बीच है । इस प्रकार 10,000 आबादी तक कोई विशेष अन्तर स्पष्ट नहीं होता है । किन्तु इससे अधिक आबादी वाले केन्द्र उदाहरण के लिये बेला प्रतापगढ एव कुन्डा मे सेवाओं की सख्या 14 एव 16 प्रकार की है । इस सह - सम्बन्ध को तहसील स्तर पर देखने का प्रयत्न किया गया है ,। तहसील स्तर पर सेवा केन्द्रों की जनसख्या एव उनके सेवा के प्रकार मे ऋणात्मक सह सम्बन्ध है । कुन्डा, पट्टी एव प्रतापगढ तहसीलों मे सह सम्बन्ध क्रमश - 0 3, - 0 2 तथा -0 3 है । सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाई एव उनके कार्यात्मक प्रकारों का सह-सम्बन्ध भी चित्र द्वारा (चित्र सख्या 4 5) प्रस्तुत किया गया है । इस आरेख से स्पष्ट होता है कि अधिकाश सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक इकाई 20 से कम ही है । तथा उनके कार्यात्मक प्रकार मे भी अन्तर नहीं है । अधिकाश सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाई की सख्या 4 और 12 के बीच है । इस आरेख से भी धनात्मक सह - सम्बन्ध बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता है । यही स्थिति 20 वर्ष पहले भी थी । जैसा कि चित्र सख्या 4 5 से स्पष्ट होता है । यद्यपि इनमे कोई भी सह - सम्बन्ध प्रमाणिक नहीं प्रतीत होते है । किन्तु इस दिशा मे और अधिक शोध की भी आवाश्यकता है ।

सेवा केन्द्रों मे जनसख्या की परिवर्तनशीलता

सेवा केन्द्रों मे कार्यात्मक इकाई एव उनके प्रकारों के विश्लेषण के साथ - साथ उनकी जनसख्या मे होने वाले परिवर्तन पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है । यह एक सामाजिक प्रकिया है जो आर्थिक प्रक्रिया से जुडी है । विगत 20 वर्षो (1961 - 81) मे सेवा केन्द्रों मे होने वाले जनसख्या की वृद्धि को सारिणी 4.5 -द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस सारिणी के आधार पर सेवा केन्द्रों को चार भागों मे विभक्त किया जा सकता है

1 वे सेवा केन्द्र जिनमे जनसख्या वृद्धि 200% से अधिक हुयी है जैसे - कुन्डा, परियावाँ एव सराय भूपत ।

सारिणी सख्या 4 5 सेवा केन्द्रों मे जनसख्या वृद्धि (1961 - 81)

क्रम स0	सेवा केन्द्र	प्रातशत
01	बेला प्रतापगढ	133 4
02	कुन्डा	273 6
03	मानिकपु	62 1
04	प्रतापगढ	39 4
05	कन्धई मधुपुर	37 5
06	पट्टी	114 3
07	ऐधा	58 7
08	अन्तू	20 5
09	कटरा मेदिनी गज	158 8
10	लरून	46 6
11	रेहुआ लाल गज	26 6
12	अन्तसुण्ड	3 0
13	परियावा	370 9
14	सराय इन्द्रावत	42 2
15	सडवा चन्द्रिक	39 5
16	शहाटीकर	26 2
17	सबलगढ	48 7
18	जामताली	25 1
19	डीह मेहदी	44 2
20	रामजीतपुर चिलबिला	48 9

21	धारूपुर	33 2
22	अजगरा	28 9
23	सग्रामगढ	43 6
24	दलीपपुर	59 4
25	ताला	57 8
26	भादयू	79 6
27	रामापुर	110 1
28	रामगज	64 4
29	उदई शाहपुर	54 1
30	मानधाता	83 5
31	मझिलगो	10 0
32	आसपुर देवसरा	62 1
33	भदरी	38 1
34	सराय भूपत	490 8
35	शीतलामऊ	68 1
36	आधारपुर	31 8
37	मोहम्मदाबाद उर्फ कालाकाकर	13 2
38	राजगढ	9 3
39	रामनगर भोजपुर	25 3
40	भोपियामऊ	92 5
41	सहेरूआ	53 1
42	नरी	40 7
43	कोंहडौर	66 7
44	उडैयाडीह	50 7
45	गडवारा	32 4

46	कजासराय गुलामी	43 9
47	नरई	35 9
48	सैफाबाद	41 9
49	मेहलवा मलकिन	64 6
50	भदोही	70 2
51	अठेहा	32 0
52	बासी	47 3
53	पिचूरा	25 1
54	सदहा	51 2
55	भोजपुर	89 5
56	भगेसर	33 2
57	पूरे गोलिया	111 2
58	उतरास	47 2
59	हरचेनपुर	84 4
60	कन्धारपुर	19 6
61	बीन्द	61 5
62	धरौली	-7 3
63	कल्यानपुर	42 3
64	महुली	- -
65	दशरथपुर	0 9
66	उगापुर	48 2
67	सागीपुर	-4 4
68	आमापुर	56 2
69	नेवादाखुर्द	20 8
70	नरहरपुर	22 6

71	लक्ष्मणपुर	50 0
72	रोकैयापुर	15 3
73	सवेया	43 8
74	रघुनाथपुर	15 7
75	सरायभीमसेनपुर	43 2
76	गुलामीपुर	46 4

श्रोत जनपद जनगणना पुस्तिका 1961, 1981

2 वे सेवा केन्द्र जिनमे जनसख्या वृद्धि 150% से 200% के बीच है जैसे - बेला प्रतापगढ, कधई मधुपुर, कटरा मेदनीगज, रामापुर एव पूरे गोलिया

3 वे सेवा केन्द्र जहॉ पर कि जनसख्या वृद्धि 50% से 100% के मध्य है जैसे - मानिकपुर, ऐधा, दलीपपुर, ताला, भादयू, रामगज, उदयीशाहपुर, मानधाता, आसपुर देवसरा, शीतलमऊ, भोपिया मऊ, सहेरूआ, कोंहडौर, उडैयाडीह, मेहलवा मालकिन, सदहा, भोजपुर, हरचेनपुर, बींद, आलापुर, लक्ष्मणपुर एव सराय भीमसेनपुर आदि ।

4 वे सेवा केन्द्र जिनकी जनसख्या मे 50% से कम वृद्धि हुयी है वे इस प्रकार है - नरी, गडवारा, कजासराय गुलामी, नरई, सैफाबाद, अठेहा, बासी, पिचूरा, भगसेरा, उतरास, कन्धारपुर, कल्यानपुर, आगापुर, नेबादा खुर्द, नरहरपुर, रोकैयापुर, सवैया, रघुनाथपुर, मुलामीपुर ।

5 कुछ ऐसे भी सेवा केन्द्र है जहॉ पर अपवादस्वरूप जनसख्या मे ह्रास हुआ है जैसे - धरौली, दशरथपुर, सागीपुर एव महुली ।

सेवा केन्द्रों मे साक्षरता की स्थिति

यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकाक है जो सामाजिक स्तर मे परिवर्तनशीलता का द्योतक है। अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों का शैक्षिक स्तर एव विगत दो दशकों (1961 - 81) मे कुल जनसख्या मे साक्षरता प्रतिशत सारिणी 4 6 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि सेवा केन्द्रों मे निवास करने वाली जनसख्या का साक्षरता अनुपात बढ रहा है । 99 प्रतिशत केन्द्रों मे साक्षरता की स्थिति मे सुधार हुआ है । सन् 1981 की साक्षरता प्रतिशत के आधार पर सेवा केन्द्रों को अधोलिखित वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है

1 वे सेवा केन्द्र जहॉ पर साक्षरता का अनुपात 25 से अधिक है । जैसे - प्रतापगढ, पट्टी, राजगढ, तथा सराय भीमसेनपुर ।

2 वे सेवा केन्द्र जहॉ पर कि साक्षरता का अनुपात 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है जैसे -

सारिणी संख्या 4 6 सेवाकेन्द्रों में साक्षरता 1961-81 (प्रतिशत मे)

क्रम स0	सेवाकेन्द्र	1961	1981
01	बेला पतापगढ		56 4
02	कुन्डा	19 0	31 8
03	मानिकपुर	6 9	26 3
04	प्रतापगढ सिटी	22 6	24 8
05	कन्धई मधुपुर	2 2	29 1
06	पट्टी	20 8	51 8
07	ऐंधा	9 7	30 0
08	अन्तू	13 8	31 6
09	कटरा मेदिनीगज	18 5	33 4
10	लरूल	6 0	14.7
11	रेहुआ लालगज	12 6	22 0
12	अन्तसण्ड	8 9	20 7
13	परियावा	13 9	18 7
14	सराय इन्द्रावत	9 5	23 2
15	सडवा चन्द्रिका	15 4	26 9
16	राहाटीकर	20 3	20 4
17	सबलगढ	16 1	37 0
18	जामताली	15 2	20 6
19	डीहमेहदी	20 4	28 1
20	रामजीतपुर चिलाबेला	17 2	15 1

21	धारूपुर	15 0	25 9
22	अजगरा	14 5	28 3
23	सग्रामगढ	12 8	24 5
24	दलीपपुर	24 8	17 8
25	ताला	18 1	31 3
26	भादयू	8 7	37 2
27	रामापुर	15 3	18 7
28	रामगज	28 1	29 4
29	उदईशाहपुर	17 4	29 7
30	मानधाता	21 4	27 2
31	मझिलगो	4 5	25 6
32	आसपुर देवसरा	12 6	22 8
33	भदरी	2 3	27 2
34	सराय भूपत	-	38 0
35	शीतलमऊ	22 0	37 8
36	आधारपुर	12 0	35 1
37	मोहम्मदाबाद उर्फ कालाकाकर	39 1	38 7
38	राजगढ	11 8	55 2
39	रामनगर भोजपुर	21 5	24 3
40	भोपियामऊ	21 9	31 3
41	सहेरूआ	18 1	23 6
42	नरी	4 0	16 7
43	कोंहडौर	25 0	37 6

44	उडेयाडीह	20 0	28 3
45	गडवारा	22 2	31 3
46	कजासराय गुलामी	13 8	24 5
47	नरई	11 2	20 2
48	सैफाबाद	15 1	26 2
49	मेहलवा मालकिन	12 7	42 7
50	भदोही	18 2	32 4
51	अठेहा	16 1	21 7
52	बासी	9 3	17 8
53	पिंचूरा	3 8	9 8
54	सदहा	6 8	13 8
55	भोजपुर	21 9	23 8
56	भगसेरा	24 7	35 5
57	पूरेगोलिया	61 5	43 7
58	उतरास	8 1	16 5
59	हरचेनपुर	19 0	22 7
60	कन्धारपुर	15 6	17 2
61	बीन्द	12 8	19 8
62	धरौली	15 8	22 8
63	कल्यानपुर	3 8	31 5
64	महुली		10 0
65	दशरथपुर	11 0	19 0
66	उगापुर	20 6	28 6

67	सागीपुर	16 7	32 0
68	आमापुर	17 8	28 3
69	नेवादाखुर्द	9 6	35 1
70	नरहरपुर	8 7	41 9
71	लक्ष्मणपुर	36 6	47 4
72	रोकैयापुर	22 9	26 2
73	सवैया	10 4	18 8
74	रघुनाथपुर	20 9	32 3
75	सरायभीमसेनपुर	18 5	63 2
76	गुलामीपुर	8 2	24 6

स्रोत जनपद जनगणना पुस्तिका 1961, 1981

भोपियामऊ, कोंहडौर, गडवारा, सैफाबाद, मेहलवा मर्लाकिन, कुन्डा, मानिकपुर, कधई, मधुपुर, ऐधा, अन्तू, कटरा मेदिनीगज, सडवा चन्द्रिका, सबलगढ, डीह मेहथी, धारूपुर, अजगरा, ताला, भादयूँ, रामगज, उदयीशाहपुर, मानधाता, मझिलुगो, भदरी, सराय भूपत, शीतलमऊ, धारूपुर, कालाकाकर, भदोही, उडैयाडीह, भगसेरा, पूरेगोलिया, कल्यानपुर, आगापुर, सागीपुर, आमापुर, नरहरपुर, नेवादा खुर्द, लक्ष्मणपुर, रोकैयापुर तथा रघुनाथपुर ।

3 वे सेवा केन्द्र जहाँ पर कि साक्षरता का अनुपात 25 प्रतिशत से कम है जैसे - प्रतापगढ सिटी, लरून, रेहुआ, लालगज, अन्तसुन्ड, सराय इन्द्रावत, परियावाँ, रहाटीकर, जामताली, चिलबिला, सग्रामगढ, दलीपपुर, रामपुर, आसपुर देवसरा, राम नगर, भोजपुर, नरी, सहेरवा, कजा सराय गुलामी, नरई, अठेहा, बासी, पिचूरा, सदहा, भोजपुर, उतरास, हरचेनपुर, कधारपुर, बीद, धरौली, महुली, दशरथपुर, सवैया एव मुलामीपुर ।

यह उल्लेखनीय है कि इनमे से पिचूरा को छोड कर शेष अन्य सेवा केन्द्रों का साक्षरता अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक है । सन् 1961 की तुलना मे 1981 मे जो वृद्धि हुयी है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामाजिक परिवर्तन की लहर अब तीव्रता से चल पडी है । यद्यपि कि साक्षरता स्तर मे अभिवृद्धि जनसख्या प्रवास को बढावा दे रही है । यही कारण है कि तहसील एव जिला मुख्यालयों की जनसख्या बढ रही है तथा रोजगार के अवसर की तलाश मे लोग आस - पास के नगरों उदाहरण के लिये लखनऊ, कानपुर, बनारस एव इलाहाबाद की ओर प्रवास कर रहे है ।

सेवा केन्द्रों की आर्थिक सरचना - सेवा केन्द्रों की आर्थिक सरचना का विश्लेषण करने के लिये उनमे काम करने वाली जनसख्या को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय वर्गो मे विभक्त किया गया है और 1961 तथा 1981 के आँकडों के आधार पर तुलनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । यह तुलनात्मक स्थिति रेखाचित्र (4 6) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इससे अधोलिखित तीन निष्कर्ष निकलते है

1 तृतीयक प्रकार के व्यवसाय मे लगी हुयी जनसख्या के प्रतिशत मे सन् 1981 में 1961 की

तुलना मे वृद्धि हुयी है ।

2 द्वितीय प्रकार के व्यवसाय मे लगी हुयी जनसख्या के प्रतिशत मे वृद्धि हो रही है तथा साथ ही साथ अधिकाश सेवा केन्द्रों मे द्वितीयक प्रकार का व्यवसाय प्रचलित हो रहा है ।

3 प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय के अनुपात मे 1961 की तुलना मे 1981 मे कमी आयी है ।

अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिवासों मे सरचनात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ रही है । इससे उनमे न केवल गतिशीलता आई है अपितु उनका आर्थिक आधार भी सुदृढ हो रहा है । निश्चय ,ही इससे स्थानिक एव क्षेत्रीय समायोजन एव आर्थिक विकास मे वृद्धि होगी ।

REFERENCES

1 Berry, B.J L., (1967), **Geography of Market Centres and Retail Distribution**, Englewood Cliffs . Prentice - Hall

2 Berry, B J.L and Garrison, W L (1958), The Functional Bases of the Central Place Hierarchy, **Economic Geography**, 34, 145-54

3 Breese, G (1963), Urban Development Problems in India, **A.A.A.G.** 53, 253 - 265

4 Brush, J.E (1953), The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, **Geographical Review**, 43, 380 - 402

5 Brush, J.E. & Bracy, H.E. (1955), Rural Service Centres in Southwestern Wisconsin and England, **Geog. Rev.**, 45, 4, 559-69

6 Christaller, W. (1966), **Central Place in Southern Germany** (Translated by C.W. Baskin), New Jersey : Englewood Cliffs

7. Cooley, C.H. (1984) **The Theory of Transportation**, Publication the American Economic Association, 9, 1 - 48

8 Dickinson, R E. (1932), The Distribution and Function of the Smaller Urban Settlement of East Anglia, **Geography**, 17, 19-31

9 Folke, Steen, (1968) Central Place System and Spatial Interaction, in Jacobsen, N.K and Johnston, R.H. (eds), 21st Intl Geogr Cong Collected paper - 57

10 Galpin, G.J (1915), The Social Anatomy of An Agricultural Community, **Research Bulletin in Agricultural experiment Station** University of Wisconsin, Madison, 34

11 Jefferson, M. (1939), The Law of Primate City, **Geog. Rev.** 39, 226 - 232

12 Mayfield, R C. (1967), A Central Place Hierarchy in Northern India, **Quantitative Geography** Pt.1 Economics and Cultural Topics, Illinois, 120 - 166

13. Misra K.K. (1981) **System of Service Centres in Hamirpur District**, U P , India, unpublished Ph.D. thesis, Bundelkhand University, Jhansi.

14. Smails, A.W. (1944), The Urban Hierarchy of England and Wales **Geography**, vol. 29, pp 41-51

15. Singh, G. (1973), **Service Centres : Their Function and Hierarchy**, Ambala District Punjab, India, unpublished thesis, Cincinati University U.S A.

16. Von Thunen, H (1826), Deriso-lierte state in Bezichung Hug landwirts chaft and National Konomic, Rostock Translated by Warteburgh C M **As Von Thunen's Isolated State**, London Oxford University Press.

16. Woodcock, R C and Bailey M J (1928), **Quantitative Geography,** Eastover Macdonald and Evans

अध्याय 5

सामाजिक - आर्थिक कारक एवं रूपान्तरण

विगत अध्याय मे सेवा केन्द्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया है और उसके सामाजिक व आर्थिक आधारों के परिवर्तन को स्प्ष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । प्रस्तुत अध्याय मे अधिवास तत्र एव सेवा केन्द्रों मे होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों का सह - सम्बन्ध स्प्ष्ट करने का प्रयास किया गया है ।

इस **अध्याय** मे मुख्य रूप से सामाजिक कारक के अन्तर्गत जनसख्या वृद्धि, नगरीकरण एव शिक्षा तथा आर्थिक कारकों के अन्तर्गत जनसख्या व्यवसाय प्रतिरूप, भूमि उपयोग, कृषि प्रतिरूप इत्यादि का विश्लेषण किया गया है । कुछ सम्बान्धत सकल्पनाओ का परीक्षण भी किया गया है ।

सामाजिक रूपान्तरण

जनसख्या जोन्स (1981) तथा क्लार्क (1972) ने जनसख्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करते हुये स्पष्ट किया है कि समस्त सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का आधार जनसख्या ही है । जनसख्या वह सदर्भ बिन्दु है जिससे अन्य समस्त तत्वों का निरीक्षण किया जाता है तथा उन्हे अर्थ प्रदाना किया जाता है । यह समस्त सामाजिक आर्थिक विश्लेषण मे "फोकस" का कार्य करती है । चान्दना (1980) का विचार है किसी क्षेत्र की जनसख्या वृद्धि उस क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक विकास, सास्कृतिक पृष्ठि भूमि, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनैतिक अवधारणाओं की सूचक होती है ।

जनसख्या वृद्धि अध्ययन क्षेत्र मे सर्वप्रथम जनगणना का श्रीगणेश । फरवरी 1869 मे हुआ। इस गणना मे जनपद की जनसख्या 782,681 आकी गयी । किन्तु जनसख्या का विधिवत कार्य वर्ष 1901 मे प्रारम्भ हो सका । इस जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या 908,105 थी जिसमे 443,994 पुरुष 464,111 महिलाए थी । आधुनिकतम (1981) जनगणना के अनुसार यह जनसख्या बढकर 1,806,833 हो गयी है जिसमे पुरुषों की सख्या

908,050 है । इन आठ दशकों मे जनसख्या लगभग दुगुनी हो गयी है, जैसा कि सारिणी (सख्या 5 ।) से स्पष्ट है । 80 वर्षों मे 98 9 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट होता है कि वार्षिक वृद्धि दर केवल । 23 प्रतिशत है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । किन्तु विभिन्न दशकों की जनसख्या के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे जनसख्या की वृद्धि समान रूप से नहीं हुई है । सबसे विशिष्ठ तथ्य यह है कि पुरूषों की तुलना मे महिलाओं की सख्या लगभग सभी दशकों मे अधिक रही है । यह इस बात का स्पष्ट सकेत है कि अध्ययन क्षेत्र जन प्रवास समस्या से पूर्णत प्रभावित हे । प्रारम्भ से ही गरीबी एव पिछडेपन के कारण इस क्षेत्र की कार्यशील जनसख्या बडे बडे महानगरों बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मध्यम श्रेणी के नगरों - अमृतसर, लुधियाना, कानपुर, लखनऊ इत्यादि की ओर प्रवासित होती रहती है । इस क्षेत्र से कुछ जनसख्या का प्रवास पूर्वी द्वीप समूह - जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन तथा बर्मा (मुख्य रूप से रगून) की ओर भी हुआ (नेविल, ।904) । इस प्रवास के फलस्वरूप पुरूषों की सख्या पूर्ण रूप से प्रभावित हुई क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया मे पुरूषों का ही योगदान था ।

जनसख्या वृद्धि के विश्लेषण की दृष्टि से वर्ष ।92। विभाजक रेखा का कार्य करता है, क्योंकि इसके पूर्व हमारे प्रदेश की जनसख्या मे निरनतर ह्रास हुआ और अध्ययन क्षेत्र उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा । वर्ष ।90। - 2। मुख्य रूप से बीमारी, महामारी, सूखा, बाढ, अकाल तथा विश्व युद्ध के भयकर परिणामों से प्रभावित रहा । जैसा कि (सारिणी 5 2) से स्पष्ट है वर्ष ।90। - ।। तथा ।9।। - 2। मे अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या मे क्रमश । 4 तथा 4 9। प्रतिशत ह्रास हुआ । इस ह्रास के मुख्य कारण इन्फलुएन्जा, चेचक तथा हैजा जैसी महामारियाँ थी, जिससे समूचा देश प्रभावित हुआ । इन महामारियों के साथ साथ मानसून की असफलता से उत्पन्न अकाल से भी जनसख्या का ह्रास हुआ, क्योंकि भुखमरी के कारण जनसख्या का एक महत्वपूर्ण वर्ग प्रभावित हुआ ।

अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक स्थिति मे भी ।92। के बाद से पर्याप्त अन्तर आया । ।92। - 3। मे जनपद की जनसख्या मे लगभग 6 0 प्रतिशत (5 98 प्रतिशत) की वृद्धि

सारिणी संख्या 5.1 : प्रतापगढ जनपद में जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	दशक की विभिन्न व्यक्ति मे	प्रतिशत
1901	443,994	464,111	908,105		
1911	435,152	460,127	895,299	-12806	-1 14
1921	415,491	435,261	850,753	+44527	-4 91
1931	440,051	461,567	901,618	+50866	+5 98
1941	527,429	509,067	1,036,496	+134878	+14 96
1951	542,763	564,042	1,106,805	+70309	-6 78
1961	607,165	642,031	1,252,196	+145,391	+13 14
1971	705,726	716,981	1,422,707	+170,511	+13 62
1981	898,783	908,050	1,806,833	+384126	+27 0

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1951-81

सारिणी सख्या 5.2 अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धि की दिशा

वर्ष	प्रतापगढ जनपद की जनसख्या का प्रतिशत	उत्तर प्रदेश की जनसख्या का प्रतिशत	भारत की जनसख्या का प्रतिशत
1901			
1911	1 4	-0 07	5 93
1921	-4 91	-3 08	-0 31
1931	+5 98	6 08	11 0
1941	+14 96	13 57	14 22
1951	-6 78	11 83	13 31
1961	+13 14	16 66	21 64
1971	+13 66	19 78	24 80
1981	+27 0	25 59	25 0

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1951-81

हुई । ठीक इसी प्रकार 1931 - 41, 1941 - 51, 1951 - 61, 1961 - 71 तथा 1971 - 81 मे जनसख्या मे लगातार वृद्धि हुई । इसका मुख्य कारण मृत्युदर मे कमी है । साथ ही स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं मे सुधार के कारण महामारी से होने वाली मृत्यु पर नियन्त्रण पा लेने के कारण जनसख्या की वृद्धि दर पर अनुकूल प्रभाव पडा । अध्ययन क्षेत्र ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश तथा सम्पूर्ण देश मे मृत्युदर मे कमी आई है । जन्मदर बढी है । अस्तु जनसख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । सारिणी सख्या 5 2 से स्पष्ट है कि(चित्र सख्या 5 1) विगत् दशक 1971 - 81 मे अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या की वृद्धि (27 0 प्रतिशत), प्रदेश (25 59 प्रतिशत) तथा राष्ट्र की वृद्धि (25 0 प्रतिशत) से किचित अधिक थी ।

वृद्धि - वितरण प्रतिरूप भौगोलिक दृष्टि से यह देखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि लघु प्रादेशिक स्तर पर जनसख्या वृद्धि का प्रतिरूप क्या है । इस दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर कुल जनसख्या वृद्धि का प्रेक्षण किया जा सकता है । यह सारिणी (सख्या 5 3) 1961 - 71 तथा 1971 - 81 की जनसख्या वृद्धि दिखाने के साथ साथ विगत् दो दशकों (1961 - 81) मे विकास खण्ड स्तर पर हुई जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत भी दर्शाती है ।

जिन विकास खण्डों मे जनसख्या वृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक है वे विकास खण्ड ऐसे है जहाँ पर नगरीय जनसख्या पाई जाती है । सदर (53 0 प्रतिशत) तथा कुन्डा (54 9 प्रतिशत) विकास खण्ड इसी कोटि मे है ।

जिन विकास खण्डों मे जनसख्या की वृद्धि 40 से 50 प्रतिशत के बीच हुई है वे मान्धाता (47 0 प्रतिशत), कालाकाकर (46 1 प्रतिशत), बाबागज (40 9 प्रतिशत), बिहार (48 6 प्रतिशत), रामपुर खास (40 3 प्रतिशत), गौरा (43 1 प्रतिशत), शिवगढ (44 4 प्रतिशत) तथा आसपुर देवसरा (44 2 प्रतिशत) है ।

कुछ ऐसे विकास खण्ड है जिसमे जनसख्या वृद्धि विगत् दो दशकों मे 30 से 40 प्रतिशत के बीच है । उनमे मगरौरा (39 6 प्रतिशत), सागीपुर (32 5 प्रतिशत), सडवा चन्द्रिका (34 0

सारिणी संख्या 5 3 जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत मे)

विकासखण्ड का नाम	1961-71	1971-81	1961-81	20 वर्षों मे औसत वृद्धि
सदर	14 9	33 1	53 1	2 7
लक्ष्मणपुर	12 8	25 0	38 2	1 91
मानधाता	12 9	28 2	47 5	2 4
स0 चन्द्रिका	10 2	21 6	34 0	1 7
सागीपुर	27 6	20 9	32 5	1 6
कुन्डा	24 0	25 0	54 9	2 7
कालाकाकर	13 8	28 3	46 1	2 3
बाबागज	13 4	28 2	40 9	2 1
बिहार	14 7	29 6	48 6	2 4
रामपुरखास	9 3	28 4	40 3	2 0
पट्टी	15 3	28 1	47 7	2 4
गौरा	15 6	23 8	43 1	2 2
शिवगढ	12 1	26 1	41 4	2 1
मगरौरा	12 5	24 1	39 6	2 0
आसपुर देवसरा	14 32	26 1	44 2	2 2

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971
जिला साख्यकी पत्रिका, 1984

प्रतिशत) तथा लक्ष्मणपुर (38 2 प्रतिशत) है ।

विगत दो दशकों मे (1961 - 81) मे अध्ययन क्षेत्रकी वार्षिक वृद्धि 2 2 प्रतिशत थी । जिन विकास खण्डों मे वार्षिक दर इससे अधिक थी वे सदर, मानधाता, कालाकाकर, बिहार तथा पट्टी है । आसपुर देवसरा तथा गौरा की वृद्धि दर क्षेत्र के वृद्धि दर के बराबर है । मगरौरा, रामपुरखास, बाबागज, सागीपुर, कुन्डा, सडका चन्द्रिका तथा लक्ष्मणपुर की विकास दर क्षेत्र के विकास दर से कम है । विकास खण्ड स्तर पर वृद्धि दर चित्र 5 2 के माध्यम से प्रदर्शित की गयी है ।

ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि का (सारिणी सख्या 5 4) अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सदर, कुन्डा, पट्टी, सडवा चन्द्रिका और कालाकाकर मे जो वृद्धि मे अधिकता है वह नगरीय जनसख्या के कारण है । ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि अधिकाश विकासखण्ड मे समान है ।

नगरीकरण की प्रवृत्ति नगरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रकिया है जो सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का द्योतक हे । अनेक विद्वान तो यह मानते है कि नगरीकरण की तीव्रता विकास का परिचायक है (मिश्रा, 1984) ।

जब किसी स्थान विशेष पर जनसख्या का केन्द्रीकरण होने लगता है और अकृषिकृत कार्यो मे वृद्धि होने लगती है तथा जनसख्या का अधिकाश भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो पर आश्रित हो जाता है तो उसे नगरीकरण कहते है । उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष मे स्वतत्रता के पश्चात् इस प्रक्रिया मे तेजी से वृद्धि हुई है । इसके कई सामाजिक - आर्थिक कारण है जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर की कमी, शिक्षा मे वृद्धि, भूमि का असमान वितरण तथा नगर एव देहात की असमान मजदूरी प्रमुख है । क्षेत्र विशेष की आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से औद्योगीकरण, वाणिज्यिक व्यापार के अवसरों मे वृद्धि तथा यातायात के साधनों की सुगमता भी नगरीकरण की प्रवृत्ति को बल प्रदान करती है ।

अध्ययन क्षेत्र मे नगरीकरण की प्रक्रिया आधुनिक है । जैसा कि सारिणी सख्या 5 5 से स्पष्ट

सारिणी सख्या 5.4 . जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि(प्रतिशत मे)

विकासखण्ड का नाम	1961-71	1971-81	1961-81	
सदर,13 3	8 9	21 0	1 1	
लक्ष्मणपुर	12 8	25 0	38 2	1 9
मानधाता	12 9	28 2	47 5	2 4
सडवा चन्द्रिका	12 6	16 4	28 3	1 4
सागीपुर	13 5	20 9	32 5	1 9
कुन्डा	14 0	15 3	43 0	2 2
कालाकाकर	13 5	17 7	34 1	1 7
बाबागज	13 4	28 2	40 9	2 1
बिहार	13 8	29 6	48 6	2 4
रामपुरखास	14 1	28 4	40 3	2 0
पट्टी	13 2	20 5	38 9	1 9
गौरा	13 1	23 8	43 1	2 2
शिवगढ	12 3	26 1	41 4	2 1
मगरौरा	14 1	24 0	39 6	2 0
आसपुर देवसरा	14 3	26 1	44 2	2 2
जनपद	13 32	22 6		

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971
जिला साख्यकी पत्रिका, 1984

Ⓐ

TOTAL POPULATION GROWTH RATE
AT BLOCK LEVEL
(1961-81)

N

VERY HIGH	> 23
HIGH	22 - 22
MEDIUM	17 - 19
LOW	< 17

5 0 5 10
KM

Ⓑ

RURAL POPULATION GROWTH RATE
AT BLOCK LEVEL
(1961-81)

N

VERY HIGH	>17
HIGH	14-17
MEDIUM	11 - 14
LOW	< 11

5 0 5 10
KM
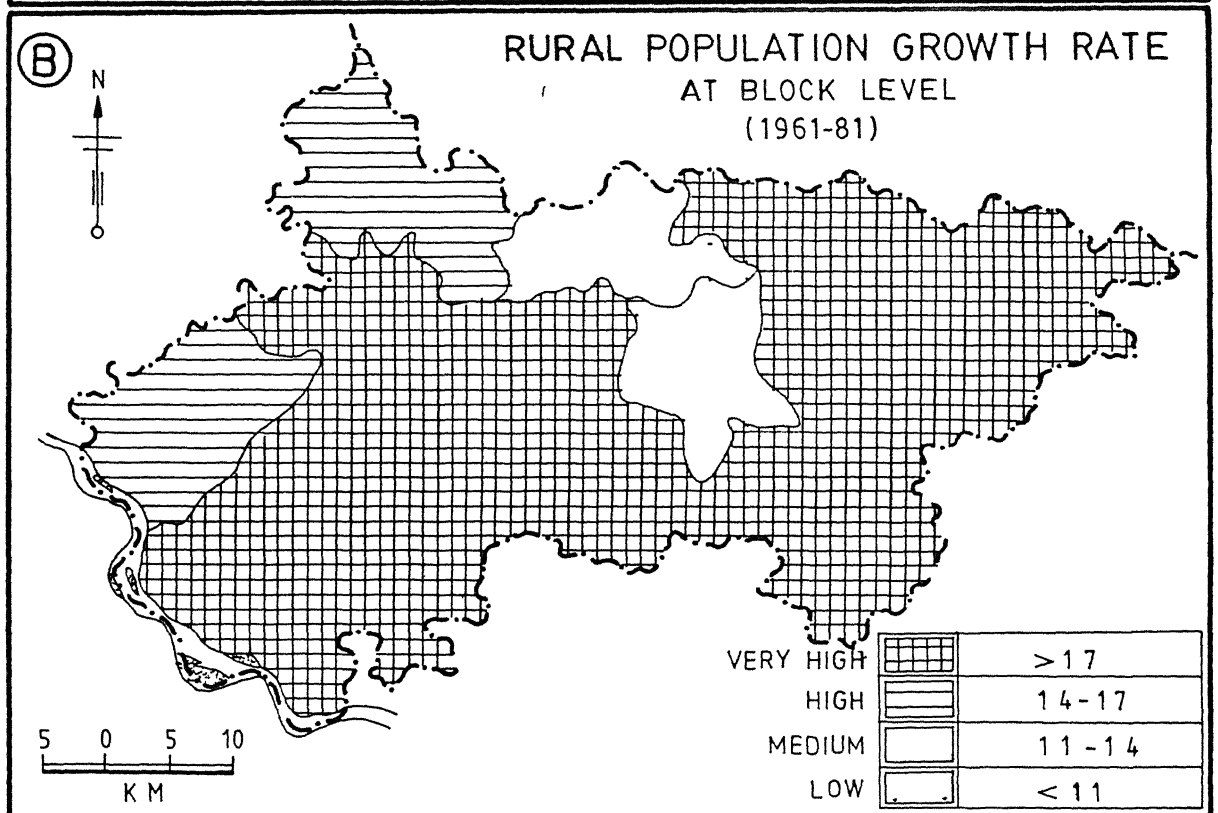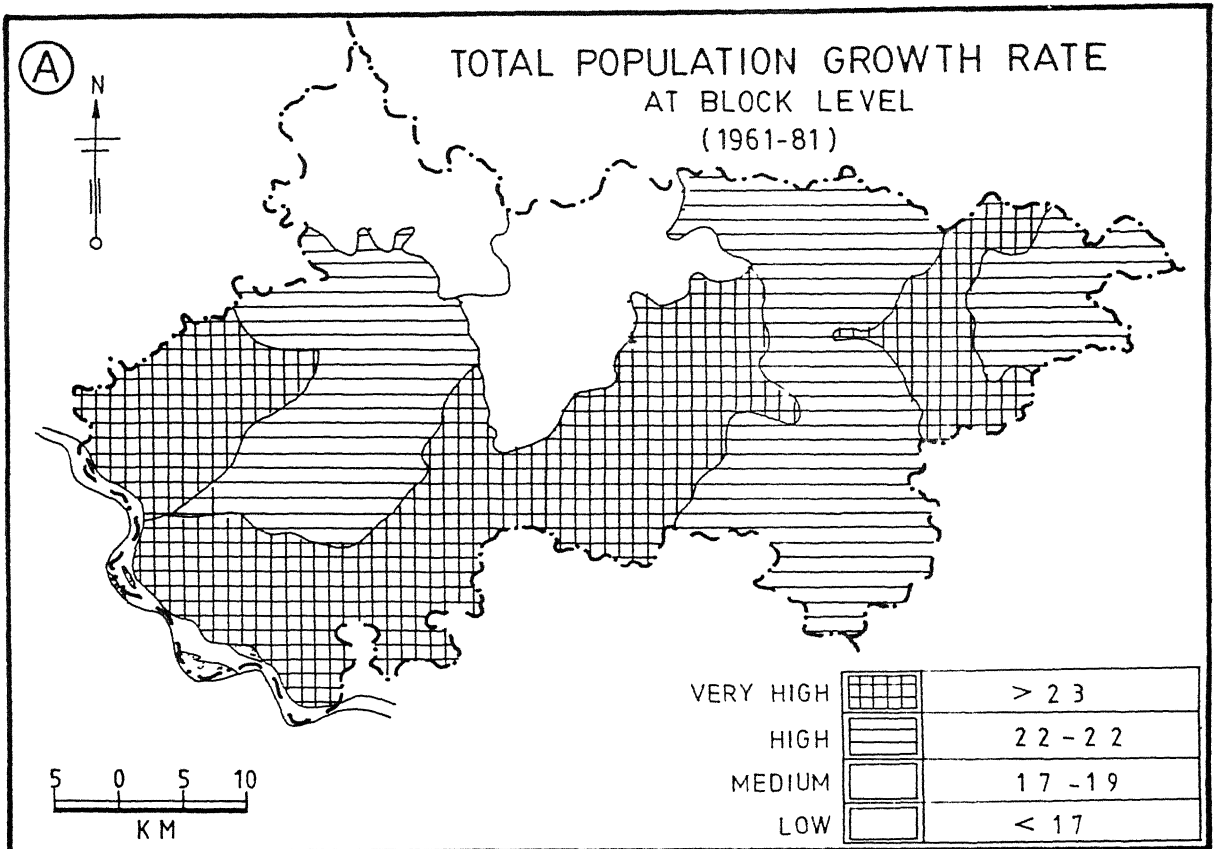
Fig 52

सारिणी संख्या 5 5 . प्रतापगढ़ जनपद मे ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की वृद्धि (प्रतिशत मे)

वर्ष	ग्रामीण जनसख्या	नगरीय जनसख्या
1901	-	-
1911	-1 2	-21 6
1921	-5 1	16 5
1931	5 8	28 6
1941	14 7	35 9
1951	6 7	17 1
1961	12 7	42 4
1971	13 3	30 4
1981	23 0	225 7

स्रोत भारतीय जनगणना 1961, 1971,1981

है कि सन् 1951 - 61 मे नगरीय आबादी मे 42 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 1961 - 71 मे यह वृद्धि 30 4 प्रतिशत रही है । वास्तव मे 1961 तथा 1971 मे केवल बेला प्रतापगढ (जो कि जिला मुख्यालय है) ही मात्र एक नगर था । इसका मुख्य कारण यह है कि सन् 1961 मे नगरीय परिभाषा को बहुत अधिक वैज्ञानिक बना दिया गया । फलस्वरूप मानिकपुर, कटरा मेदनीगज तथा कसबा प्रतापगढ जैसे छोटे नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी मे जा मिले । इस प्रकार 1961 - 71 मे केवल एक ही नगरीय अधिवास था । सन् 1981 मे पुन 6 नये अधिवासों के नगरीय अधिवासों की श्रेणी मे आ जाने के कारण नगरीय जनसख्या मे 225 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । नगरीयकरण की दृष्टि से ये पिछडा हुआ क्षेत्र है क्योंकि 1901 से 1971 तक नगरीय जनसख्या कुल जनसख्या का केवल 2 0 प्रतिशत या उसके आस पास ही रही है । किन्तु 1981 की जनगणला मे नये नगरीय अधिवासों के जुड जाने से तथा जनसख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण एव नगरीय अनुपात के अन्तर मे कुछ कमी आयी है तथा वर्तमान मे नगरीय जनसख्या का योगदान कुल जनसख्या का 5 0 प्रतिशत है । सारिणी सख्या 5 6 मे अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष के विभिन्न दशकों मे ग्रामीण नगरीय अनुपात को प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रदेश और देश की तुलना मे अध्ययन क्षेत्र मे कुल जनसख्या मे नगरीय जनसख्या का योगदान बहुत कम है । देश की नगरीय आबादी लगभग 24 प्रतिशत तथा प्रदेश मे 18 प्रतिशत है जबकि प्रतापगढ जनपद मे यह केवल 5 प्रतिशत है ।

साक्षरता साक्षरता जनसख्या की गुणात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है तथा सामाजिक परिवर्तनों के मूल्याकन मे इसका महत्वपूर्ण स्थान है (चान्दना 1980) । जनसख्या के साक्षरता अनुपात की वृद्धि जहाँ एक ओर सामाजिक परिवर्तन को इंगित करती है वहीं पर दूसरी ओर इससे आर्थिक परिवर्तन पर भी प्रभाव पडता है । साक्षरता के साथ दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है । जीवन मूल्य मे बदलाव होने लगता है तथा जनसख्या की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने लगती है । यदि हम 1901 - 81 के आँकडों पर दृष्टिपात करे तो यह स्पष्ट होगा कि साक्षरता के अनुपात मे प्रत्येक स्तर पर सतत् वृद्धि हो रही है । साक्षरता का सबसे

सारिणी 5 6 प्रतापगढ जनपद मे ग्रामीण एव नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	प्रतापगढ जनपद		उत्तर प्रदेश		भारत	
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
1901	97 9	2 1	88 9	11 1	89 2	10 6
1911	98 1	1 9	89 8	10 2	89 7	10 3
1921	98 1	1 9	89 4	10 6	88 8	11 2
1931	97 9	2 1	88 8	11 2	88 0	12 0
1941	97 7	2 3	87 4	12 4	86 1	13 9
1951	96 6	2 4	86 4	13 6	82 7	17 3
1961	98 3	1 7	87 2	12 8	82 0	18 0
1971	98 1	1 9	86 0	14 0	80 1	19 9
1981	94 9	5 1	82 0	18 0	76 3	23 73

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961
भारतीय जनगणना, 1961,1971, 1981

सारिणी संख्या 5 7 प्रतापगढ़ जनपद मे साक्षरता का तुलनात्मक स्वरूप

	प्रतापगढ जनपद			उत्तर प्रदेश			भारत		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	स्त्री	पुरूष	कुल
1901	6 1	0 1	3 1	-	-	-	9 83	0 60	5 35
1951	14 6	1 2	7 6	-	-	-	24.90	7 93	16 67
1961	24 8	3 2	13 7	-	-	-	34 44	12 95	24 0
1971	31 2	6 2	18 5	31 5	10 6	21 7	39 45	18 69	29 5
1981	38 9	8 8	23 8	38 76	14 0	27 2	46 74	24 88	36 2

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971, 1981

साख्यकीय डायरी, उत्तर प्रदेश 1986

सारिणी सख्या 5 8 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत (ग्रामीण)

विकास खण्ड का नाम	1961			1971			1981		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
सदर	17 4	2 7	20 0	37 1	8 9	23 1	45 8	13 0	29 4
लक्ष्मणपुर	13 6	1 5	15 2	34 0	5 4	19 2	40 5	7 5	23 7
मानधाता	12 8	1 6	14 3	34 7	6 4	20 1	42 1	8 5	25 0
स0 चन्द्रिका	12 6	1 6	14 2	35 1	5 4	19 6	42 6	12 9	25 0
सागीपुर	11 4	1 6	13 0	26 1	3 9	15 0	33 3	3 3	19 3
कुण्डा	9 8	1 5	11 3	28 0	6 8	17 5	33 1	12 2	22 7
कालाकाकर	9 2	0 8	10 4	23 4	4 7	14 3	45 1	4 9	25 2
बाबागज	9 9	1 3	11 21	24 9	4 3	14 5	21 8	6 0	18 8
बिहार	10 6	0 9	11 6	28 7	5 3	16 9	35 3	10 4	23 0
रामपुरखास	9 1	0 8	9 9	24 0	3 5	13 7	28 7	5 2	17 0
पट्टी	11 8	0 7	13 2	31 5	6 2	18 9	40 9	7 0	23 6
गौरा	11 5	1 0	12 5	31 6	4 2	17 7	371	6 6	21 6
शिवगढ	13 1	1 5	9 7	31 8	5 1	20 0	41 2	7 8	24 1
मगरौरा	12 3	1 3	12 6	36 4	5 4	18 8	37 0	6 8	21 8
आसपुर देवसरा	11 7	1 5	13 2	32 0	6 2	19 2	39 9	7 2	23 3

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961, 1971, 1981

महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुरूषों के साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता मे वृद्धि हो रही है । अध्ययन क्षेत्र मे 1901 - 81 मे साक्षरता 3 1 प्रतिशत से 23 8 प्रतिशत हो गयी । किन्तु यह वृद्धि प्रदेश एव देश की तुलना मे कम है । स्त्रियों एव पुरूषों की साक्षरता का अनतर भी इसकी पुष्टि करता है । पुरूषों की साक्षरता 1901 - 81 मे 6 0 प्रतिशत से बढकर 39 0 प्रतिशत हो गयी जबकि स्त्रियों की साक्षरता 0 1 प्रतिशत से 8 8 प्रतिशत ही हुयी है । स्त्रियों की साक्षरता का यह अनुपात प्रदेश (14 0 प्रतिशत) और राष्ट्र (25 0 प्रतिशत) की तुलना मे बहुत कम है । साक्षरता मे वास्तविक वृद्धि स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई । जबकि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर शिक्षा सस्थाए स्थापित की गयी ।

अध्ययन क्षेत्र मे साक्षरता अनुपात का वितरण प्रतिरूप मानचित्र (5 3) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस मार्नचित्र से स्पष्ट है कि सदर विकास खण्ड मे जिला मुख्यालय होने के कारण साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है । इस मानचित्र मे पुरूषों एव स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत का वितरण भी अलग अलग मानचित्रों मे दिखाया गया है । पुरूषों की साक्षरता के अनुपात के वितरण मे अधिक विषमता नहीं पायी जाती है । पश्चिम मे रामपुरखास और बाबागज विकास खण्डों को छोडकर शेष अन्य विकासखण्डों मे वितरण प्रतिरूप लगभग समान है । स्त्रियों की साक्षरता के वितरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि महिलाओं मे साक्षरता की बहुत कमी है । जबकि महिलाओं की साक्षरता को सामाजिक विकास तथा विकास स्तर के उन्नयन का प्रतीक माना जाता है । महिलाओं की साक्षरता का औसत 7 9 प्रतिशत है । 15 विकास खण्डों मे से दस विकासखण्डों मे महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत इस औसत से भी कम है । मानधाता तथा बिहार विकास खण्डों मे स्त्रियों की साक्षरता 7 9 तथा 10 7 के बीच है । केवल तीन ऐसे विसकासखण्ड है जिनकी साक्षरता 10 7 से 13 6 प्रतिशत के बीच है । ये विकासखण्ड कालाकाकर, सदर तथा सडवा चन्द्रिका है ।

महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुरूषों के साथ साथ स्त्रियों की साक्षरता मे वृद्धि हो रही है । अध्ययन क्षेत्र मे 1901 - 81 मे साक्षरता 3 1 प्रतिशत से 23 8 प्रतिशत हो गयी । किन्तु यह वृद्धि प्रदेश एव देश की तुलना मे कम है । स्त्रियों एव पुरूषों की साक्षरता का अनतर भी इसकी पुष्टि करता है । पुरूषों की साक्षरता 1901 - 81 मे 6 0 प्रतिशत से बढकर 39 0 प्रतिशत हो गयी जबकि स्त्रियों की साक्षरता 0 1 प्रतिशत से 8 8 प्रतिशत ही हुयी है । स्त्रियों की साक्षरता का यह अनुपात प्रदेश (14 0 प्रतिशत) और राष्ट्र (25 0 प्रतिशत) की तुलना मे बहुत कम है । साक्षरता मे वास्तविक वृद्धि स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुई । जबकि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर शिक्षा सस्थाए स्थापित की गयी ।

अध्ययन क्षेत्र मे साक्षरता अनुपात का वितरण प्रतिरूप मानचित्र (5 3) द्वारा प्रदर्शित किया गया है । इस मार्नचित्र से स्पष्ट है कि सदर विकास खण्ड मे जिला मुख्यालय होने के कारण साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है । इस मानचित्र मे पुरूषों एव स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत का वितरण भी अलग अलग मानचित्रों मे दिखाया गया है । पुरूषों की साक्षरता के अनुपात के वितरण मे अधिक विषमता नहीं पायी जाती है । पश्चिम मे रामपुरखास और बाबागज विकास खण्डों को छोडकर शेष अन्य विकासखण्डों मे वितरण प्रतिरूप लगभग समान है । स्त्रियों की साक्षरता के वितरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि महिलाओं मे साक्षरता की बहुत कमी है । जबकि महिलाओं की साक्षरता को सामाजिक विकास तथा विकास स्तर के उन्नयन का प्रतीक माना जाता है । महिलाओं की साक्षरता का औसत 7 9 प्रतिशत है । 15 विकास खण्डों मे से दस विकासखण्डों मे महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत इस औसत से भी कम है । मानधाता तथा बिहार विकास खण्डों मे स्त्रियों की साक्षरता 7 9 तथा 10 7 के बीच है । केवल तीन ऐसे विसकासखण्ड है जिनकी साक्षरता 10 7 से 13 6 प्रतिशत के बीच है । ये विकासखण्ड कालाकाकर, सदर तथा सडवा चन्द्रिका है ।

आर्थिक रूपान्तरण

व्यवसायिक सरचना   कार्यरत जनसख्या के व्यवसायिक वर्गो का विश्लेषण कर किसी क्षेत्र का आर्थिक आधार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है । सामान्यत यदि किसी क्षेत्र मे कार्यरत जनसख्या का अनुपात अधिक होता है तो जनसख्या की निर्भरता कम होती है और प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक स्तर मे निरन्तर वृद्धि होती है । यह महत्वपूर्ण है कि जनगणना के विभिन्न दशकों मे कार्यरत जनसख्या की परिभाषा तथा व्यवसायिक सरचना की परिभाषा मे बदलाव होता रहा है । यही कारण है कि, किन्हीं दो दशकों की व्यवसायिक सरचना और कार्यरत जनसख्या का तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव नहीं हो पाता । वर्ष 1981 मे व्यवसायिक संरचना के विश्लेषण के लिये मुख्य रूप से जनसख्या को तीन वर्गों मे विभक्त किया गया है

1 मुख्य कर्मकर

2 सीमान्त कर्मकर

3 बेराजगार

एक व्यक्ति यदि वर्ष के अधिकाश समय मे (कम से कम 183 दिन) किसी आर्थिक क्रिया मे लगा हुआ था तो उसे मुख्य कर्मकर माना गया । किन्तु एक व्यकित जो वर्ष के कुछ महीने तक ही कार्य मे लगा था उसे सीमान्त कर्मकर माना गया तथा वह व्यक्ति जो वर्ष भर किसी भी आर्थिक उत्पादन की प्रकिया मे नहीं रह पाया है उसे कार्य न करने वाले की श्रेणी मे रखा गया है ।

कार्य की परिभाषा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आर्थिक उत्पादन को कार्य माना गया हे । यह शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, अथवा शारीरिक व मानसिक दोनों ही हो सकता है । कार्य की सीमा के अन्तर्गत केवल वास्तविक कार्य को ही नहीं अपितु प्रभावी निरींक्षण एव निदेशन को भी इसके अन्तर्गत रखा गया है । कार्यरत जनसख्या को 4 भागों मे वर्गीकृत किया गया है   -

1 कृषक

2 कृषि श्रमिक

3 पारिवारिक उद्योग एव

4 अन्य कर्मकर

प्रस्तुत विश्लेषण मे कृषक तथा कृषि श्रमिकों को प्राथमिक व्यवसाय के अन्तर्गत रखा गया है तथा पारिवारिक उद्योग एव अन्य कार्यो. मे लगी हुई जनसख्या को क्रमश सुविधा के अनुसार द्वितीयक एव तृतीयक वर्गो के अन्तर्गत रखा गया है । इन तीनों वर्गो के अन्तर्गत प्रतापगढ जनपद की कार्यरत जनसख्या को सारणी सख्या 5 9 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारणी से अध्ययन क्षेत्र की कार्यरत जनसख्या का तीन दशकों (1961 - 81) का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है । इस सारणी से स्पष्ट है कि कृषि ही आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक जनसख्या कृषि पर ही आधारित है । यद्यपि विगत दशकों की तुलना मे कृषि मे कार्यरत जनसख्या मे ह्रास हुआ है, क्योंकि वष 1961 मे इसके अन्तर्गत 87 0 प्रतिशत लोग लगे हुये थे । जबकि वर्ष 1981 मे यह प्रतिशत घटकर 84 5 प्रतिशत हो गया है । किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि मे लगी जनसख्या के अनुपात का ह्रास द्वितीयक व्यवसाय मे नहीं परिलक्षित होता है । जैसा कि स्पष्ट है कि द्वितीयक व्यवसाय मूलत औद्योगिक है, किन्तु इसमे केवल 3 0 प्रतिशत जनसख्या को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है । सबसे प्रमुख बात यह है कि द्वितीयक व्यवसाय के अनुपात मे भी ह्रास हुआ है क्योंकि वर्ष 1961 - 81 मे यह 6 2 प्रतिशत से घट कर केवल 2 9 प्रतिशत रह गया है । स्पष्टतया औद्योगीकरण की प्रवृत्ति को उचित महत्व नहीं प्राप्त हुआ । प्राथमिक व्यवसाय का ह्रास तृतीयक व्यवसाय की वृद्धि मे परिलक्षित होता है । यह वे कर्मकर है जो मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक व्यापार, वाणिज्य, सेवा तथा यातायात सम्बन्धित कार्यों मे कार्यरत है । विगत तीन दशकर्से मे तृतीयक व्यवसाय मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । वर्ष 1961 मे केवल6 60 प्रतिशत लोग अन्य सेवाओं (तृतीयक व्यवसाय) मे लगे थे किन्तु वर्ष 1981 मे यह अनुपात दुगुने से अधिक (13 7 प्रतिशत) हो गया ।

विकास खण्ड स्तर पर जनसख्या के व्यवसायिक सरचना का वितरण सारणी सख्या 5 10 मे

सारिणी सख्या 5 9 प्रतापगढ जनपद मे व्यवसायिक वर्गो मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत

व्यावसायिक वर्ग	1961	1971	1981
प्राथमिक व्यावसाय	87 1	87 6	84 5
द्वितीयक व्यावसाय	6 3	4 5	2 9
तृतीय व्यावसाय	6 7	7 9	13 7

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

सारिणी संख्या 5 10 जनपद मे विकास खण्डवार जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत)

विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक क्रियाये			द्वितीयक क्रियाये			तृतीयक क्रियाये		
	1961	1971	1981	1961	1971	1981	1961	1971	1981
सदर	76 6	75 6	84 0	7 6	7 9	3 3	15 8	16 5	12 7
लक्ष्मणपुर	88 1	89 3	88 5	5 9	4 5	2 7	6 0	6 2	8 8
मानधाता	90 0	90 8	87 5	5 6	4 0	4 1	4 4	5 2	8 4
स0 चन्द्रिका	87 9	88 8	89 4	6 7	3 9	2 2	5 4	7 2	8 4
सागीपुर	90 0	93 9	92 9	5 0	2 6	2 6	4 2	3 5	4 5
कुण्डा	85 1	87 4	90 0	7 5	4 7	2 1	7 4	7 9	6 9
कालाकाकर	81 7	890 4	89 2	8 6	4 3	3 6	9 7	5 3	7 2
बाबागज	88 9	91 1	91 7	5 6	3 8	2 0	5 4	5 1	5 1
बिहार	89 3	90 9	86 8	6 5	4 5	3 5	4 2	4 6	9 7
रामपुरखास	89 4	91 6	92 9	5 8	3 3	2 0	4 8	5 1	5 1
पट्टी	90 0	88 2	91 6	5 0	4 3	1 7	5 0	7 5	6 7
गौरा	92 8	88 5	88 4	4 1	4 3	3 3	3 4	7 5	8 3
शिवगढ	89 8	85 4	86 0	4 7	4 1	2 1	5 5	10 5	11 9
मगरौरा	90 4	89 2	89 1	5 0	3 2	2 5	4 6	7 6	8 4
आसपुर देवसरा	90 6	93 2	91 7	4 3	2 7	0 9	3 1	5 1	7 4

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक, 1961-81

प्रस्तुत किया गया है । यह सारणी वर्ष 1961 तथा 1981 की स्थिति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है । इस सारणी से जहाँ प्राथमिक व्यवसाय अथवा कृषि का वर्चस्व, आर्थिक आधार के रूप मे स्पष्ट है, वहीं दूसरी ओर द्वितीयक व्यवसाय (पारिवारिक एव अन्य उद्योग) की कमी तथा तृतीयक व्यवसाय मे अपेक्षाकृत अभिवृद्धि भी दिखाई पडती है । विकासखण्ड स्तर पर व्यवसायिक सरचना के प्रतिरूप का चित्र सख्या 5 4 तथा 5 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह दोनों रेखाचित्र वर्ष 1961 तथा 1981 की स्थिति को विकास खण्ड स्तर पर दर्शाने का प्रयत्न करते है । 1961 तथा 1981 की व्यवसायिक सरचना मे दो महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट दिखायी देते है

1 प्रत्येक विकासखण्ड मे द्वितीयक प्रकार के व्यवसाय मे लगी जनसख्या के अनुपात मे ह्रास हुआ है ।

2 तृतीयक प्रकार के व्यवसाय मे अपेक्षाकृत आनुपातिक वृद्धि हुई है । तृतीयक व्यवसाय पर निर्भरता 4 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के मध्य है । इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था मे विविधता की प्रक्रिया प्रारम्भ है किन्तु गति बहुत धीमी है । विविधता की इस प्रक्रिया मे तृतीयक प्रकार के व्यवसाय अधिक व महत्वपूर्ण होंगे । सम्भवतया इनसे ही नगरीकरण की प्रक्रिया को आधार मिलेगा (रजा, 1981 तथा मिश्रा, 1990) ।

भूमि उपयोग - व्यवसायिक सरचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि अध्ययन क्षेत्र का मुख्य आर्थिक आधार है । इस आधार को स्पष्ट करने के लिये कृषि उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

मानव सभ्यता के आरम्भ से ही भूमि का उपयोग कृषि उत्पादन के लिये होता रहा है । वास्तव मे यह सबसे बडी प्राकृतिक सम्पदा है । भूगोल विशेषज्ञों ने भूमि उपयोग के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण कर इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया है । इस परम्परा मे कई पाश्चात्य एव भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने योगदान किया है । इनमे प्रो0 इनायदी (1964), प्रो0 स्टैम्प (1962) तथा प्रो0 शफी (1960, 1972) के कार्य विशेष रूप

PRATAPGARH DISTRICT
SECTORAL COMPOSITION OF WORKERS
AT BLOCK LEVEL
(1961)
N
PRIMARY WORKERS
SECONDARY WORKERS
TERTIARY WORKERS
4 0 4 8 12
KM
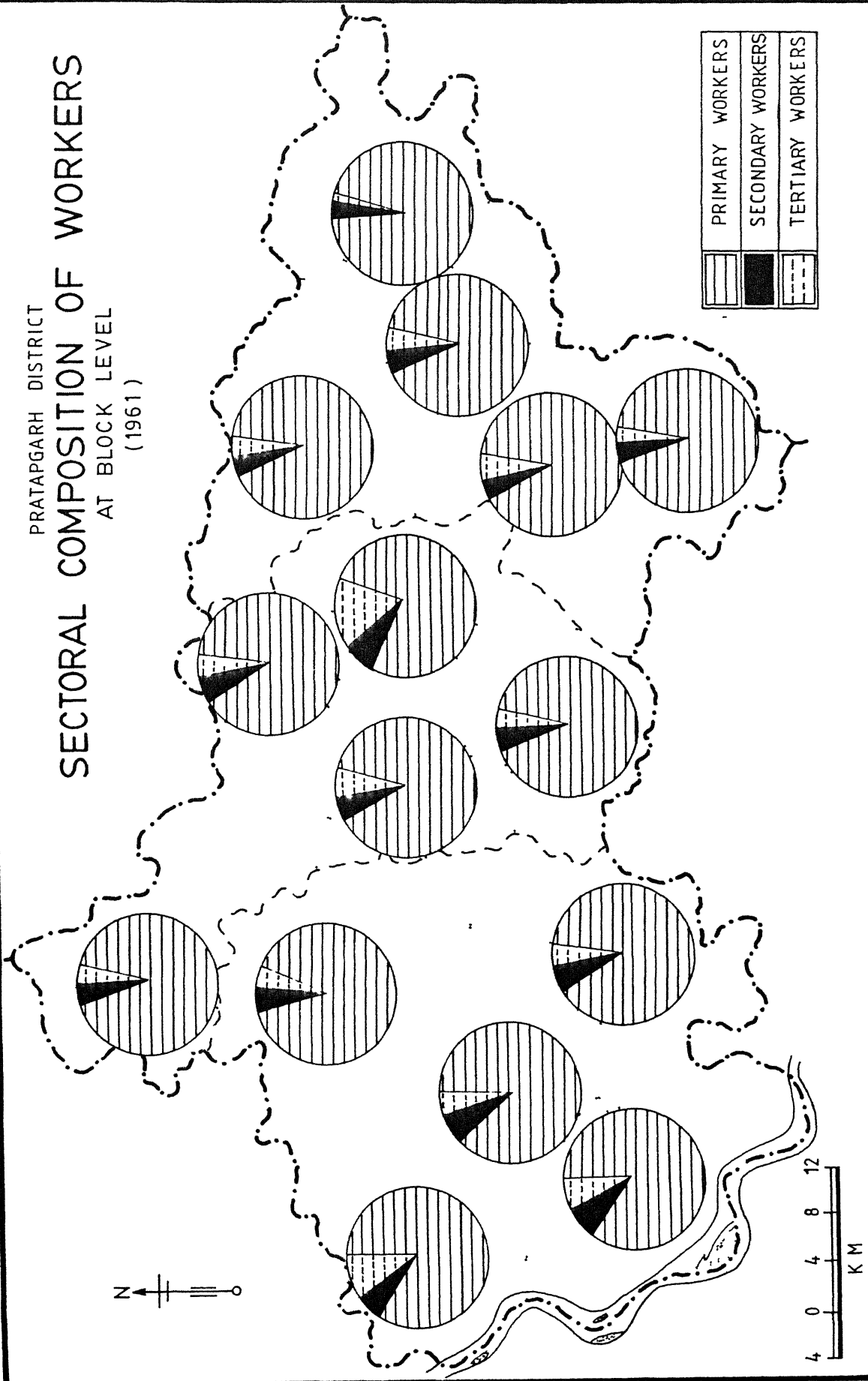
Fig 54

PRATAPGARH DISTRICT
SECTORAL EMPLOYMENT OF WORKERS
AT BLOCK LEVEL
(1981)
N
PRIMARY WORKERS
SECONDARY WORKERS
TERTIARY WORKERS
4 0 4 8 12
KM
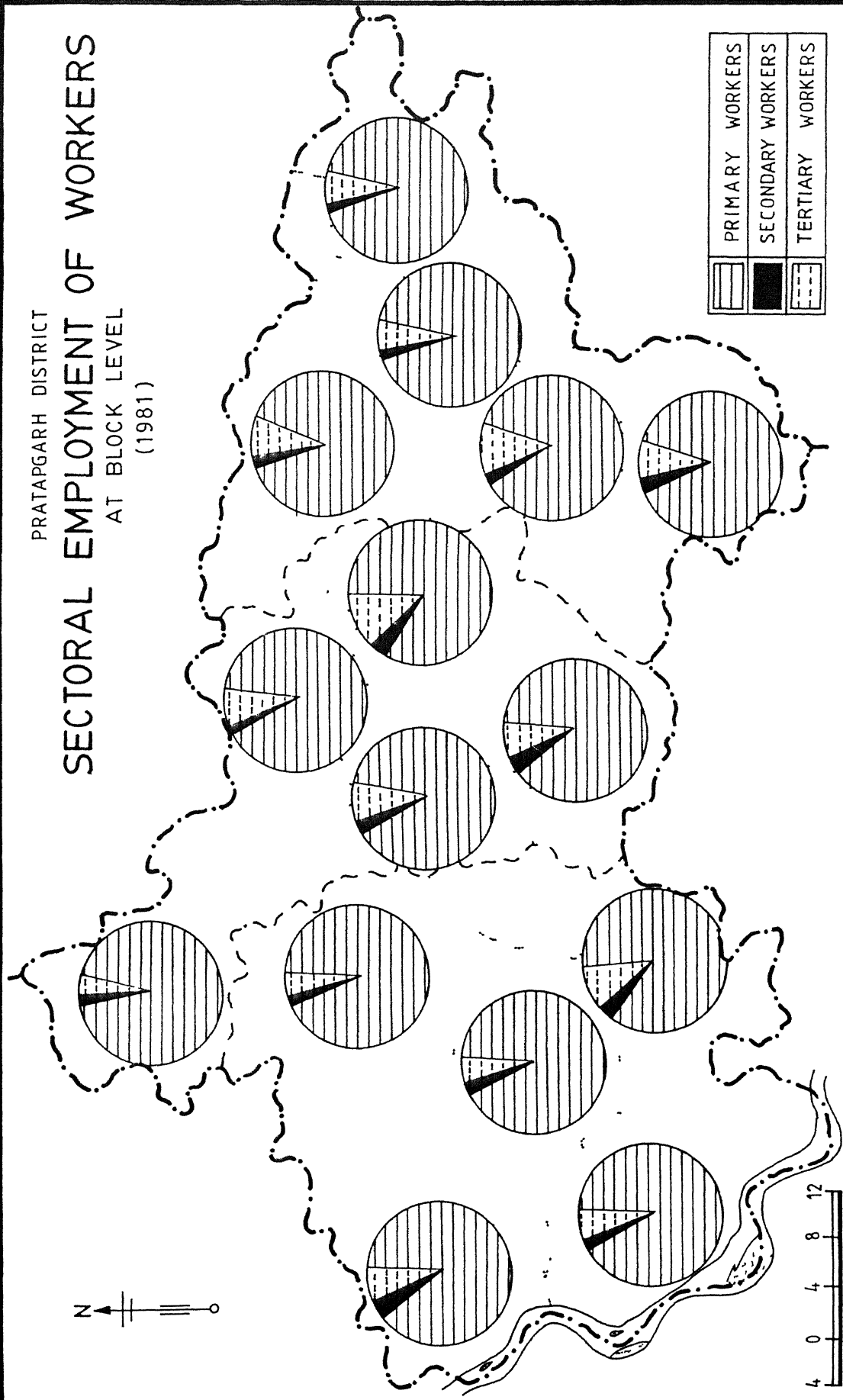
Fig 55

से उल्लखनीय है ।

अध्ययन क्षेत्र मे स्वतत्रता से पूर्व एव पश्चात् के भूमि उपयोग का प्रतिरूप सारिणी सख्या 5 ।। म दिया गया है । यद्यपि भूमि उपयोग के वर्गीकरण मे किचित भिन्नता के कारण पूर्ण रूप से तुलनात्मक अध्ययन सभव नही है, किन्तु फिर भी इससे महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते है । सारिणी सख्या 5 ।। से स्पष्ट है कि वन के क्षेत्रों मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वर्ष ।96। से ।986 - 87 तक वन का क्षेत्रफल केवल 0 । प्रतिशत ही बना रहा है । किन्तु परती क्षेत्र मे ह्रास हुआ है । शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष ।90। मे 56 2 प्रतिशत, वर्ष ।95। मे 6। 7 प्रतिशत तथा ।96। मे 64 7 प्रतिशत था । तात्पर्य यह है कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र मे वृद्धि हुई है । यह उल्लेखनीय है कि सिचित क्षेत्र मे पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । उदाहरण क लिए ।95। मे सिंचित क्षेत्र केवल 38 0 प्रतिशत था जबकि सन् ।96। मे यह बढ कर 40 0 प्रतिशत हो गया था तथा ।986 - 87 मे सिंचित क्षेत्र 62 0 प्रतिशत तक पहुच गया । इसी प्रकार एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रमे पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । वर्ष ।96। मे एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 24 3 प्रतिशत था जो ।986 - 87 मे बढ कर 38 0 प्रतिशत हो गया । उसका महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पादन पर पडा है और उत्पादन क्षमता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

वर्ष ।986 - 87 के भूमि उपभोग का प्रतिरूप विकासखण्ड स्तर पर देखा गया है (सारिणी सख्या 5 ।2 तथा चित्र सख्या 5 6) । इस सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद मे वन का अभाव है, किन्तु ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि अधिक है । जिन विकास खण्डों मे शुद्ध बोया गया क्षेत्र 60 0 प्रतिशत से अधिक है, उनमे आसपुर देवसरा (67 4 प्रतिशत), सागीपुर (66 8 प्रतिशत), मगरौरा (66 3 प्रतिशत), पट्टी (66 । प्रतिशत), मानधाता (66 0 प्रतिशत), सदर (65 4 प्रतिशत), सड़्वा चन्द्रिका (63 0 प्रतिशत), गौरा (62 3 प्रतिशत), लक्ष्मणपुर (60 8 प्रतिशत) तथा शिवगढ (60 4 प्रतिशत) है । किन्तु कालाकाकर (59 7 प्रतिशत), रामपुरखास (59 3 प्रतिशत), कुन्डा (59 । प्रतिशत), बाबागज (58 । प्रतिशत) तथा बिहार (56 3 प्रतिशत) विकास खण्डों मे शुद्ध बोये गये क्षेत्र ,का क्षेत्रफल 60 प्रतिशत से कम है, जो

LAND USE PATTERN
PRATAPGARH DISTRICT
(1986-87)
N
NET AREA CULTIVATED
PERMANENT PASTUREE
AREA NOT CULTIABLE
BARREN LAND
OTHER CURRENT FALLOW
CURRENT FALLOW
CULTURABLE WASTE
FOREST
4 0 4 8 12
K M
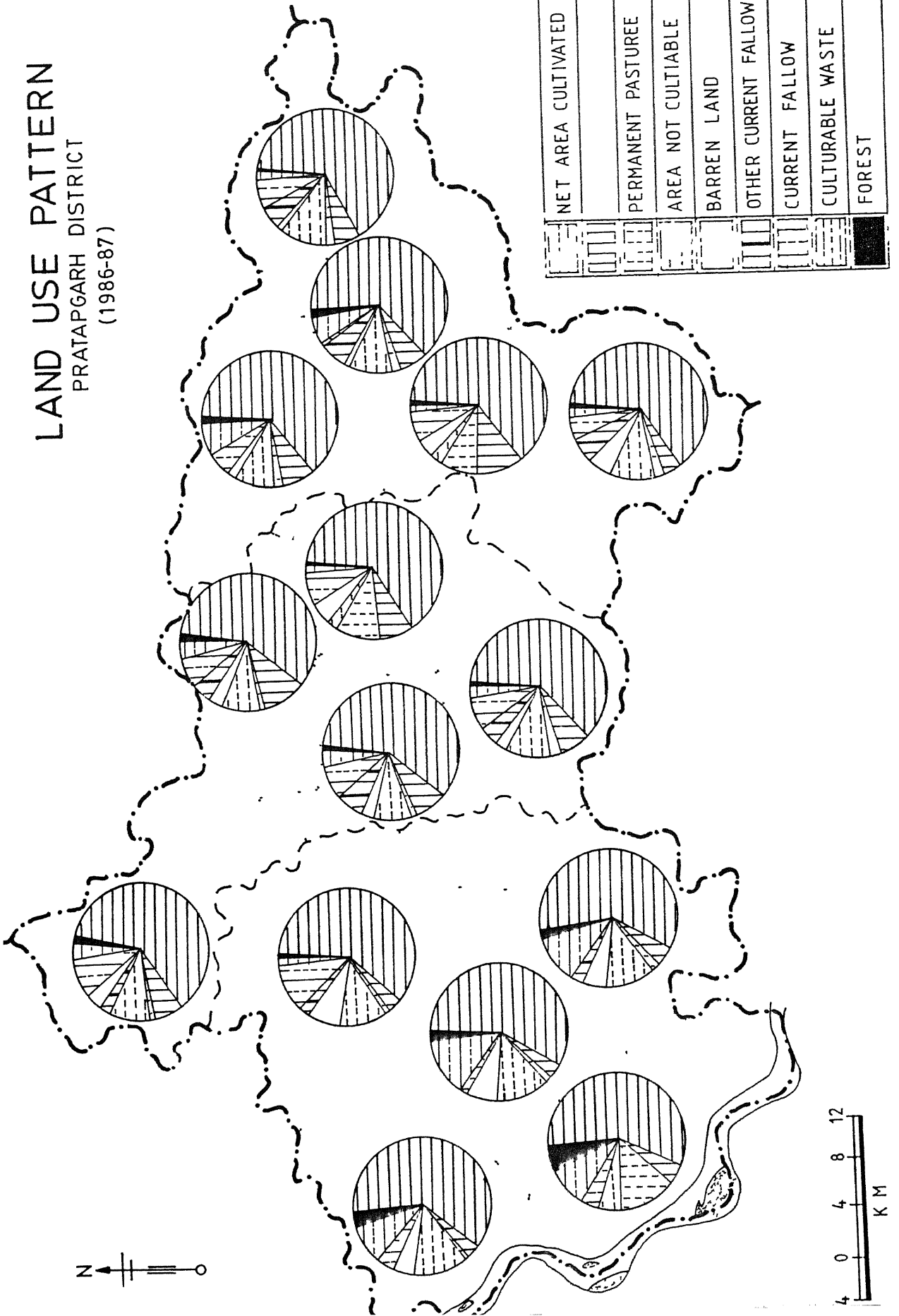
अध्ययन क्षेत्र के औसत उपयोग से कम है । इसका मुख्य कारण यह है कि इन विकास खण्डों मे ऊसर तथा बंजर भूमि अधिक है तथा सिंचाई के साधन अपेक्षाकृत कम है ।

फसल प्रतिरूप - विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाद्यान्न तथा मुद्रादायिनी फसलों के महत्व का स्पष्टीकरण होता है । इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र मे जीविकोपार्जन की कृषि की जाती है अथवा विपणन कृषि पर विशेष बल दिया जाता है । इस तथ्य विश्लेषण के लिये सारिणी सख्या 5 13 तथा चित्र सख्या 5 7 को, देखा जा सकता है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे कृषि योग्य भूमि का अधिकाश भाग प्रारम्भ से ही खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत ही रहा है । किन्तु कुछ अत्यनत महत्वपूर्ण परिवर्तन विगत् 25 वर्षो मे हुये है । स्वतत्रता से पूर्व मुख्य रूप से मोटे अनाज वाली फसलें -- ज्वार, बाजरा, जौ, चना जैसी फसलें अधिक महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि इसके अन्तर्गत अधिकाश भाग लगा था । किन्तु 1961 एव 1986 - 87 के आकडों से स्पष्ट है कि मोटे अनाज वाली फसलों की तुलना मे धान एव गेहू की फसलों का महत्व बढा है । सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के कारण सम्भवत धान की तुलना मे गेहू के क्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि हुई । वर्ष 1961 मे धान के अन्तर्गत 26 6 प्रतिशत तथा गेहू के अन्तर्गत 9 5 प्रतिशत क्षेत्र लगा था । जबकि वर्ष 1986 - 87 मे धान के अन्तर्गत 33 1 प्रतिशत और गेहू के अन्तर्गत 36 3 प्रतिशत भाग लगा था । यह स्पष्ट है कि धान की तुलना मे गेहू के क्षेत्रफल मे तीव्रता से वृद्धि हुई है । वर्ष 1986 - 87 के आँकडों से यह भी स्पष्ट है कि दाल वाली फसलें -- अरहर, चना तथा मटर के उत्पादन पर भी बल दिया जाने लगा है । मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत गन्ना, आलू तथा तिलहन प्रमुख है । किन्तु जहाँ एक ओर आलू एव तिलहन के क्षेत्रफल मे वृद्धि हुई, वहीं गन्ना के उत्पादन क्षेत्र मे कमी आई है । वर्ष 1961 मे गन्ना के अन्तर्गत 1 5 प्रतिशत क्षेत्रफल था जबकि वर्ष 1986 - 87 मे यह केवल 0 9 प्रतिशत रह गया । इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने की खेती विपणन की दृष्टि से लाभकारी नहीं है । जबकि आलू के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र वर्ष 1961 तथा वर्ष 1986 - 87 मे 0 6 प्रतिशत से 1 8 प्रतिशत हो गया है । तिलहन

सारिणी संख्या 5·13 प्रतापगढ़ जनपद में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल §हे0/प्रतिशत§

खाद्यान्न की फसलें	1901	1951	1961	1986-87
धान	13155 §5 7§	66896§23 6§	77263§26 6§	109650§33 1§
गेहूँ	24824§10 7§	25658§8 8§	27337§9 5§	120216§36 3§
जौ	41421§17 8§	53917§18 5§	52237§18 1§	8486§2 6§
ज्वार	14780§6 3§	11640§4 0§	9020§3 1§	5948§0 6§
बाजरा	11211§4 8§	170440§5 8§	19196§6·6§	16734§5 0§
मक्का	820§0 3§	2179§0 7§	2363§0 8§	2589§1 8§
अरहर	–	–	–	16888§5 1§
मूग उर्द	–	–	–	6171§2·9§
चना	27308§11 7§	23485§8 0§	23346§8 1§	12976§4 0§
मटर	–	–	–	4666§1·4§
अन्य खाद्यान्न की फसलें	83037§35·7§	71769§24 6§	61738§21·5§	2374§0·8§
कुल खाद्यान्न फसलों का योग ·	216556§93 0§	274588§94 0§	272499§94 3§	309998§93 6§
मुद्रादायिनी फसलें				
गन्ना	4923 §2 1§	4368 §1 5§	4181 §1 5§	2819 §0 9§
आलू	–	1306 §0 5§	1624 §0·6§	5441 §1 8§
तिलहन	1125 §0 4§	347 §0 1§	394 §0·1§	1497 §0 5§
अन्य मुद्रादायिनी फसलें	10194 §4·3§	11410 §3 9§	10067 §3·5§	11306§3 4§
कुल मुद्रादायिनी फसलों का योग .	17142 §7 4§	17431§5 96§	17266§5·99§	21063§6 4§
कुल फसलों का योग:	23798§100 0§	292020§100 0§	288764§100 0§	331033§100 0

स्त्रोत · प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैण्ड बुक 1961

का क्षेत्र वर्ष 1961 तथा 1986 - 87 मे 0 1 प्रतिशत से बढ कर 0 5 प्रतिशत हो गया । विगत् 26 वर्षो (1961 - 87) मे खाद्यान्न के अन्तर्गत लगे क्षेत्र की तुलना मे मुद्रादायिनी फसलों के क्षेत्र मे वृद्धि हुई है । खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र 94 3 प्रतिशत (1961) से घटकर 93 6 प्रतिशत (1986 - 87) रह गया । और इस बीच मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ क्षेत्र 5 97 प्रतिशत से बढकर 6 4 प्रतिशत हो गया । किन्तु फिर भी मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र की यह वृद्धि नगण्य है ।

लघु क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप के विश्लेषण के लिये विकास खण्ड स्तर पर वर्ष 1986 - 87 के आँकडों को सारिणी सख्या 5 14 तथा मानचित्र 5 7 द्वारा प्रदर्शित किया गया है । स्पष्ट है कि सभी विकासखण्डों मे धान एव गेहू के अन्तर्गत लगा क्षेत्र अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है । जिन विकास खण्डों मे धान की तुलना मे गेहू की खेती अधिक हो रही है उनमे सदर, लक्ष्मणपुर, मानधाता, सडवा चन्द्रिका, सागीपुर, कुन्डा, शिवगढ तथा आसपुर देवसरा है । शेष सात विकास खण्डों (कालाकाकर, बाबागज, बिहार, रामपुरखास, पट्टी, गौरा तथा मगरौरा) मे धान की खेती अधिक होती है । खाद्यान्न की फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों का महत्व जिन विकासखण्डों मे बढा है उनमे सदर, सडवा चन्द्रिका, साँगीपुर, शिवगढ, मानधाता मुख्य है । फसल मे विविधता की प्रक्रिया प्रारम्भ होगयी है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।

फसल गहनता फसल गहनता शुद्ध बोया गया क्षेत्र एव सकल बोया गया क्षेत्र का अनुपात होता है । इससे क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग तथा उत्पादकता का स्पष्टीकरण होता है । इसका परिकलन अधोलिखित सूत्र के द्वारा किया जाता है (राम किशोर, 1987) ।

$$\text{फसल गहनता} = \frac{\text{स0 बो0 क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बो0 क्षेत्र}} \times 100$$

स0 बो0 - सकल बोया गया

शु0 बो0 - शुद्ध बोया गया क्षेत्र

सारिणी संख्या 5 14 प्रतापगढ जनपद में विकास खण्डवार फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत 1986-87

	धान	गेहूँ	जौ	ज्वार	बाजरा	मक्का	अन्य धान	उर्द	मूग	चना	मटर	अरहर	कुल खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	आलू	तम्बाकू	अन्य फसल
सदर -	10 7	28 9	6 6	3 5	13 8	0 4	1 3	2 2	1 3	9 0	1 4	12 5	91 6	0 5	0 3	1 3	--	6 3
लक्ष्मणपुर	28 7	37 6	3 4	1 7	8 0	0 0	0 7	2 5	0 8	4 2	1 5	6 0	94 1	0 3	0 3	0 6	-	3 8
मानधाता	28 8	38 8	1 9	1 1	7 8	0 1	1 0	1 9	1 0	2 9	1 4	5 0	91 8	0 3	0 8	2 8	0 0	4 3
स0 चन्द्रिका	12 2	28 4	5 6	4 2	11 6	0 1	1 5	3 8	0 8	9 5	1 8	10 0	89 6	0 5	1 0	1 8	-	7 1
सागीपुर	25 5	3 5	3 3	5 9	4 8	0 1	1 7	5 2	1 1	6 8	2 1	7 2	95 4	0 5	0 2	1 2	-	3 8
कुण्डा	31 0	38 4	4 0	1 2	5 5	0 0	0 3	1 1	0 6	4 8	1 2	4 4	92 5	0 6	0 1	1 3	0 0	5 5
कालाकाकर	40 7	37 5	1 7	1 4	3 1	0 0	0 4	1 5	1 2	1 3	0 9	3 8	93 5	0 7	0 3	1 6	-	3 9
बाबागज	47 0	40 4	0 9	1 0	0 9	0 0	0 2	1 0	1 0	1 1	0 9	1 6	96 0	0 5	0 5	1 3	0 0	1 7
बिहार	44 2	39 5	1 4	0 5	2 0	0 0	0 3	1 7	1 0	1 5	1 3	2 2	95 4	0 3	0 3	2 0	0 0	2 0
रामपुर	41 3	38 5	1 9	1 6	2 1	0 0	0 9	2 1	1 5	1 8	1 4	3 0	96 2	0 3	0 4	1 3	0 0	1 8
पट्टी -	36 9	36 5	1 0	1 0	2 8	2 9	0 4	0 6	0 8	2 7	1 8	4 3	91 2	0 7	2 1	1 6	-	4 1
गौरा	40 9	36 8	1 1	0 5	2 5	0 6	0 2	0 9	0 7	2 3	1 3	2 6	90 5	0 4	1 5	2 0	-	5 6
शिवगढ	16 6	31 2	5 2	1 3	12 8	1 2	1 0	1 0	0 7	7 8	1 1	12 6	92 5	0 4	0 6	2 2	-	4 3
मगरौरा	37 2	35 7	1 8	0 9	3 9	0 3	0 8	0 9	0 5	3 7	3 5	4 4	91 6	0 6	0 3	1 3	-	5 1
आसपुर देवसरा	36 4	38 8	0 5	1 8	0 8	6 0	0 2	0 8	1 0	2 3	0 7	2 2	92 7	0 3	2 6	1 8	-	2 6
जनपद	33 1	36 3	2 6	0.6	5 0	1 8	0 8	1 8	1 1	4 0	1 4	5 1	93 6	0 5	0 9	1 6	0 0	3 4

स्रोत जिला साख्कीय पत्रिका, 1988

विकास खण्ड स्तर पर फसल गहनता का तुलनात्मक प्रारूप सारिणी 5.15 मे प्रस्तुत है । इन दो वर्षो (1979-80 व 1986-87) के फसल गहनता से स्पष्ट है कि केवल सदर विकासखन्ड को छोडकर शेष अन्य विकासखण्डों मे फसलगहनता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । दोनों के अन्तर से यह भी प्रतीत होता है कि कुछ विकासखण्डों मे उदाहरण के लिये बिहार (27.4 प्रतिशत), आसपुर देवसरा (22.3 प्रतिशत) तथा कालाकाकर (20 प्रतिशत) मे फसलगहनता मे 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । लक्ष्मणपुर, पट्टी, गौरा, बाबागज, मगरौरा, मडवा चन्द्रिका मानधाता तथा कुन्डा विकासखण्डों मे फसलगहनता मे 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । रामपुरखास तथा शिवगढ एव सागीपुर विकासखण्डों मे फसलगहनता की वृद्धि की दर 10 प्रतिशत से कम है केवल सदर विकासखण्ड मे ही ऐसा है जहाँ पर फसलगहनता मे लगभग 3.0 प्रतिशत का ह्रास हुआ । सारिणी 5.15 मे प्रस्तुत दो विभिन्न वर्षो के फसलगहनता के अन्तर प्रतिशत को मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया (चित्र सख्या 5.15) है। जिले के फसल गहनता पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि जनपद स्तर पर फसल गहनता वर्ष 1961 मे 124 से बढकर 1986-87 मे 148 हो गयी है किन्तु फसलगहनता की सीमा को और अधिक बढाया जा सकता है । फसलगहनता की वृद्धि के लिये सिचाई की सुविधाओं मे वृद्धि अत्यावश्यक है ।

फसलोत्पादन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढाने के अनेक प्रयत्न किये गये जिसमे चावल, गेहू, दाल, तिलहन तथा मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त प्रभाव पडा है । सारिणी सख्या 5.16 मे प्रतापगढ जनपद मे प्रमुख फसलों के उत्पादन का विवरण प्रस्तुत है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि विगत् सात आठ वर्षो मे चावल एव गेहू के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई । चावल के उत्पादन मे लगभग 60.0 प्रतिशत की वृद्धि तथा गेहू के उत्पादन मे लगभग 93.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु जौ, ज्वार, बाजरा तथा अन्य खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन मे गिरावट आई है । स्पष्ट है कि मोटे अनाज वाली फसलों का महत्व कम होता जा रहा है । दालों के उत्पादन मे भी कमी आई है । किन्तु उर्द, मूग तथा मटर के उत्पादन मे वृद्धि हुई है । तिलहन

सारिणी संख्या 5 15 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर फसलगहनता

विकासखण्ड का नाम	1979-80	1986-87	अन्तर	अन्तर प्रतिशत
सदर	135	131	-4	2 96
लक्ष्मणपुर	125	144	+19 0	15 2
मानधाता	135	153	+18 0	13 0
सडवा चन्द्रिका	121	134	+13 0	10 74
सागीपुर	138	139	+1 0	0 72
कुण्डा	124	137	+13 0	10 48
कालाकाकर	135	162	+27 0	20 0
बाबागज	134	160	+26 0	19 4
बिहार	124	158	+34 0	27 4
रामपुरखास	140	148	+8 0	5 7
पट्टी	132	153	+21 0	15 9
गौरा	136	159	+23 0	17 0
शिवगढ	123	134	+11 0	8 94
मगरौरा	134	149	+15 0	11 19
आसपुर देवसरा	134	164	+30 0	22 38
जनपद	134	148	+14 0	10 45

सारिणी सख्या 5 16 प्रतापगढ जनपद मे मुख्य फसलों का उत्पादन (मी0 टन)

फसल	1978-79	1986-87
चांवल	92284	146705
गेहँ	107422	207164
जौ	25590	10358
ज्वार	6513	6408
बाजरा	20034	14177
मक्का	1818	1838
अन्य खाद्यान्न	3115	1815
कुल खाद्यान्न	256780	388465
उर्द	830	2268
मूँग	265	1635
चना	11188	11148
मटर	3144	3938
अन्य दालें	682	10
कुल दालें	41939	36054
तिलहन		
लाही सरसों	315	306
अलसी	33	72
तिल	17	27
मूगफली	25	6
मुद्रादायिनी		
गन्ना	90133	62071
आलू	1110176	91401
तम्बाकू	45	20

स्रोत जिला सांख्यकीय पत्रिका 1980, 1988

वाली फसलों के अन्तर्गत अलसी और तिल को छोड़कर शेष अन्य फसलों के उत्पादन मे कमी हुई है ।

मुद्रादायिनी फसलों, मुख्य रूप से गन्ना, आलू एव तम्बाकू के उत्पादन मे कमी आई है ।

• सिचाई ससाधन तथा सिचाई गहनता कृषि की उत्पादकता तथा विविधता मे सिचाई के साधनों का विशिष्ट स्थान है । स्पष्ट है कि कृषि की परिवर्तनशीलता अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक परिवर्तन मे महत्वपूर्ण स्थान रखती है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 38 0 प्रतिशत भाग सिचित था । किन्तु तृतीय एव चतुर्थ पचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप तथा कालान्तर मे पाचवी, छठी एव सातवीं योजनाओं के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन् 1986-87 मे कुल बोये गये क्षेत्र का 62 0 प्रतिशत भाग सिचित था (सारिणी 5 17) । सिचाई के कई साधन है । किन्तु जो चार साधन प्रमुख है उनमे नहर, नलकूप, कुए एव तालाब का विशेष महत्व है । सन् 1979-80 मे नहरों की कुल लम्बाई 1055 6 कि0 मी0 थी जो 1986-87 मे बढकर 1685 कि0 मी0 हो गयी है । ये नहरे मुख्यरूप से शारदा सहायक परियोजना का अग है । चार सिचाई योजनाये भी चलाई गई है । किन्तु शक्ति के अभाव मे उनका लाभ नहीं लिया जा सका । नलकूपों की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन् 1979-80 तथा 1986-87 मे राजकीय तथा निजी नलकूपों की सख्या क्रमश 113 तथा 17511 से बढकर 155 तथा 27761 हो गयी है । निजी नलकूपो की सख्या मे जिस गति से वृद्धि हुई उसस न केवल किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सिद्ध होती है, अपितु कृषि मे सिचाई के महत्व का स्पष्टीकरण भी होता है । परम्परागत सिचाई के साधन उदाहरण के लिये कुए, रहट तथा पम्पिग सेटों की सख्या मे कमी आई है । पक्के कुए 31580 (1979-80) से घटकर 20118 हो गये है । इसी बीच रहट की सख्या 13 से 6 तथा पम्पिग सेटों की सख्या 1577 से घटकर 823 हो गयी है । सिचाई के विभिन्न साधनों की सख्या मे काफी प्रकार का उतार चढाव आया है । उदाहरण के लिये 1986-87 मे नहरों एव नलकूपों के द्वारा क्रमश 59 2 प्रतिशत तथा 36 7

प्रतिशत भाग सींचा गया है । कुए एव तालाबों का योगदान 3 3 प्रतिशत तथा 0 6 प्रतिशत रहा है । सिचाई के अन्य साधनों का योगदान केवल 0 3 प्रतिशत रहा है । यदि हम 1979-80 के आकडों से इसकी तुलना करे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि कुँआ, तालाब और इसी प्रकार के अन्य परम्परागत सिचाई के साधनो का महत्व धीरे धीरे घट रहा है (सारिणी सख्या 5 18 से 5 20) ।

विकासखण्ड स्तर पर नहर, नलकूप, कुआ, तालाब तथा सिचाई के अन्य साधनों द्वारा की जाने वाली सिचाई का तुलनात्मक विवरण सारिणी सख्या 5 20 मे प्रस्तुत किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि नहर एव नलकूपों के प्रभाव मे व्यापक वृद्धि हुई । सिचाई की गहनता को विकासखण्ड स्तर पर प्रदर्शित करने के लिये अधोलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है (रामकिशोर) ।

$$\text{सि0 स0 सूत्र} = \frac{\text{स0 सि0 क्षेत्रफल} \times 100}{\text{शु0 स0 क्षेत्रफल}}$$

जिसमे सि0 = सिंचित

स0 = सघनता

सू0 = सूचकाक

शु0 = शुद्ध

स0 = सकल

सिचाई गहनता को सारिणी सख्या 5 21 द्वारा दर्शाया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि 1979-80 तथा 1986-87 के अन्तराल मे सिचाई गहनता मे वृद्धि हुई । इन दो समयों के मध्य सिंचाई गहनता के अन्तर वृद्धि को मानचित्र (सख्या 5 8) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस मानचित्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के विकासखन्डों को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है

प्रथम वे विकासखन्ड जहाँ पर सघनता की बढोत्तरी अन्तर प्रतिशत 16 से अधिक है । इनके अन्तर्गत केवल कालाकाकर विकासखन्ड आता है ।

सारिणी सख्या 5..17 प्रतापगढ़ जनपद में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हैक्टयर)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हैक्टयर)	प्रतिशत
1951	230253	87554	38 0
1961	238104	95278	40 0
1979-80	222160	130361	58 7
1986-87	224685	140089	62 0

स्रोत जिला जनगणना पुस्तिका 1961

जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

सारिणी सख्या 5 18 प्रतापगढ जनपद मे सिंचित साधनों की सख्या

	1979-80	1986-87
नहरों की लम्बाई (कि0 मी0)	1055 6	1685
राजकीय नलकूप	113	155
पक्के कुए	31580	20118
रहट	13	6
पम्पिग सेट	1577	823
निजी नलकूप	17511	21761

स्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

सारिणी संख्या 5.19 प्रतापगढ जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत)

वर्ष	1979-80	1986-87
नहर	45 7	59 2
नलकूप	38 4	36 7
कुए	14 0	3 3
तालाब/झील	1 7	0 6
अन्य	0 2	0 2

स्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

सारिणी संख्या 5 20 प्रतापगढ जनपद में विकास खण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (1979-80, 1986-87)

विकास खण्ड का नाम	नहर		नलकूप		कुऐं		तालाब		अन्य	
	1979-80	1987-87	1979-80	1986-87	1979-80	86-87	1979-80	86-87	79-80	86-87
सदर	12 7	19 9	55 4	69 8	31 8	9 5	0 1	0 0	-	0 8
लक्ष्मणपुर	50 3	66 5	27 1	25 6	20 7	7 6	1 4	0 3	0 5	-
मानधाता	38 3	55 4	44 4	41 7	15 6	2 5	1 0	0 3	0 7	0 1
स0 चन्द्रिका	2 0	2 2	62 3	86 1	35 6	10 3	0 0	0 1	0 1	1 3
सांगीपुर	32 0	61 7	25 6	26 0	40 5	11 9	1 9	0 1	0 0	0 3
कुण्डा	80 8	92 3	16 0	6 9	3 3	0 3	0 1	0 5	-	-
कालाकाकर	82 9	94 2	12 9	5 6	3 3	0 2	0 9	0 0	-	-
बाबागज	78 6	91 5	17 1	7 0	1 0	0 2	3 1	1 3	0 2	-
बिहार	68 6	89 2	34 9	9 5	3 0	0 3	2 9	0 4	0 6	0 6
रामपुरखास	65 7	84 3	29 4	14 9	4 5	0 8	0 9	0 0	-	-
पट्टी	31 4	35 9	57 6	62 5	8 8	1 2	2 2	0 3	0 3	0 2
गौरा	35 8	49 3	52 9	44 5	8 2	1 9	3 1	4 3	0 0	0 0
शिवगढ	14 7	13 7	61 4	18 7	23 5	7 5	0 4	0 1	0 3	0 0
मगरौरा	26 8	36 2	46 3	7 9	12 8	2 2	4 8	0 8	0 0	0 0
आसपुर देवसरा	29 1	37 2	56 2	61 5	12 6	1 2	1 6	0 1	0 5	0 0

स्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

सारिणी संख्या 5 21 जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर सिचाई गहनता

विकासखण्ड का नाम	1979-80	1986-87	अन्तर प्रतिशत
सदर	102	104	2 0
लक्ष्मणपुर	103	112	8 7
मानधाता	114	118	3 5
सडवा चन्द्रिका	119	109	8 4
सागीपुर	104	103	1 0
कुण्डा	108	114	5 6
कालाकाकर	105	140	33 3
बाबागज	104	116	11 5
बिहार	103	118	14 6
रामपुरखास	108	112	3 7
पट्टी	110	116	5 5
गौरा	110	122	10 9
शिवगढ	104	108	3 8
मगरौरा	108	108	-
आसपुर देवसरा	107	118	9 3

श्रोत जिला साख्यकीय पत्रिका 1980, 1987

(A)

PRATAPGARH DISTRICT

LAND USE INTENSITY DIFFERENTIALS

(1979-87)

N

IN PER CENT

	< 07
	07 - 06
	06 - 11 3
	11 3 - 16 8
	> 16 8

5 0 5 10

KM

(B)

PRATAPGARH DISTRICT

IRRIGATION INTENSITY DIFFERENTIALS

(1979-87)

N

IN PER CENT

	0 - 8
	8 - 16
	> 16

5 0 5 10

KM
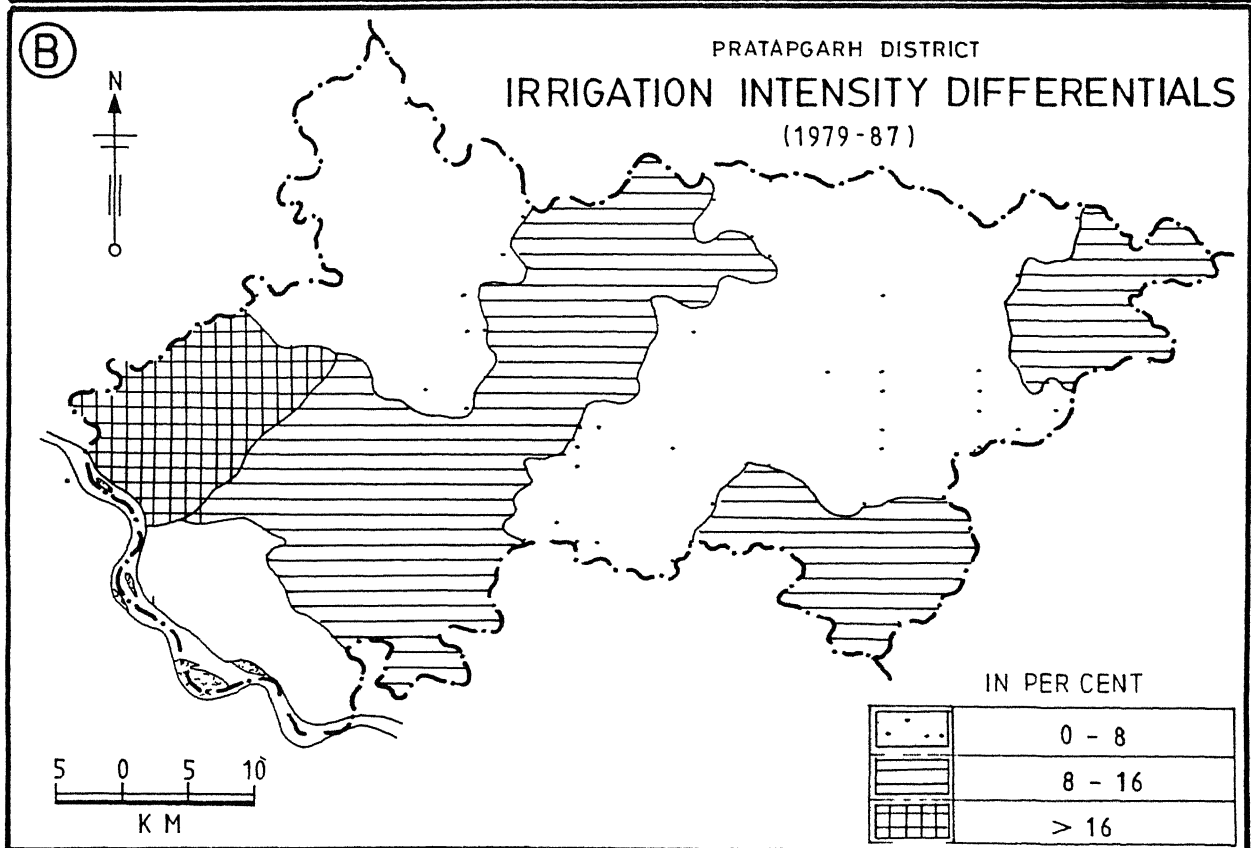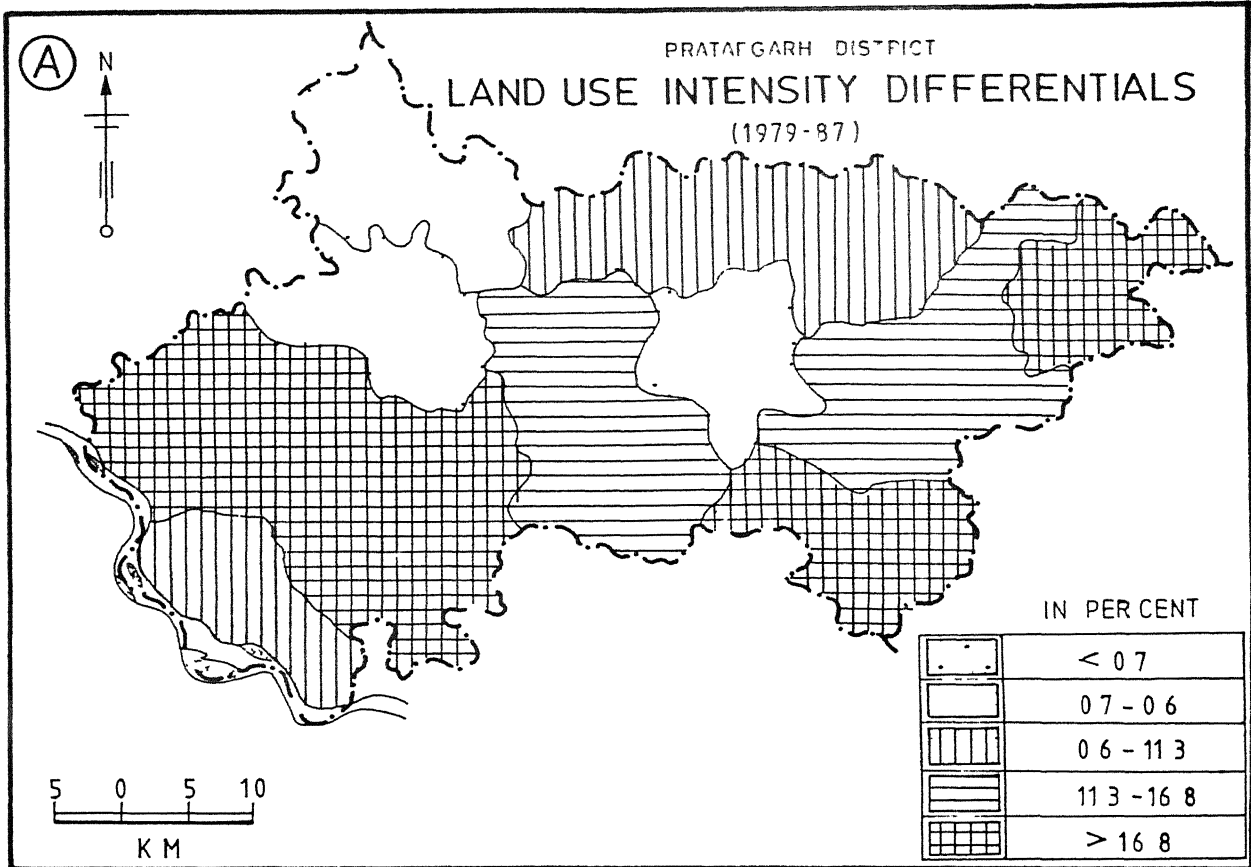
Fig.5.8

द्वितीय वे विकासखन्ड जहाँ पर सघनता का बढात्तरी अन्तर प्रतिशत 8 से 16 के बीच है। इनके अन्तर्गत आसपुर देवसरा, गौरा, बिहार, बाबागज तथा सडवा चन्द्रिका विकासखन्ड आते है ।

तृतीय वे विकासखन्ड जहाँ सिचाई सघनता की बढोत्तरी का अन्तर प्रतिशत 8 से कम है। इसके अन्तर्गत सदर, मानधाता, सागीपुर, कुन्डा, रामपुरखास, पट्टी तथा शिवगढ विकासखन्ड आते है ।

सामाजिक - आर्थिक रूपान्तरण सहसम्बन्ध उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अधोलिखित सकल्पनाओं का परीक्षण सह सम्बन्ध विधि के आधार पर किया गया है, ये सकल्पनाये इस प्रकार है -

1 ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि के साथ साथ धान एव गेहू (जो खाद्यान्न की मुख्य फसलें है) के क्षेत्रफल मे भी वृद्धि हो रही है ।

2 ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि एव वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल मे महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

3 प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायिक वर्गो मे कार्यरत जनसख्या के प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि मे भी महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

4 साक्षरता प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि मे महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

5 भूमि उपयोग गहनता तथा सिचाई गहनता मे महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

6 धान के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र तथा विकास खण्डों मे सेवाकेन्द्रों मे महत्वपूर्ण सह सम्बन्ध है ।

7 गेहू के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एव विकास खण्डों मे सेवाकेन्द्रों की सख्या मे महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है ।

8 वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एव विभिन्न विकासखन्डों के सेवा केन्द्रों की सख्या मे सह सम्बन्ध है ।

इन सकल्पनाओं के परीक्षण के लिये कोटिक्रम पर आधारित सह सम्बन्ध का परिकलन किया गया है तथा टी टस्ट

का प्रयोग कर 95 प्रतिशत सम्भावना का आधार मानकर प्रमाणिकता परीक्षण किया गया है । सह सम्बन्धों का परिकलित परिणाम सारिणी सख्या 5 2 2 तथा सह सम्बन्धों के प्रतिरूपों का परिणाम रेखा चित्रों (सख्या 5 10) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस परिकलन से अधोलिखित तथ्य स्पष्ट होते है

1 यह सत्य है कि ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि तथा धान एव गेहू के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल मे महत्वपूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध है क्योंकि उनमे से प्रत्येक का सह सम्बन्ध 0 5 है जो 95 प्रतिशत की सम्भावना पर प्रामाणिक है । यह सम्बन्ध इस बात का द्योतक है कि जनसख्या मे वृद्धि के साथ धान गेहूँ के क्षेत्रफलों मे वृद्धि हो रही है ।

2 द्वितीयक सकल्पना प्रामाणिक प्रतीत होती है क्योंकि ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि के साथ वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों का सह सम्बन्ध 0 5 है । यह इस बात का द्योतक है कि अध्ययन क्षेत्र मे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ रही है । चतुर्थ सकल्पना केवल आन्तरिक रूप से ही उचित प्रतीत होती है ।

3 प्राथमिक, द्वितीयक, तथा तृतीयक वर्गो मे लगी हुई कार्यरत जनसख्या एव ग्रामीण जनसख्या की वृद्धि के सह सम्बन्ध क्रमश 0 03, 0 12, तथा 0 24 है जो प्रामाणिक सह -सम्बन्ध नहीं है ।

4 ग्रामीण जनसख्या वृद्धि के साथ साक्षरता प्रतिशत मे भी वृद्धि हो रही है क्योंकि उनका सह सम्बन्ध 0 4 है किन्तु ये भी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता है । तत्यपि यह है कि जनसख्या की वृद्धि की साक्षरता प्रतिशत की गति से अधिक है ।

5 भूमि उपयोग गहनता तथा सिचाई गहनता अन्योश्रित से सह सम्बन्ध (0 86)

6 छठी सकल्पना कि धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा सेवाकेन्द्रों की सख्या मे प्रामाणिक सह

सारिणी सख्या 5 22 विकास स्तर पर चुने हुये सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण चर और सहसम्बन्ध

क्रम स0	सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण चर		कोटिक्रमानुसार सह-सम्बन्ध
01	धान के अन्तगत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 5
02	गेहू के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 5
03	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 5
04	प्राथमिक वग मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 5
05	द्वितीयक वर्ग मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 12
06	तृतीयक वर्ग मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 24
07	साक्षरता प्रतिशत	ग्रामीण जनसख्या वृद्धि का प्रतिशत	0 4
08	भूमि उपयोग गहनता प्रतिशत	सिचाई गहनता प्रतिशत	0 86
09	धान के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड मे सेवाकेन्द्रों की सख्या	0 8
10	गेहू के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड मे सेवाकेन्द्रों की सेवा	0 2
11	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत	विकासखण्ड मे सेवाकेन्द्रों की सख्या	0 5

स्रोत परिकलन पर आधारित

मम्बन्ध है, सत्य है, क्योंकि यह 0 8 है इससे स्पष्ट है कि धान की खेती के उत्पादन से, सेवाकेन्द्रों के विकास को बल मिला है ।

7 सातवीं सकल्पना खरी नहीं उतरती क्योंकि गेहूँ के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्रफल तथा सेवाकेन्द्रों की सख्या मे यद्यपि धनात्मक (0 2) सम्बन्ध है किन्तु यह प्रामाणिक नहीं है ।

8 आठवीं सकल्पना प्रामाणिक प्रतीत होती है क्योंकि वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत लगे हुये क्षेत्र एव सेवाकेन्द्रों की सख्या मे धनात्मक सह सम्बन्ध (0 5) है । स्पष्ट है कि जैसे जैसे क्षेत्र मे वाणिज्यि से सम्बन्धित फसलों का प्रचलन बढ रहा है वैसे वैसे सेवाकेन्द्रों की सख्या मे वृद्धि हो रही है ।

उपरोक्त निष्कर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो न केवल अधिवास तत्र मे होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करते है अपितु ये अधिवास तत्रों को सुसगठित करने मे नीति निर्धारण के स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते है । अध्ययन क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हो रहे है, और इन परिवर्तनों से सेवा केन्द्रों की सख्या मे वृद्धि हो रही है ।

भूमि सुधार एव भूस्वामित्व के वितरण का प्रतिरूप

भूमि सुधार एव भूस्वामित्व के वितरण का प्रतिरूप अधिवासों के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अधिवासों का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है और कृषि उत्पादन का मुख्य आधार भूमि है । इसलिये भूमि क स्वामित्व का प्रतिरूप तथा भूस्वामित्व को सगठित करने क लिये जो भी प्रयत्न समय समय पर किये जाते है उनका अधिवासों की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव पडता है । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र मे मुगलकाल से पूर्व भूराजस्व अथवा भूमि सुधार का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलता है । किन्तु शेरशाह एव सम्राट अकबर द्वारा किये गये प्रशासकीय एव भूराजस्व निर्धारण के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे है (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1980) । अध्ययन क्षेत्र मे मुख्य रूप से तीन बदोबस्त सम्पन्न हुये । प्रथम बदोबस्त अक्टूबर 1860 मे प्रारम्भ हुआ, द्वितीय जुलाई सन् 1892 तथा तृतीय अक्टूबर 1922 मे सम्पन्न हुये । इन बदोबस्तों का मुख्य उद्देश्य भूमि की क्षमता के आधार पर

गजस्व निर्धारण करना, बिचर्वालिया प्रथा को समाप्त करना, बटाई प्रथा मे सुधार लाना तथा खेत पर काम करने वालों का अधिक से अधिक सरक्षण पदान करना था ।

स्वतन्त्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन एव भूमि सुधार कानून एक्ट, 1950 की व्यवस्था कर भूस्वामित्व के बिखराव को समेट कर उन्हे तीन वर्गो मे विभाजित किया

1. भूमिधर जिसको पूणरूप से भूमि पर स्वामित्व प्राप्त है तथा अपनी सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। इनको पैतृक स्वामित्व भी प्राप्त है ।

2. सीरदार यह वे किसान है जिनका पैतृक अधिकार प्राप्त है किनतु भूमि का स्थान्तरण नहीं कर सकते है । यदि चाहे तो दस गुना राजस्व जमाकर भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर सकते थे ।

3. असामी यह वे किसान थे जो वन, भूमि, रहन भूमि व बगीचे की भूमि का उपयोग कर सकत है किन्तु उनको पैतृक अधिकार नहीं था । उन्हे भूमि से बेदखल किया जा सकता है ।

सन 1971 म अध्ययन क्षेत्र मे 110400 भूमिधर थ जो 36029 हैक्टयर भूमि पर खेती करते थे । सीरदार की सख्या 165500 थी और अनके अधिकार क्षेत्र मे 65693 हैक्टयर भूमि थी । सन 1953 म उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम की व्यवस्था की गयी है । जिसका उद्देश्य बिखरी हुयी तथा छोटी कृषि सीमाओं को पुन गठित करना था । इसका कार्यान्वयन सन् 1970 मे हुआ (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1980) । सन् 1960 मे भूमि सीमा निर्धारण के लिये तथा बडे कृषकों से भूमि लेकर छोटे किसानों अथवा सीमान्त कृषकों मे वितरित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार **भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1960** की व्यवस्था की है जिसका कार्यान्वयन अध्ययन क्षेत्र मे जनवरी 1961 मे प्रारम्भ हुआ ।

इन विभिन्न भूमि सुधार के अधिनियमों के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र का भूस्वामित्व तथा भूमि सीमा पूर्णरूपेण प्रभावित हुई । सारिणी सख्या 5 23 मे प्रतापगढ जनपद मे क्रियात्मक

सारिणी सख्या 5 23 प्रतापगढ जनपद मे क्रियात्मक जोतों की संख्या

वर्ष	1951	1961	1977	1980-81
0 - 2 है0	65323	67881	363200	392616
	(69 1)	(68 2)	(93 7)	(94 4)
2 - 4 है0	16763	17325	18596	12814
	(17 7)	(17 4)	(4 8)	(3 1)
4 - 10 है0	12134	13783	5139	10258
	(12 8)	(13 8)	(1 3)	(2 5)
10 है0 अधिक	381	595	442	--
	(0 4)	(0 6)	(0 2)	--
	94601	99584	387372	415688
	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961 जिला साख्यकीय पत्रिका 1978

जोतों की सख्या और उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित किया गया है । इस सारिणी से स्पष्ट है कि क्रियात्मक जोतों की सख्या तथा क्षेत्रफल मे पर्याप्त विषमता पायी जाती है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सीमान्त कृषकों की सख्या बहुत अधिक है । अध्ययन क्षेत्र मे 83 प्रतिशत सीमान्त कृषक है जिनके पास 46 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है । । से 2 हैक्टयर, 2 से 3 हैक्टयर तथा 3 से 5 हैक्टयर के बीच ।। 3, 3 । तथा । 8 कृषक है जबकि उनके द्वारा अधिकृत भूमि का क्षेत्रफल क्रमश 24 प्रतिशत, ।2 4 प्रतिशत तथा ।0 0 प्रतिशत है । लगभग 7 0 प्रतिशत कृषक ऐसे है जिनके पास 5 हैक्टयर से अधिक भूमि है और उनके द्वारा अधिकृत भूमि भी कुल भूमि का 7 0 प्रतिशत है । सारिणी सख्या

मे स्पष्ट है कि सन् ।95।, ।96।, ।97। तथा ।980-8। मे भूमि के सीमान्तीकरण मे वृद्धि हुई है । भूमि का यह सीमान्तीकरण जहाँ एक ओर उपज को प्रभावित करता है वहीं दूसरी ओर प्रवास को बल देता है । अधिकाश क्रियात्मक जोतों का आकार सीमान्त से कम है । अत नई कृषक पद्धति का भी लाभ नहीं मिल पाता । फलत बडे पैमाने पर कृषि जनसख्या नगरों की ओर पलायन हो रही है । इस प्रकार की प्रवासी जनसख्या नगरों मे मुख्य रूप से अनौपचारिक वर्ग की अर्थव्यवस्था मे कार्यरत है । उदाहरण के लिये उनमे से अधिकाश लोग रिक्शा चालक, ठेला चालक, पान अथवा चाय की दुकान पर या इसी प्रकार अन्य कार्यों मे लगे हुये है किन्तु इस पलायन से निश्चित रूप से नगरीय जनसख्या मे वृद्धि हुई है । बेला प्रतापगढ की बढती हुई आबादी इसका उदाहरण है । दूसरी ओर बडे अथवा मध्यम वर्ग के जोतों वाले कृषक अपनी भूमि बटाई पर देकर अथवा बेचकर स्थानीय कस्बों मे बसने का प्रयत्न कर रहे है । कुन्डा, पट्टी तथा अन्तू इसके मुख्य उदाहरण है । ये लोग मुख्यत होटल, चाय व पान की दुकान, कपडे की दुकान, चूना तथा सीमेन्ट इत्यादि की दुकानें स्थापित कर रहे है । यह प्रवृत्ति इस लिये है कि इस वर्ग के कृषक वास्तविक अर्थों मे कभी भी कृषक नहीं रहे है बल्कि वे जमींदार अथवा बिचवलिया जमींदार रहे है । इधर जनसख्या प्रवास के कारण खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की कमी हो रही है । अत इस वर्ग के कृषकों के लिये कृषि-भूमि प्रबध कठिन होता जा रहा है । विकास खन्ड स्तर पर भमस्वामित्व वितरण प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया है (चित्र 5 9) । इस स्तर
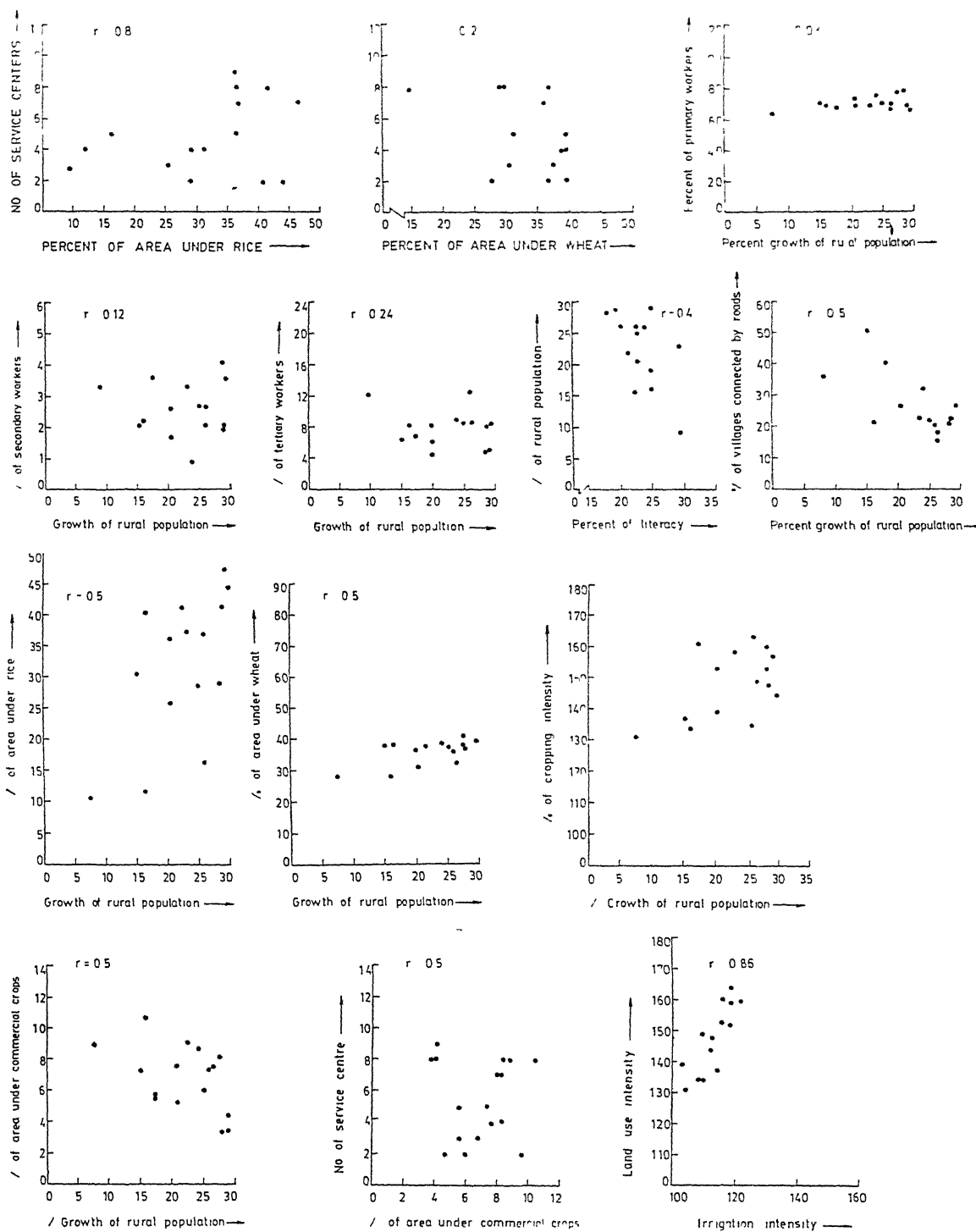
पर भी सीमान्त कृषकों का वर्चस्व स्पष्ट है क्योंकि प्रत्येक विकासखन्ड मे 80 से 88 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टयर या उससे भी छोटी है ।

उपर्युक्त सामाजिक व आर्थिक कारकों के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य मे अगले अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र की विकास विषमताओं का निरूपण किया गया है ।

REFERENCES

1. Chandna R C and Manjit S (1980), Introduction to Population Geography, Concept New Delhi, p. 96

2. Clark, J I. (1972), Population Geography, Second Edition, Oxford and New York Pergamon

3. Davis, K (1952), The Population of India and Pakistan, New Jersey Princeton

4. Enyedi, G Y (1964) Geographical Types of Agriculture, Applied Geography in Hungary, Budapest

5. Jones, H R (1981), A Population Geography, London and New York Harper and Row

6. Kishore, R. (1987) Micro Level Planning of Musafir Khana Tahsil, District Sultanpur, U.P unpublished Ph D. Dissertation University of Allahabad.

7. Misra, H.N (1990), Tertiarization of Indian Towns . A Study of the Process of Urban Growth in a Developing Region, Proceedings of the I.G.U Commission on Urban Geography, China.

8. Misra, H.N (1984), Urban System of a Developing Economy, Allahabad . I.I.D.R. and also in 1988 New Delhi : Heritage Publishers

9 Nevill, H.R (1904), Pratapgarh District Gazetteer, Allahabad Government Press.

10 Ramchandran, H (1980), Village Cluster and Development, New Delhi Concept

11 Raza, Moonis (1981), Urbanization and National Development in Honzo M (edit), Urbanization and National Development, Singapore Maruzen Asia.

12 Shafi, M. (1960), Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh, Economic Geography, vol. 19, No 36, No 4, pp 296-305

13 Shafi, M. (1972), Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plains, The Geographers, vol. 19, No. 1, pp. 4-13.

14 Stamp, L.D. (1962), The Land of Britain : Its use and Misuse IIIrd Edition London Longmans.

अध्याय 6

विकास विषमता प्रतिरूप

विगत अध्याय मे अधिवासों मे होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों को अध्ययन क्षेत्र मे होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है । अध्ययन क्षेत्र मे होने वाले परिवर्तनों से स्थानिक विकास विषमता उद्भूत हुई है । प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के स्थानिक विकास विषमता के प्रतिरूप का अध्ययन किया गया है ।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

सामाजिक - आर्थिक विकास की प्रक्रिया सर्वत्र समान नहीं होती है । अत स्थानिक, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर विकास की विषमता बढती जाती है । ये विशेषताये ग्राम व नगरीय स्तर पर भी दिखायी पडती है । विषमताओं की मापने के कई सूचकाक समय समय पर प्रयोग मे लाये गये है तथा विषमता के प्रतिरूप को स्पष्ट करने के लिये भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है । अर्थशास्त्रियों ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की व्याख्या भी की है । विकास विषमता प्रतिरूप को विभिन्न सिद्धान्तों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमे कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय (इन्दु मिश्रा, 1991) है । अत इन माडलों के मूल तत्वों को सक्षेप मे यहॉ प्रस्तुत करना समीचीन होगा ।

रस्टो का आर्थिक विकास सिद्धान्त रस्टो महोदय का सिद्धान्त, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1955 मे किया था (कीबुल 1967) मुख्य रूप से नवीनताओं पर बल देता है । यह माडल प्रादेशिक विषमताओं को स्पष्ट करने के साथ ही एक प्रदेश मे समय के अन्तराल पर बढती हुई सम्पन्नता मे परिवर्तनों का विश्लेषण करता है । रस्टो ने आर्थिक विकास को पॉच अवस्थाओं मे विभक्त किया है (चित्र सख्या 6 ।)
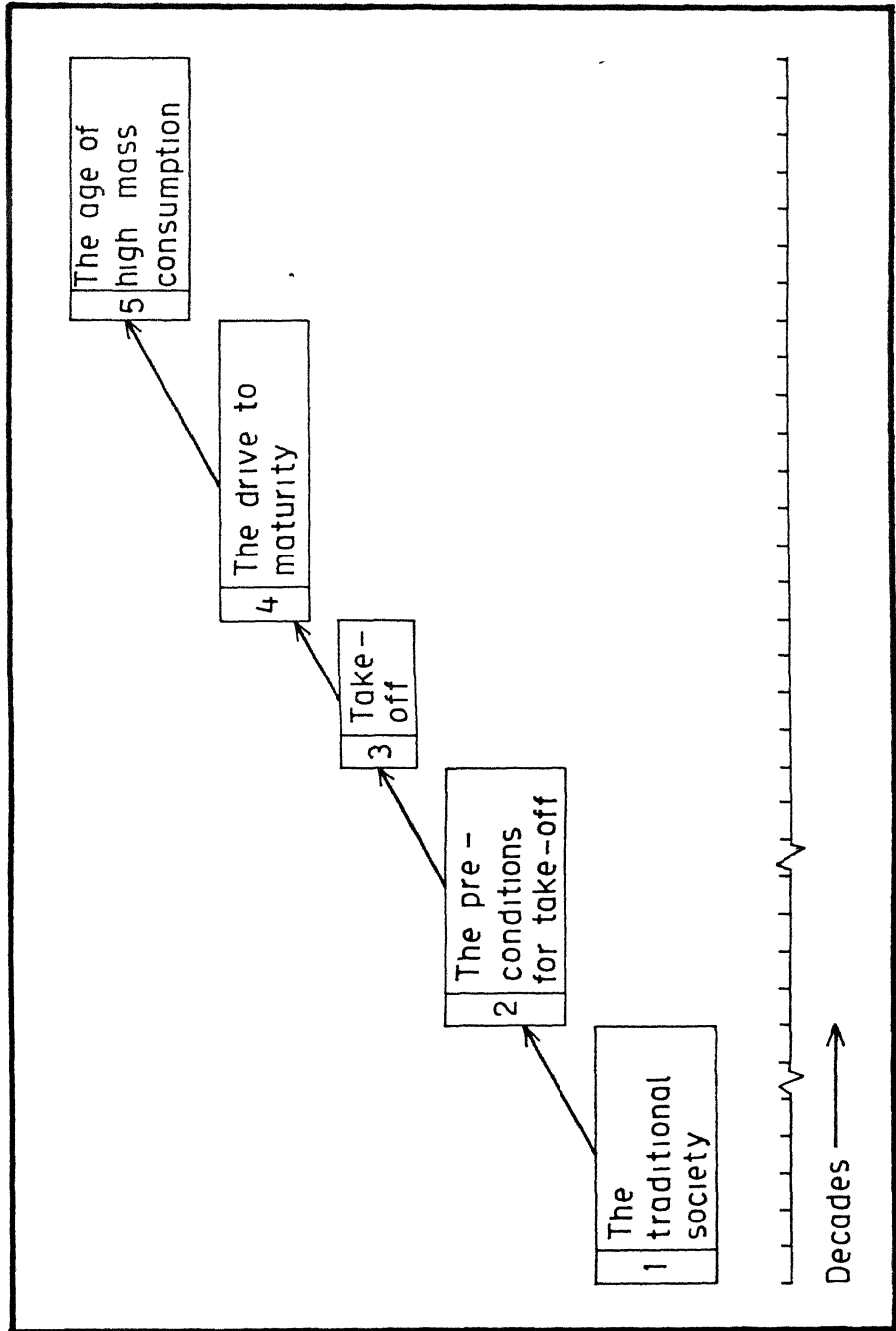
THE ROSTOW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
(From R J Chorley and P Haggett, Models in Geography, Methuen)

Fig 6.1

1 प्रथम अवस्था मे एक रूढिवादी समाज की कल्पना की गई है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और वह भी जीविका निर्वाह स्तर पर । सम्भावित ससाधनों का पता नहीं लग पाया है ।

2 द्वितीय अवस्था वह अवस्था है जिसमे आर्थिक वृद्धि तेजी से प्रारम्भ हो जाती है । व्यापार का विस्तार होता है और वाहृय प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीको के साथ - साथ आधुनिक विधियों का भी श्रीगणेश हो जाता है ।

3 तृतीय अवस्था "टेक आफ" अथवा ऊपर उठने की अवस्था है । प्राचीन परम्पराये पूरी तौर पर नवीन परम्पराओं से आच्छादित हो जाती है और आधुनिक औद्योगिक -समाज का जन्म हो जाता है । अनेक औद्योगिक इकाइयॉ उद्‌भूत हो जाती है तथा राजनैतिक एव सामाजिक सस्थाये परिवर्तित होने लगती है और स्वय - पोषी वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है ।

4 चतुर्थ अवस्था मे औद्योगिक समाज का सुसगठन हो जाता है । पूँजी का न्यास बढने लगता है । जैसे - जैसे नई इकाइयॉ विकसित हो जाती है, कुछ औद्योगिक इकाइयॉ समाप्त हो जाती है ।

मिरडल का क्युमुलेटिव कांजेशन माडल मिरडल महोदय ने 1956 मे "क्युमुलेटिव कोजेशन माडल" प्रस्तुत किया (चित्र सख्या 6 2) । इनके अनुसार प्रादेशिक विषमताये आर्थिक विकास का अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम है । विपणन शक्ति इस विषमता को प्रभावित करती है । एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को बिना हानि पहुँचाये कभी भी विकसित नहीं हो सकता । जैसा कि

चित्र से स्पष्ट है, मुख्य रूप से आर्थिक उन्नति उन स्थानों पर होती है जहाँ पर कि कच्चा माल और शक्ति के साधन सरलता से उत्पन्न होते है । एक बार जब विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तो वहाँ पर सचयी कारक कार्य करने लगते है । केन्द्रोपसारित बल तथा गुणक प्रभाव भी कार्य करने लगते है जिसके फलस्वरूप विकासशील औद्योगिक इकाइयाँ द्वितीयक औद्योगिक इकाइयों को जन्म देने लगती है । सामाजिक इकाइयाँ इस प्रक्रिया को सम्बल प्रदान करती है । इस श्रखला क्रम तथा प्रक्रिया के फलस्वरूप स्वयपोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है । निर्धन क्षेत्रों से केन्द्रीय प्रदेशों की ओर ससाधनों के आकर्षण को मिरडल ने "बैकवाश इफेक्ट" की सज्ञा दी तथा अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फेलने वाले सम्भावित विकास को उन्होंने "स्प्रेड इफैक्ट" की सज्ञा दी । इस प्रकार उन्होंने तीन स्थितियों का वर्गीकरण किया है

1 प्राथमिक औद्योगिक स्थिति जब कि प्रादेशिक विषमताये न्यूनतम होती है ।

2 द्वितीय स्थिति जिसके अन्तर्गत सचयी कारक सर्वोत्कृष्ट होते है एव एक प्रदेश विशेष अन्य प्रदेश की तुलना मे आगे बढ रहा है । इस स्थिति मे ससाधनों के वितरण मे असन्तुलन बढने लगता है ।

3 तृतीय स्थिति वह है जिसमे कि निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताये कम होने लगती है ।

मिरडल महोदय के इस माडल की कटु आलोचना हुई है क्योंकि यह बहुत ही अधिक गुणात्मक और वास्तविकता से परे है । किन्तु फिर भी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के

अन्तर को स्पष्ट करने मे इस माडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है (कीबुल, 1967) ।

फ्रीडमैन का केन्द्र सीमान्त माडल - यह माडल विकास विषमता प्रतिरूप तथा उनके कारणों का भी संक्षिप्त उल्लेख करता है । इनके अनुसार विश्व को गतिशील प्रदेश, द्रुतगति मे बढने वाले अथवा स्थानिक प्रदेशों मे विभाजित किया जा सकता है । इस प्रतिरूप के अन्तर्गत पाच विशिष्ट कटिबन्ध देखे जा सकते है (फ्रीडमैन, 1966)

1 केन्द्र प्रदेश यह वह भाग है जहाँ पर कि नगरीय औद्योगिकरण, उच्च स्तरीय तकनीक, विविध ससाधन, श्रम तथा जटिल आर्थिक सरचना एव उच्च वृद्धि पर केन्द्रित है ।

2 अग्रोन्मुख मध्यम प्रदेश यह वह प्रदेश है जो केन्द्र क चारों ओर परिधि के रूप मे फैला हुआ है और केन्द्र से प्रभावित है । इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर ससाधनों का बहुतायात से उपयोग हो रहा है । जनसख्या प्रवासित हो रही है और आर्थिक वृद्धि अचर है ।

3 साधन सम्पन्न सीमान्त प्रदेश यह वह भाग है जहाँ पर कि नये अधिवास विकसित हुये है तथा वृद्धि की सम्भावना है । नये खनिज ससाधनों का विकास और शोषण प्रारम्भ है ।

4 निम्नोन्मुख प्रदेश यह केन्द्र से दूर अतिम सीमा वाले प्रदेश है जहाँ पर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षीणकाय है तथा कृषि का उत्पादन न्यूनतम है । यहाँ पर प्राथमिक

ससाधन पूर्णतौर पर समाप्त हो गये है । फ्रीडमैन के अनुसार विश्व की विषमता का यहीं दृश्य है । बृहद नगरीय प्रदेश विकसित होने लगते है तथा यातायात की सुविधा और जटिल होने लगती है ।

5 पचम अवस्था मे उपर्युक्त चतुर्थ अवस्था की परिस्थितियाँ चरम सीमा पर होती है । उत्पादन की प्रचुरता बढ जाती है एव व्यवसाय मे तकनीकी व्यवसाय की वृद्धि होने लगती है, भौतिक सुख - सुविधा की वृद्धि के साथ ससाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण के कार्य मे होने लगता है ।

यह सिद्धान्त पूजी निर्माण की विधि की व्यवस्था तो करता है, किन्तु इन पाचों अवस्थाओं मे सम्बध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं करता । किन्तु फिर भी यह स्पष्ट है, और विकसित देशों के विश्लेषण मे बहुत अर्थयुक्त है । विकासोन्मुख देशों मे क्या यही प्रक्रिया कार्य करती है यह विचारणीय प्रश्न है । निश्चित रूप से तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत ही आते है (हैमन्ड, 1982) ।

ध्रुव /केन्द्र विकास सिद्धान्त अधिवास तत्र एव विकास मे अन्योन्याश्रित सम्बध है । इसी पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखकर विकास केन्द्र सकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ है । यद्यपि इस सकल्पना की कठोर आलोचना हुयी है । किन्तु फिर भी तृतीय विश्व के विकास की विचारधारा मे आज के सन्दर्भ मे विकास केन्द्र सकल्पना सबसे महत्वपूर्ण एव शक्तिशाली सकल्पना है । पेराउक्स महोदय (1955) द्वारा प्रतिपादित विकास ध्रुव विकास सिद्धान्त मुख्य रूप से आर्थिक सिद्धान्त है और अस्थानिक है । किन्तु सन् 1966 मे वोडविली ने इस

सकल्पना का न केवल अनुवाद किया अपितु भौगोलिक सकल्पना के रूप मे प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया । कालान्तर मे इस विचारधारा को नियोजकों मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला । भारतवर्ष जैसे देशों मे तो इसे एक वैचारिक दर्शन और क्रियात्मक भूमिका के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध मे अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसमे जानसन (1970), आर0 पी0 मिश्रा (1978), हरमनसन (1971), कुर्कलिन्सकी (1971), मोसली (1974) इत्यादि के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस सिद्धान्त की मुख्य विचारधारा यह है कि विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से ही विकास सम्भव है । यदि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र मे विकासकेन्द्र होंगे तो अपने द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक सुविधाओं के द्वारा आस पास के क्षेत्रों को विकसित करने मे महत्वपूर्ण योगदान करेगे । अन्तर - प्रादेशिक एव ग्रामीण - नगरीय विषमता को दूर करने मे इस सिद्धान्त को अनेक भूगोल वेत्ताओं ने बिल्कुल रामबाण के रूप मे प्रस्तुत किया है ।

ऐसा समझा जाता है कि विकास केन्द्र, बाजार केन्द्र का पदानुक्रम मिलकर विकास की एक ऐसी श्रृखला उत्पन्न करेगा जिससे कि प्रादेशिक विकास को गति मिलेगी (मिश्रा, 1984) । किन्तु इस सिद्धान्त की कटु आलोचना हुई । विभिन्न सतर पर अधिवास केन्द्रों की स्थापना मे लगने वाला धन कहाँ से मिलेगा ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह भी मूल प्रश्न है कि यदि इस प्रकार के केन्द्रों की आवश्यकता है तो वह स्वय क्यों उत्पन्न नहीं होंगे । अधिवासों का विकास प्रादेशिक, आर्थिक, सामाजिक एव राजनैतिक सरचना पर आधारित है, और जब तक उस प्रदेश मे रहने वाली जनसख्या की आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं होगी कि वह इन केन्द्रों मे स्थित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आश्रय दे सके, इस प्रकार के सेवाकेन्द्र

कभी भी विकसित नहीं होंगे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के केन्द्रों की उत्पत्ति एव विकास माग और आपूर्ति पर आधारित है । इसके अतिरिक्त विकास ध्रुव सिद्धान्त "टाप-टाऊन माडल" को प्रश्रय देता है जिसमे विकास की सकल्पना ऊपर से नीचे की ओर की गयी है ।

विकास केन्द्र से मिलती जुलती कई अन्य सकल्पनाये भी है जिनमे कि छोटे एव मध्यम श्रेणी के नगर पर आधारित विकास तथा झुरमुट अथवा एग्रोपालिटन सकल्पनाये मुख्य है । छोटे एव मध्यम श्रेणी के नगरों के विकास के सदर्भ मे दत्ता (1981), राडनेली (1983), तथा मिश्रा (1936) के कार्य उल्लेखनीय है । इस सकल्पना के अनुसार प्रादेशिक विकास के लिये बडे नगरों की तुलना मे छोटे नगरों का विकास यदि किया जाय तो विकास की गति मध्यम तीव्र होगी ।

ग्रामीण झुरमुट अथवा एग्रोपालिटन सकल्पना का विकास फ्रीडमैन तथा डगलाश (1976) एव रामचन्द्रन (1980) ने प्रस्तुत किया । यह सकल्पना स्टूर एव टेलर (1980) के अनुसार "बाटम - अप रणनीति" है जिसमे यह सकल्पना की गयी है कि विकास का विकेन्द्रीकरण लघुस्तर पर आवश्यक है और यह इसी रणनीति के अन्तर्गत सम्भव है ।

सीमाकन सूचकांक एव विधियाँ

इन माडलों का मुख्य उद्देश्य विकसित, अर्द्धविकसित, विकासशील तथा पिछडे हुये प्रदेशों मे व्याप्त एव उत्तरदायी प्रक्रियाओं को विश्लेषित करना है । सन् 1970 के आसपास जब भूगोल मे समाज कल्याण एव क्षेम सम्बन्धी आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ तो भूगोलविदों ने विषमता प्रतिरूप को सीमांकित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया । इनमे ड्रेवनासकी (1970), हार्वे

(1972), स्लेटर (1975), स्मिथ (1977, 1979), स्टूर एव टाड (1977) का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सन् 1961 की जनगणना से प्राप्त आँकडों के आधार पर अशोक मित्रा (1965) ने सर्वप्रथम जनपद स्तर पर विकास को नापने का प्रयत्न किया । नाथ (1979) ने प्रान्तीय स्तर पर प्रादेशिक विभेद शीलता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । राव (1973) ने सन् 1960 एव 1970 के मध्य उत्पन्न हुई विषमता का नापने का सफल प्रयोग किया है । सुन्दरम् (1983) ने भी भारतवर्ष मे जनपद स्तर पर विकास की विभेद-शीलता प्रदर्शित कर विकसित, विकासशील एव पिछडे क्षेत्रों को सीमाकित किया । इस प्रकार का प्रयत्न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूण नहीं है । अपितु योजना की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे क्षेत्र जो कि विकास की प्रतीक्षा कर रहे है, उन्हे सीमाकित कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है ।

सीमाकन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है । इसमे साधारणतम तकनीक से लेकर अत्यन्त उच्च स्तरीय विधियों का प्रयोग किया गया है । सामान्य रैंकिग, "जी स्कोर", सामूहिक सूचकाक तथा प्रिन्सिपल कम्पोनन्ट विधिया प्रमुख है । विभिन्न विधियो के साथ साथ विविध प्रकार के चरों का भी प्रयोग किया गया है । सामान्यत एक से अधिक चर प्रयोग मे लाये गये है । चरों का चुनाव समय समय पर बदलता रहा है । प्रारम्भ मे "बाल मृत्युदर" को ही विकास का सूचक माना जाता था । यदि मृत्युदर अधिक है तो विकास कम है और यदि कम है तो देश अधिक विकसित है । सयुक्त राष्ट्र सघ ने "जीवन स्तर" को महत्वपूर्ण सूचकाक के रूप मे विकसित किया । जीवन स्तर को एक सामूहिक सूचकाक के रूप मे विकसित किया गया जिसमे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, व्यवसाय की

स्थिति, यातायात की सुविधा, उपभोग एव बचत, आवास, वस्त्र, आमोद - प्रमोद के अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव की स्वतत्रता जैसे आयाम सम्मिलित थ । वास्तविकता यह है कि विकसित तथा अविकसित अवस्थाओं के मध्य कई स्थितिया है जिनका निरूपण पूर्णरूपेण सम्भव नहीं है । विकास की स्थिति कई आयामों स प्रभावित होती है जो आर्थिक, जनांकिक, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी है । कुछ विद्वानों ने महिला शिक्षा, रोजगार के अवसर, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध पय जल की उपलब्धता और आवास की स्थिति को सम्मिलित कर विकास का विषमता प्रतिरूप मापने का प्रयास किया है । विकास का व्यक्तित्व बहुआयामी है और इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में विकास विषमता मापन

अध्ययन क्षेत्र मे सामाजिक - आर्थिक विकास की विभेद शीलता को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्‌देश्य उसे **विकसित** अर्द्धविकसित, विकासशील एव अविकसित वर्गो मे विभक्त करना है । पस्तुत अध्ययन मे कुल 21 चरों का चुनाव किया गया है । यह चर अधोलिखित है

1 जनसख्या का घनत्व, 1981

2 लिग अनुपात वर्ष, 1981

3 जनसख्या वृद्धि, 1971-81

4 साक्षरता प्रतिशत, 1981

5 कर्मकारों का प्रतिशत, 1981

6 अकर्मकारों का प्रतिशत, 1981

7 नगरीय जनसख्या का प्रतिशत, 1981

8 सडक का घनत्व प्रति 1000 जनसख्या, 1986-87

9 सडक से जुडे गावों का प्रतिशत, 1986-87

10 विद्युतीकृत गावों का प्रतिशत, 1986-87

11 कृषि याग्य भूमि का प्रतिशत, 1986-87

12 मुद्रादायिनी फसलों का प्रतिशत, 1986-87

13 फसलगहनता का प्रतिशत, 1986-87

14 शुद्ध सिचित क्षेत्र का प्रतिशत, 1986-87

15 प्रति हैक्टेयर पर रासायनिक खाद का उपयोग कि0 ग्रा0, 1986-86

16 प्रति व्यक्ति उत्पादन कि0 ग्रा0, 1986-87

17 प्रति व्यक्ति भूमि का उपयोग हे0, 1986-87

18 प्रति हजार जनसख्या पर जू0 बे0 स्कूल, 1986-87

19 प्रति हजार जनसख्या पर डाकघर, 1986-87

20 प्रति हजार जनसख्या पर बाजार, 1986-87

21 प्रति हजार जनसख्या पर अस्पताल, 1986-87

इन चरों का सह-सम्बन्ध विकास खड स्तर पर कम्प्यूटर पर एस पी एस एस प्रोग्राम की सहायता से ज्ञात किया गया है । वह सह-सम्बन्ध (सारिणी सख्या 6 1) रेखाकित किये गये है जिनका सिगनिफिकेट लेवेल 99 प्रतिशत है । इसको ज्ञात करने के लिये टी - टेस्ट का उपयोग किया गया है, जिसका सूत्र इस प्रकार है

इस सूत्र से यह प्रतीत होता है कि कुल ऐसे 20 सह-सम्बन्ध है जो 99 प्रतिशत "कानाफडेन्स लिमिट" पर "सिगनिफिकेंट" है । इन 20 सह-सम्बन्ध से अधोलिखित निष्कर्ष निकलते है

(1) जनसख्या के घनत्व तथा प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि तथा प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि मे धनात्मक सह-सम्बन्ध (0 83) है । किन्तु प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन एव जनसख्या घनत्व मे ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (66) है । स्पष्ट है कि जनसख्या घनत्व एव खाद्यान्न आपूर्ति मे अन्तर है ।

(2) लिग अनुपात तथा सडक के घनत्व मे ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है जिससे सपष्ट होता है कि नगरीय अधिवासों की तुलना मे ग्रामीण भाग मे सडकों का समुचित विकास नहीं हुआ है ।

(3) जनसख्या वृद्धि तथा विद्युतीकृत गावों के प्रतिशत मे नकारात्मक सह-सम्बनध (70) है । ठीक इसी प्रकार जनसख्या वृद्धि एव प्रति हैक्टेयर उर्वरक के उपयोग मे भी नकारात्मक (66) सह-सम्बन्ध है । इससे स्पष्ट है कि जनसख्या का अधिकाश भाग कृषि के आधुनिकीकरण पर बल नहीं देता है ।

(4) जनसख्या की वृद्धि एव सिंचित भूमि का धनात्मक (72) सह-सम्बन्ध इस बात का द्योतक है कि कृषि मे सिचाई साधनों का उपयोग बढ रहा है ।

(5) साक्षरता तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे लगी जनसख्या प्रतिशत का सह-सम्बन्ध धनात्मक (64) है । यह इस बात का सूचक है कि साक्षरता वृद्धि के साथ जनसख्या का प्रवास होने लगता है और साथ ही साथ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे लगी जनसख्या का अनुपात बढने लगता है । यह मुख्य रूप से तृतीयक (टरशियरी) प्रकार के व्यवसाय की वृद्धि का द्योतक है । साक्षरता प्रतिशत तथा सडक के घनत्व मे धनात्मक (65) सह-सम्बन्ध है । **इससे यह प्रतीत होता है कि नगरीय आवासों का सडक यातायात, ग्रामीण अधिवासों के यातायात की अपेक्षाकृत अच्छा है । यह निष्कर्ष सख्या 2 का पूरक है ।**

(6) यह महत्वपूर्ण है कि साक्षर जनसख्या और प्रति हैक्टेयर उर्वरक के प्रयोग मे धनात्मक (75) सह-सम्बन्ध है । साक्षर किसान **ही** कृषि आधुनिकीकरण मे विश्वास **रखते** है । इससे जुडा हुआ महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि साक्षरता और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि मे नकारात्मक (75) सह-सम्बन्ध है ।

(7) प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन और साक्षरता मे नकारात्मक (85) सह-सम्बन्ध है ।

(8) कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों मे लगी कार्यशील जनसख्या तथा प्रति व्यक्ति कृषिकृत भूमि (63) के मध्य नकारात्मक सह-सम्बन्ध है यह अपने आप मे स्पष्ट है ।

(9) नगरीय जनसख्या तथा सडक यातायात के मध्य सह -सम्बन्ध (76) महत्वपूर्ण है ।

(10) ऐसा प्रतीत होता है कि नगरीय जनसख्या उर्वरक के प्रयोग मे आगे है क्योंकि इनके दोनों के बीच का सह - सम्बन्ध धनात्मक (88) है । आधुनिकीकरण एव नगरीकरण की यह प्रक्रिया सडक घनत्व तथा प्रति हैक्टेयर उर्वरक उपयोग से पुन स्पष्ट होती है क्योंकि इसके बीच का सह-सम्बन्ध 63 है ।

(11) फसलगहनता तथा सिंचित कृषि भूमि का धनात्मक सह-सम्बन्ध (87) है । यह इस बात का द्योतक है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है । जैसे जैसे सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढता है वैसे वैसे फसल गहनता बढती जाती है ।

(12) प्रति हैक्टेयर उर्वरक का उपयोग तथा प्रति **व्यक्ति कृषिकृत भूमि एव प्रति व्यक्ति खाद्यान्न** उत्पादन मे धनात्मक सम्बन्ध है । इनका सह-सम्बनध क्रमश 65 तथा 63 है। प्रति व्यक्ति कृषि **भूमि** एव **प्रति** व्यक्ति **खाद्यान्न उत्पादन का सह-संबध 87 है ।**

(13) प्रति एक हजार जनसख्या पर स्कूल तथा जनसख्या का सम्बन्ध ऋणात्मक (69) है । **इससे स्पष्ट है कि शिक्षण सस्थाओं** एव जनसख्या वितरण मे उचित तालमेल नहीं है ।

विकास वितरण प्रतिरूप

उपर्युक्त चरों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न विकास खन्डों को उनके विकास स्तर

क आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है । यह वर्गीकरण नियोजन मे सहायक सिद्ध हो सकता है । तथा कम विकसित अथवा अर्धविकसित विकास खन्डों को निर्धारित कर वहाँ विशेष योजनाये चला कर उनको एक निश्चित स्तर पर लाया जा सकता है । विकास स्तर को निर्धारित करने के लिये उपर्युक्त 21 चरों को "लीनियर माडल" के आधार पर "जी स्कोर" का प्रयोग कर कुल स्कोर क आधार पर विकास का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है । "जी" स्कोर का सूत्र इस प्रकार है

"जी स्कोर" के योग के आधार पर विकास खन्डों को 4 वर्गो मे विभाजित किया गया है

1 अविकसित विकास खन्ड (0-15) इस वर्ग के अन्तर्गत मगरोरा एव गौरा विकास खन्ड है जिनका सूचकाक 0-15 के बीच है । ये ऐसे विकास खन्ड है जहाँ विकास गति धीमी है तथा सुविधाओं का अभाव है ।

2 विकासशील विकास खन्ड (15-20) इस वर्ग के अन्तर्गत आसपुर देवसरा, सागीपुर, बिहार, शिवगढ, बाबागज, लड्वा चन्द्रिका, मानधाता एव कालाकांकर विकास खन्ड आते है । इनका विकास सूचकाक 15 से 20 के बीच है । इन विकास खन्डों मे भी सामाजिक-आर्थिक तत्र एव सुविधाये अपेक्षाकृत अविकसित है ।

3 मध्यम स्तरीय विकास खन्ड (20 से 25) इसके अन्तर्गत लक्ष्मणपुर, कुन्डा, रामपुर एव पट्टी विकास खन्ड स्थित है । इन विकास खन्डों मे सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं का वितरण अपक्षाकृत ठीक है । इन विकास खन्डों मे विकास की गति तीव्र होने के कारण यहाँ पर जीवन स्तर अन्य दो वर्गों की तुलना मे अच्छा है ।

4 उच्च स्तरीय विकास खन्ड (25 से अधिक) इस वर्ग के अन्तर्गत प्रतापगढ विकास खन्ड है जिसमे कि सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं का विवरण सर्वोत्कृष्ट है ।

मानचित्र सख्या 6 3के विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विकास मुख्य रूप से अध्ययन क्षेत्र के केन्द्रीय भाग मे केन्द्रित है । इसमे प्रतापगढ विकास खन्ड मुख्य है । सम्भवतया प्रतापगढ नगर की स्थित ने विकास को केन्द्र भाग मे ही अपने **स्थिति** कि चारों ओर सीमित कर रखा है । **कुन्डा एव रामपुर खास विकास खण्ड इसके अपवाद है ।** किन्तु सामान्यतया केन्द्र की तुलना मे सीमान्त क्षेत्रों मे विकास गति धीमी है । योजनाबद्ध विकास मे इस तथ्य को ध्यान मे रखना होगा और केन्द्र से सीमान्त प्रदेश की ओर विकास के आयाम को गति देने के लिये नीति स्तर पर प्रयास करना होगा ।

REFERENCE

1. Drewnowski, J (1970). **Studies in the Measurement of Levels of living and welfare, U.N.R.I.**

2. Dutta, S.S. (1981). India's Urban future:Role of Small and medium towns, **Jl. of the Institute of Town Planning, India.**

3. Friedmann, J. (1966), The Urban-Regional Frame for National Development International Development Review.

4. Friedmann, J. and Doughloss, (1976) Agropolitan Development Towards a New Strategy for Regional Development in Asia, **Proceedings of the Seminar on Growth Pole Strategy and Regional Development in Asia**, UNCRD Nagoya, 337-387

5. Johnston, E.A.J (1970), **The Organization of Space in Developing Countries**, Cambridge (Mass) : Harvard University Press.

6. Keeble, D. (1967), Models of Economic Development in R.J. Chorley and P. Haggett (1967), **Models in Geography**, London : Methuen.

7. Kuklinski, A. and R. Petrella (eds) (1971) **Growth and Regional Policies** the Hague : Mouton

8. Hammond, C.W. (1982), Elements of Human **Geography**, London

: George Allen & Unwin.,

9. Harvey, D. (1972). Social Justice and the City, London : Edward Arnold.

10. Harvey, D. (1972), Limits to capital, London : Basil Blackwell.

11 Harmensen, Tormod (1971), Spational Organization and Economic Development Mysore : Int. of Dev. Studies.

12 Nath, V. (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual number, (January)

13. Misra, H.N. (1984) Urban System of a Developing Economy, Allahabad : I.I.D R.

14. Mitra, A. (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi : Government of India.

15 Misra, H.N. (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed) Small and Intermediate urban centres : Their role in national and regional development in the third world, London: Hodder and Stoughton.

16. Misra, Indu (1991), Human settlement system and Regional

. George Allen & Unaih.,

9 Harvey, D. (1972). Social Justice and the City, London : Edward Arnold

10. Harvey, D. (1972), Limits to capital, London : Basil Blackwell.

11 Harmensen, Tormod (1971), Spational Organization and Economic Development Mysore · Int. of Dev Studies.

12. Nath, V. (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual number, (January)

13. Misra, H.N. (1984) Urban System of a Developing Economy, Allahabad : I.I.D.R.

14. Mitra, A. (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi : Government of India.

15 Misra, H.N. (1986), Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, Uttar Pradesh, North India, in Jorge Hardoy et al (ed) Small and Intermediate urban centres : Their role in national and regional development in the third world, London: Hodder and Stoughton.

16. Misra, Indu (1991), Human settlement system and Regional

Development in Allahabad District : The Problems and Policies, D. Phil. Dissertation, Allahabad University.

17. Misra, R.P. et al (1978), Regional Planning and Development, New Delhi : Vikas.

18. Moseley, M.J.A. (1974), Growth Centres in spatial planning, Oxford : Pergman Press.

19. Perroux, F. (1955), La Nation de Croissance Economique Applique Nos. 1 & 2 aş quoted in Misra, R.P. et al 91978) above.

20. Rao, S.K. (1973), A Note on Measuring Economic Distances between Regions of India, Economic and Political Weekly, 28 (April).

21. Ramchandran, H. (1980), Village cluster and Development, New Delhi : Concept.

22. Rondinelli, D.A. (1983), Secondary cities in Developing Countries : Policies for Diffusing urbanization Beverly Hills: Sage Publication.

23. Slater, D. (1975), Underdevelopment and Inequality, Progress in Planning, 4, 97-167

24. Stohr, W. and Todtling, F.(1977), Spatial Equity - Some

Antitheses to Current Regional Development doctrine, Papers of the Regional Science Association, 38, 33-53

25 Smith, D.M (1979), Where the Grass is Greener - Living in an Unequal world, Baltimore :The John Hopkins University Press.

26. Sundaram, K V. (1983), Geography of Under-development, New Delhi Concept

27. Smith, D M (1979), Human Geography : A welfare approach, London · Edward Arnold

28. Stohr, W. and D.R F. Taylor (1980), Development from Above and Below, London . John Wiley

अध्याय 7

निष्कर्ष तथा नीतिपरक संस्तुतियाँ

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य एक लघु-स्तरीय प्रदेश की यथास्थिति पुनार्वलोकन तथा विश्लेषण करना है । इसके लिए एक जनपद का चुनाव किया गया है । यद्यपि कि जनपद एक प्रशासनिक इकाई है, किन्तु सरकारी स्तर पर लघु स्तरीय नियोजन की यह सर्वमान्य इकाई है । शोध की मुख्य आधार भूमि मानव आधिवास तन्त्र का विश्लेषण है क्योंकि मानव अधिवास किसी भी क्षेत्र के कार्यात्मक एव सगठन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और उनके विश्लेषण से उद्भूत निष्कर्ष क्षेत्रीय नियोजन मे महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करते है । प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य लक्ष्य बिन्दु निम्नलिखित है

1 मानव अधिवास तत्र का विश्लेषण करना ।

2 मानव अधिवास के सामाजिक - आर्थिक आधारों के रूपान्तरण मे लगे हुये प्रक्रमों को स्पष्ट करना ।

3 सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण से उद्भूत विकास विषमता के प्रतिरूप का सीमाकन एव विश्लेषण करना ।

4 मानव अधिवास व क्षेत्रीय सगठन सबधी कुछ नीतिपरक सस्तुतियों का उल्लेख करना ।

अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणपूर्व अचल मे स्थित प्रतापगढ जनपद है जो 3730 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर विस्तृत है । प्रमुखतया समतल धरातल वाला यह क्षेत्र अत्यन्त सघन बसा हुआ है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसख्या 18,86,833 थी, जो सन् 1991 मे बढ कर 22,11,253 हो गयी । जनसख्या का घनत्व 1981 और 1991 मे क्रमश 525 व 929 था । जनसख्या का अधिकाश भाग ग्रामीण है जो 2185 गाँवों मे निवास करती है । केवल 7 अधिवास ऐसे है जिन्हे नगरीय अधिवास का दर्जा प्राप्त है । क्षेत्रीय पर्यावरण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मिट्टी, जलवायु, तथा अन्य भौतिक ससाधन, कृषि अर्थव्यवस्था को मूल रूप से बल प्रदान करते है । वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है अथवा वनों का क्षेत्रफल अत्यन्त अल्प (0 1%) है, जो निश्चय ही पर्यावरण के सन्तुलन को

चुनौती दे रहा है । जल ससाधन भी कम है, और जो है, उनका समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाया है । खनिज सम्पत्ति का भी अभाव है । अत भूमि पर और इसलिये मिट्टी पर बोझ बढा है जिससे भू-क्षरण की प्रक्रिया तेज हो चली है ।

•

जनसख्या का अधिकाश भाग 500 - 1000 तथा 1000 - 2000 तक के आबादी के अधिवासों मे आबाद है । उल्लेखनीय है कि छोटे आबादी वाले अधिवासों की सख्या घट रही है । निरन्तर आबादी बढने के कारण छोटे अधिवास बडे अधिवासों के क्रम मे शामिल हो रहे है । उनका स्थानिक वितरण प्रमुख रूप से समान है । जनसख्या एव कार्यो के आधार पर सेवा केन्द्रों का विश्लेषण क्षेत्र मे पदानुक्रम सकल्पना का पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है । किन्तु कोटि - आकार नियम की तुलना मे जेफरसन महोदय का "प्राथमिक नगर सिद्धान्त" अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि बेला प्रतापगढ जो जनपद का मुख्यालय तथा प्रमुख नगरीय इकाई है, का आकार दूसरे क्रम पर स्थित कुण्डा नामक नगरीय इकाई से चार गुना बडा है और उत्तरोत्तर विकास के कारण बढने की यह प्रक्रिया अबोध गति से चल रही है। सेवा केन्द्र स्तर पर उनकी जनसख्या और कार्यात्मक इकाईयों तथा कार्यात्मक प्रकारो के सह - सम्बन्ध का विश्लेषण इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि जनसख्या बढने के साथ - साथ कार्यात्मक इकाईया और कार्यात्मक प्रकारों मे वृद्धि होती है । यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो सामान्य निष्कर्षो से भिन्न प्रतीत होता है और इस बिन्दु पर अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं (कार्यात्मक इकाईयों तथा कार्यात्मक प्रकार) का वितरण किसी नियमित क्रम मे नहीं हुआ है । यही कारण है कि स्थानिक सगठन ढीला है ।

सामाजिक - आर्थिक कारकों के विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे सामाजिक व आर्थिक रूपान्तरण मे गति आई है । चाहे नगरीकरण हो, शिक्षा हो, कृषि हो अथवा अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय हो - बडा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है । परिवर्तन मुख्यतया विकास - नीतियों के फलस्वरूप हुए है । ये नीतिया ग्रामीण विकास, औद्योगिक

कृषि विकास से सम्बन्धित है । इन विकास की नीतियों से उद्‌भूत परिवर्तन से अध्ययन क्षेत्र मे (अन्य क्षेत्रों की भाति) विषमता उत्पन्न हुई है जोकि विकास खण्ड स्तर पर 22 चरों के सह-सम्बन्धों के विश्लेषण एव उनके रैखिक रूपान्तरण से किये गये सीमाकन से स्पष्ट है । किन्तु यहाँ पर भी विकास की प्रक्रिया पुण्जीभूत होने के का स्पष्ट उदाहरण दिखलाई पडता है । अधिकाश विकास केवल बेला प्रतापगढ अथवा सदर विकास खण्ड मे केन्द्रित है और सीमान्त क्षेत्र अब भी विकास की भाग दोड मे काफी पीछे है । केन्द्र सीमान्त परिधि माडल और "विकास केन्द्र माडल" की उपयोगिता को ओर अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र मे देखना होगा ।

इस सम्बन्ध मे अध्ययन क्षेत्र मे विकास की दिशा को गति देने के लिये अधोलिखित बिन्दुओं को नीति स्तर पर देखना होगा ।

1 लघुस्तरीय नियोजन मे अधिवास सबधी नीति का होना परमावश्यक है, क्योंकि वे ही क्षेत्र की स्थानिक व कार्यात्मक सगठन को सम्बल प्रदान करते है । इसके लिए यह आवश्यक है कि यह अधिवास तत्र की सकल्पना के अन्तर्गत हो । जिसका मुख्य उद्‌देश्य अधिवासों मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध की स्थापना करना है ।

   अध्ययन क्षेत्र के अधिवास एव सेवाकेन्द्रों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नीतिपरक अथवा स्वतत्र सेवाओं (कार्यात्मक इकाईयों तथा उनके प्रकार) का वितरण किसी नियम अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं हुआ है । आवश्यकता इस बात की है कि वे सभी अधिवास, जहाँ पर किसी सेवा के लिए मध्यम जनसख्या सीमा अथवा न्यूनतम जनसख्या सीमा उपलब्ध है वहाँ पर उस सेवा को स्थापित किया जाय । अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए जनसख्या सीमा सारिणी सख्या 7 2 मे प्रस्तुत है । नीतिपरक कार्यात्मक इकाईयों के वितरण मे जनसख्या का थ्रेसहोल्ड आधार का कार्य कर सकता है । अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक एक हजार आबादी वाले अधिवासों की सेवाओं के वितरण मे प्राथमिकता दी जाय ।

2 अध्ययन क्षेत्र का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है । धान, गेहू, दालें एव मुद्रादायिनी तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन मे वृद्धि हो रही है, किन्तु फिर भी सिचाई के

साधन, उर्वरक और प्रोन्नत किस्म के बीज को उपलब्ध करा कर कृषि सरचना में महत्त्वपूर्ण एव द्रुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इसके लिये "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध धन का प्रयोग भी किया जा सकता है ।

3 भूमि सुधार सम्बन्धी नियमों का और कडाई से परिपालन आवश्यक है । जोतों की सख्या के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसका वितरण अत्यन्त असमान है । अधिकाश कृषक लघु एव सीमान्त कृषक की श्रेणी के अन्तर्गत आते है । जोतों के वितरण की असमानता को यदि कम करने का उपाय किया जाय तो निश्चय ही विकास विषमता क्षेत्रीय स्तर पर तथा व्यक्तिगत स्तर पर कम हो जायेगी तथा प्रति व्यक्ति आय के साधन और अधिक सुरक्षित हो जायेगे ।

4 लघु, मध्यम एव वृहत्त औद्योगिक इकाईयों के अध्ययन (सारिणी सख्या 7 ।) से स्पष्ट है कि इनका विकास खण्ड स्तर पर वितरण अत्यन्त असमान है । सदर विकास खण्ड इस दृष्टि से अधिक लाभान्वित हुआ है । इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक विकास खण्ड मे कम से कम एक मध्यम इकाई वाला उद्योग तथा स्थानीय ससाधनों पर आधारित लघु औद्योगिक इकाई के केन्द्र स्थापित किये जाये । इससे जहाँ एक ओर व्यावसायिक सरचना मे परिवर्तन होगा, वहीं पर दूसरी ओर शिक्षित बेरोजगार युवकों का नगरीय केन्द्रों की ओर प्रवर्जन रूकेगा । यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र जनसख्या प्रवास का बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है क्योंकि रोजगार के अवसर बहुत कम है

5 यह भी आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक गाव मे सुदृढ "ग्रामीण विकास परिषद" की नियमित स्थापना की जाय । वर्तमान इकाईया बहुत क्रियाशी नहीं दिखाई पडती । यह ग्रामीण परिषद गावों के विकास मे सक्रिय सहयोग कर सकती है

सारिणी स0 7 । जनपद मे विकास खण्डवार औद्योगिक इकाईयाँ

विकास खण्ड का नाम	1979-80				1984-85			
	वृहत उद्योग		लघु उद्योग		वृहत उद्योग		लघु उद्योग	
	संख्या	व्यक्ति	संख्या	व्यक्ति	स0	व्य0	स0	व्य0
सदर	-	-	26	98	2	723	47	151
लक्ष्मणपुर	-	-	1	3	-	-	12	42
मान्धाता	-	-	2	7			07	24
सं0 चन्द्रिका	-	-	2	7			09	30
सांगीपुर	-	-	2	6			12	38
कुण्डा	-	-	18	65			08	38
कालाकांकर			06	20			11	44
बाबागंज			02	07			17	71
बिहार			01	03			09	33
रामपुरखास			06	21			08	29
पट्टी			12	40			24	91
गौरा			05	17			14	67
शिवगढ़			10	36			22	77
मगरौरा			02	07			03	39
आसपुर देवसरा			04	14			07	25
ग्रामीण योग	-		99	351	2	723	210	799
नगरीय	4	126	86	308	4	107	147	598
जनपद	4	126	185	659	6	830	357	1397

सारिणी सख्या 7.2 प्रतापगढ जनपद के अधिवासों में पायी जाने वाली सेवाओं मे मध्यम जनसख्या सीमा

क्रम सख्या	सेवाये	मध्यम जनसख्या सीमा
01	प्राइमरी स्कूल	962
02	जूनियर हाईस्कूल	2529
03	हाईस्कूल	1120
04	इन्टर कालेज	1512
05	डिग्री कालेज	2663
06	चिकित्सालय	1114
07	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1027
08	परिवार कल्याण केन्द्र	1031
09	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1150
10	औषधालय	1031
11	डाकघर	1027
12	तारघर	1292
13	बस स्टेशन	1027
14	बैंक	3157
15	बाजार	1027
16	पुलिस स्टेशन	1848

स्रोत परिकलित

6 आकडों की कमी के कारण पर्याप्त एव आवश्यक सूचना सामग्री उनुपलब्ध है । प्रत्येक विकास खण्ड मे "डेटा बैंक " बनाने की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अत ये कार्य भी नीति के अन्तर्गत किया जाना चाहिये ।

यह टी कुछ महत्वपूर्ण सदर्भ है, किन्तु यह पूर्ण नहीं है । इस दिशा मे ओर अधिक शोध की आवश्यकता है ।

SELECTED BIBLIOGRAPHY

1. Ackerman, Edward A (1958), Geography as a Fundamental Research Discipline, University of Chicago, Department of Geography research paper No 53

2. Ahmad, E (1952), Rural Settlement Types in Uttar Pradesh, A.A.A.G. Vol. 42

3. Ahmad, E (1953) Village Survey, Ind. Geog. Jl, Vol 28 No. 182.

4 Ahmad, E (1962) Indian Village Patterns, Geog. Outlook, Vol 3, No. 1.

5 Ahmad, E (1976), Some Aspects of Indian Geography, Allahabad . Central Book Depot.

6 Alam, S.M. (1965), Hyderabad-Secunderabad : A study in Urban Geography, Bombay Allied publishers

7 Alam, S.M. (1972), Metropolitan Hyderabad and Its region : A strategy for development, New Delhi : Allied Publishers.

8. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L., (1958), A note on Central Place Theory and the Range of a good, Economic Geography, Vol. 34, PP 304-11.

9. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L. (1958), The Functional Bases of the Central Place Hierarchy, Economic Geography, Vol. 34, PP 145-54.

10. Berry, B.J.L. (1967), Geography of Market Centres and Retail Distribution, Englewood Chiffs : Prentice - Hall.

11. Berry, B.J.L. (1973), The Human Consequences of Urbanization London · Macmillan.

12. Bhagat, Bibhe 91982), Spatial System of Class II Towns of U.P., D.Phil Dissertation (Unpublished), Allahabad University.

13. Boudeville, T.R., (1966), <u>Problems of Regional Economic Planning</u> Edinburgh University Press.

14. Beguin, H., (1979), Urban Hierarchy and the Rank-Size Distribution, <u>Geographical Analysis</u>, 2

15. Bennett, R.J. (1981), <u>Quantitatine Geography and Public Policy</u>, London Routledge & Kegan paul.

16. Bhat, L.S. et al. 91976) Micro Planning A case study of karnal area, Haryana · R.B. Publications

17. Bhoosan, B.S. (1981), <u>Towards Alternative Settlement Policy</u>, New Delhi : Heritage-

18. Breese, G. (1963), Urban Development Problems in India, <u>A.A.A.G.</u>, 53, 253-265.

19. Brush, J E (1953), The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, <u>Geog. Rev</u>. 43, 380-402

20. Brush, J E. and Bracey, H.E. (1955), Rural Services Centres in South Western Wisconsin and Southern England, <u>Geog. Rev</u>. 45, 559-69.

21. Christraller, W. (1966), <u>Central Places in Southern Germany</u> (Translated by C.W. Baskin) New Jersey : Engle wood cliffs.

22. Chisholm, M. and Manners, G. (eds) (1973), **Spatial Policy Problems of the British Economy**, London Cambridge University Press.

23 Clark, J.I., **Population Geography** Second Edition, Oxford and New York Pergamon

24. Comeron, G. and Wingo L. eds (1970), **Cities and Regions**, Edinburgh Oliver and Boyd

25. Davis, Kingsley (1973), Cities, Their Origin, Growth and Human Impact, **Readings from Scientific American**, San Francisco W.H. Freeman.

26. Dickinson, R.E. (1932), The Distribution and Function of the Smaller Urban Settlements of East Anglia, **Geography**, 17, 19-31.

27 Drewnowski, J. (1970), **Studies in the Measurement of Levels of living and welfare, UNRI**.

28. Drewnowski, J (1974), **On Measuring and Planning the Quality of Life**, The Hague . Monton.

29. Davis K. (1951), **The Population of India and Pakistan**, New Jersey : Princeton

30. Dacey, M.F. (1962), Analysis of central place and Point Patterns by a Nearest Neighbour method, Lund studies in Geography, Series B, **Human Geography**, 24, 55-75.

31. Dacey, M.F. (1966), Population of Places in a Central place Hierarchy, **J. of Reg. Science**, 6, pp. 27-33.

32. Dutta, S S. (1981), India's Urban Future · Role of Small and Medium Towns, **Jl. of the Institute of Town Planners, India**, 106, p. 1-7.

33. Dwivedi. R.L. (1963), Origin and Growth of Allahabad, **Ind.Geog. Jl.** 38, 16-32.

34. Dwivedi, R.L. (1964), Delimiting the umland of Allahabad, **Ind. Geog. Jl.** 39, 123-139

35 Dwivedi, R.L (1965), Demographic Features of Allahabad city, **Geog. Rev.** Ind., 27, 163-188

36. English, Paul ward and Mayfield, Robert C. eds (1972), **Man, Space and Environment**, New York : Oxford University Press.

37. Enyedi, G.Y. (1964), Geographical Types of Agriculture, **Applied Geography in Hungary**, Budapest.

38. Farooqi, Z (1987), Spatial system of class IV Towns of U.P. D. Phil dissertation, Allahabad University.

39. Friedman, J. and Alonso, U. eds (1964), **Regional Development and planning : A Reader**, Cambridge Massachusetts, M.I.I. Press

40. Friedman, J., (1966), The Urban Regional frame of national development, **International Development Review**.

41. Friedman, J., (1972), A general theory of Polarised development in N.M. Hansen (ed.) **Growth Centres in Regional Economic Development**, New York.

42 Friedman J., and Doughloss, (1976), Agripolitan Development, Towards a new strategy for Regional development in Asia, Proceedings of the Seminar on Growth Pole strategy and Regional Development in Asia UNCRD, Nagoya, pp. 337-387

43. Friedmann, J., (1988), The Strategy of Deliberate Urbanisation, AIP Journal.

44 Galpin, G. J., (1915), The Social Anatomy of an Agricultural Community, Research bulletin Agricultural Experiment Station University of Wisconsin Madison, Vol 34.

45. Ghosh, B.N., (1955), Fundamentals of population Geography, New Delhi · Sterling Publication.

46. Hansen, N.M. (1974), Public Policy and Regional Economic Development : the experience of nine western countries Cambridge Massachusetts . Ballinger.

47. Harvey, D., (1969), Explanation in Geography, London Edward Arnold.

48. Harvey, D , (1972), Social Justice and the city, London Edward Arnold

49. Harvey, D., (1972), Limits of capital, London : Basil Blackwell.

50. Harvey, D., (1974), What kind of Geography for what kind of public policy ? Transactions, Institute of British Geographers, 63, 18-24.

51 Harvey, D., (1976), The Marxist Theory of the State : **Antipode** 8 (2) 80-9

52. Haggett, P , (1977), **Geography : A modern synthesis**, New York Harper Row.

53. Hardoy, J.E. and Satterthwalte, D. (1981), **Shelter, Need and Response**, New York John Wiley & Sons.

54. Hammond, C.W. (1982), **Elements of Human Geography**, London : George Allen & Unwin.

55. Hermansen, Tormod (1971), **Spatial Organization and Economic Development**, Mysore Int. of Dev. Studies.

56. Hirschman, A.O. (1969), The Strategy of Economic Development, New Haven Yale University Press.

57. Hoselitz, B.F. (1959), Cities of India and their problems, A Review Article, **A.A.A.G.** 49, 223-231.

58. James, Preston (1972), **All possible Worlds**, Indianapolis odyssey Press

59. Jefferson, M. (1931), Distribution of the World's City Folks A study in Comparative Civilization, **Geog. Rev.** 21, 446-465.

60. Jefferson, M. (1939), The Law of Primate City, **Geog. Rev.** 29, 226-232.

61. Johnston, E.A.J. (1970), **The Organization of Space in Developing Countries**, Cambridge, Mass : Harvard University Press.

62. Johnston, R J. (1980), City and Society, London Penguin.

63. Johnston, R.J. (1983), Texts, Actors, and higher Managers, Judges, Bureacrats and the Political Organization of Space, Political Geography Quarterly, 2,3-20

64. Johnston, R.J (1987), Geography and Geographers, London : Edward Arnold.

65. Jones, H.R. (1981), A Population Geography, London and New York Harper and Row

66 King, L.J. (1969), A Quantitative Expression of the pattern of Urban Settlements in selected Areas of United States, Ambrose, P (ed), Analytical Human Geography, London · Longmans, pp. 89 - 102.

67. Kuklinski, A. and R. Petrella (eds), (1971), Growth Poles and Regional Policies, The Hague Mouton.

68. Kuklinski, A R.(ed) (1972), Growth Pole and Growth Centres in Regional Planning, Mouton : Paris.

69. Kuklinski, A.R (ed) (1975), Regional Development and Planning, International Perspectives, The Netherlands.

70. Lanegran, David A. and Palm, Risa (1978), An Invitation to Geography, 2d ed New York . Mcgraw Hill

71. Kayastha, S.L. and Prasad, J. (1978), Approach to area Planning and Development strategy : A case study of Phulpur Block, Allahabad district, N.G.J.I., Vol. 24

72. Kayastha, S.L. and Singh, R B (1980), Emerging dynamics of Integrated Rural development, **N.G.J.I.**, Vol. 26 No.3 & 4

73 Kayastha, S L. and Singh, B.N. (1981), Spatial Strategy for Integrated Rural area development A case study of Ghazipur Tahsil (U.P.), India, **N.G.J.I** , Vol. 27 No. 1 & 2

74. Kumra, V.K. (1980), Environmental Pollution and Human Health A Geographical study of Kanpur City, **N.G.J.I.**, 26, 1 & 2, 60-69

75. Keeble, D. (1967), Models of Economic Development, in R.J. Chorley and P. Hagget (1967), **Models in Geography**, London Methuen.

76. King, L.J. and Clark, G.L. (1978), Government Policy and Regional Development, **Progress in Human Geography**, 2, 1-16.

77. Losch, A. (1954), **The Economics of Location**, (Translated by W H. Waglam & W.F. Stolper) New Haven Yale University Press.

78. Mabogunje, A.L. (1981), Rural development in Nigeria Problems, Policies and issues, in Misra, R.P. (edit) **Rural development : National Policies and Experiences**, Maruzen Asia.

79. Mayfield, R.C. (1967), A central Place Hierarchy in Northern India, **Quantitative Geography** Pt. 1. Economics and Cultural Topics, Illinois PP. 120-66.

80. Misra, H.N. (1975), The Size and Spacing of Towns in the Umland of Allahabad, **The Geogr** , 22

81. Misra, H.N. (1976), Hierarchy of Towns in the Umland of Allahabad, Dec. Geogr., 14, 34 - 47.

82. Misra, H.N. (1977), Empirical and Theoretical Umlands, Allahabad A case study, Geog. Rev. Ind., 39, 312 - 319.

83. Misra, H.N. (1980), Genesis of Small and Intermediate Towns in the Mid - Ganga Valley, Analyt. Geog., 2, 19-28.

84. Misra, H.N. (1981), Rural Roots of Urban Poor : A case study of Informal Sector in an Indian City, in Misra R.P. (edit), Rural Development and National Policies and Experiences, Singapore : Maruzen Asia, 211 - 229.

85. Misra, H.N. (1982), Human Settlement System and Regional Development in a developing Economy : A case study of a Micro-region in North India, in Kammeir, H.D. (etall) (1984) Equity With Growth ? Planning Perspectives for Small Towns in Developing Countries, Bangkok . AIT.

86. Misra, H.N. (1984), Urban System of a Developing Economy Allahabad : IIDR and also in 1988, New Delhi : Heritage Publishers.

87. Misra, H.N. (edit) (1987), Rural Geography, Heritage : New Delhi.

88. Misra, H.N. (1988), Bhutan : Problems and Policies, Heritage : New Delhi.

89. Misra, H.N.(1982) Spatial System of Small and Intermediate Towns, The Geographer, Vol. 27, No.2

90. Misra, H.N. (1981) Simulating the Spatial Pattern of Class II Towns of U.P **Geographical Outlook**, Ranchi

91. Misra, H.N. (1990) Reflections on Indian Urban Geography, Trans. **Institute of Indian Geographers**, Vol. 12, No. 2, 1990.

92. Misra, H.N. (1989) Traditional and Contemporary Paradigms of Urban Geography, **Annals**, NAGI 1989, Vol. 19, No.1.

93. Misra, H N. (1988) Dynamics of Population in Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, **The Geographer**, Vol. 35, No. 1, 1988, pp. 43-53.

94. Misra, H.N. (1987) Role of Small and Intermediate Towns : A Conceptual Frame, The Indian Geographical Journal Vol. 62, 1987.

95. Misra, H.N. et al (1987) An Evolutionary Model of Service Centres in a Slow Growing Economy in Misra, H.N. (edit) **Rural Geography**, Heritage, New Delhi, 1987, pp. 232 - 245.

96. Misra, H.N (1987) Habitat and Health in an Indian Village in Misra, H.N. (edit), **Rural Geography**, Heritage, Nev Delhi, 1987, pp. 191-202.

97. Misra, H.N. (1986), **A Model of Economic Base and its application to the Towns of Uttar Pradesh** in P D Mahadev (edit), **Urban Geography**, Heritage : New Delhi, 1986.

98. Misra, H.N. (1983) Ruralization of Indian Cities A Study in Process of Penetration of Rural Functions in Urban Areas of Slow Growing Economics, **Urban India**, Vol.3, No 3, 1983

and also in K V Sundram, (edit), Geography and Planning, Concept, New Delhi

99. Misra, H N (1983) Informal Sector in Indian Cities .. Case Study of Rickshawpullers, Transaction Institute of Indian Geographers, Vol 5, 1983.

100 Misra, H.N. & Chapman, G P. (1991), Pattern of Growth of India's Class I Cities, Ceoforum (U.K.), Vol. 22, 1991

101 Misra, H.N. (1990) Housing and Health in Three Squatter Settlements in Allahabad, India (Chapter Four) in Jorge E. Hardoy et al (ed) Housing and Health in Third World Cities Earthscan, London, 1990.

102. Misra, H.N. (1968) Popular Settlements in the City of Allahabad, Cities - The International Journal of Urban Policy (U.K.), Vol 5, No.2, 1988.

103. Misra, H.N. (1986) Rae Bareli, Sultanpur and Pratapgarh Districts, (U P.), Northern India (Chapter 5) in Hardoy, J.E and Sattarthwate, D. (ed) Small and Intermediate Urban Centres : Role in National and Regional Development in theThird World, Hodder & Stoughton, London, 1986.

104 Misra, H N. (1986), Technology Transfer and Change . The Case of Three Districts in U.P., Commission on International Division of labour and Regional Development, International Geographic Union, Zaragoza (Spain), 1986.

105. Poverty, Economic Stagnation and Diseases in Uttar Pradesh (Chapter 8) in Tulchin, Joseph, S. (ed) Habitat, Health and Development, Lynne Reinner Publisher, Colorado (U.S.A.), 1986.

106. Misra, H.N. (1984) Human Settlement System and Policy Implications for Regional Development in Developing Economy : in Kammeir H.D. et. al (ed) Planning Perspectives for Small Towns in Developing Countries : AIT, Bangkok, 1984

107. Misra, H.N. (1983) Rural-Urbans in Sudan . A Case Study of Gozira Ekistics - An International Journal of Human Settlement (Greece), Vol. 300, 1983

108. Misra, H.N. (1980) Towards an Alternative Settlement Policy : The Case of India (Mimeo) UNCRD Nagoya, 1980.

109. Misra, R.P. (1971), The Diffusion of Information in the Context of Development Planning, Lund Studies, Series B in Human Geography, No. 27.

110. Misra, R.P. et. al. (1978) Regional Planning and National Development, New Delhi . Vikas.

111. Misra, R.P. et. al (1974), Regional Development Planning in India : A New Strategy, New Delhi : Vikas.

112. Misra, R.P. (edit) (1979), Habitat Asia : Issues and Responses, Vol. 1-3, New Delhi · Concept.

113. Misra, R.P. et. al. (1980), Multi-Level Planning and Integrated Rural Area Development in India, New Delhi · Heritage.

114. Misra, R.P. (1981), Humanizing Development, Singapore Maruzen Asia.

115. Misra, R.P. (1985), Development Issues of Our Time, New Delhi · Concept.

116. Misra, R.P.(1990), District Planning : A Hand book, Concept New Delhi

117. Mitra, A., (1965), Level of Regional Development in India, New Delhi . Government of India.

118. Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under Development, London.

119. Nath, V., (1970), Regional Development in Indian Planning, Economic and Political Weekly, Annual Number, January, pp. 240-260.

120. Nevill, H.R (1904), Pratapgarh : A District Gazetteer, Allahabad · Govt. Press.

121. Perroux, F., (1950), Economic Space . Theory and Application, Quart. Jl. of Economics.

122. Perroux, F., (1955), La Notion de Croissance, Economique Applique Nos. 1 & 2.

123. Preston, R.E. (1971), The Structure of Central Place Systems, Eco. Geog. 47, '2, 136 - 155.

124. Ramesh, A., (1964), Origin and Evolution of Ootaccamund, N.G.J.I, 10, 16 - 28.

125. Rao, V L S P., (1961), The Problems of Metropolitan Region Geographer's Point of View, <u>Jl. of the Inst. of Town Planners</u>, India, 25-26

126. Rao, V L.S P , (1964), <u>Towns of Mysore State</u>, Bombay Asia Publishing House

127 Rao, V L S.P., (1966), Urban Telangana Ekistics, 21

128. Rao, S K , (1973), A Note on Measuring Economic Distances between Regions of India, <u>Economic and Political weekly</u>, 28 April.

129. Ramchandran, H , (1980), <u>Village Cluster and Development</u>, Concept New Delhi.

130. Raza, M., (1980), Regional Development in Historical Perspective, <u>Pariyojan</u>, 'Vol. 1 No. 1.

131 Richardson, H W. (1973) <u>Regional Growth Theory</u>, London Macmillan.

132. Raza, M. et al (1981), India · Urbanization and National Development, in Honzo, M. (edi), <u>Urbanization and Regional Development</u>, Maruzen Asia : Singapore

133. Rondinelli, D.A. (1983), <u>Secondary Cities, in Developing Countries : Policies for Diffusing Urbanization</u>, Sage Publication . Beverly Hills.

134. Salter, Christopher L. (1971) The Cultural landscape Belmont, California Duxburg Press wooldridge, Sidney w. and East w. gordone of geography, New York · Putman.

135. Shukla, I R (1987), Rural Development Alternatives in India, Faizabad District A Case Study, Unpublished D Phil thesis University of Allahabad

136 Singh U (1958), Demographic Structure of Allahabad N.G.J.I. 4, 163 - 188

137 Singh, U (1960) Evolution of Allahabad, N.G.J.I 4 109 0 129

138. Singh, R L (1955), Evolution of Settlements in Middle Ganga Valley N.G.J.I No. 2.

139. Singh R.L. et. al (ed) (1975), Readings in Rural Settlement Geography, Varanasi . N.G.J.I.

140. Singh, L.R (1958), Rural Settlements in the Tarai Region of U P., Nat. Geogr. Vol 3

141. Singh, L.R. (1958), The Role of Geographers in Town Planning, Nat. Geogr. 1

142 Singh J (1971), Rural Settlements Types and Patterns in Baghelkhand, Madhya Pradesh, India, N.G.J.I. Vol 17, No.4.

143. Singh, K N. (1981), Spatial Analysis of Rural Settlements and their Types in Lower Ganga Ghaghra Doab, N.G.J.I Vol 27 No 3 & 4.

144. Singh, O.P., (1971), Relationships of Rank Size and Distribution of Central Places in Uttar Pradesh, Nat. Geogr., 6, 19 30.

145. Sinha, Usha (1983), Service Centres and their Role in the Diffusion of Agricultural Innovations in Karchhana Tehsil of Allahabad District, Unpublished D Phil Thesis, University of Allahabad.

146 Slater, D. (1975), Underdevelopment and Spatial inequality, Progress in Planning, 4, 97 - 167.

147 Stohr, W and Todtling, F., (1977), Spatial Equality - Some antitheses to current regional development doctrine Papers of the Regional Science Association, 38, 33 - 53.

148. Stohr, W and Taylor, D R F, (1980), Development from Above and Below, London John Wiley.

149. Stamp, L D. (1962) The land of Britain, its Use and Misuse, IIIrd Edition, London Longmans.

150. Shafi, M (1960), Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh, Economic Geography, Vol. 36, 4 pp. 296-305.

151. Shafi, M., (1972), Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plain, Geography, Vol. 19, No. 1, pp. 4 13.

152. Smith, D.M. (1977), Human Geography : A welfare Approach, London Edward Arnold.

153. Smith, D.M., (1979), Where the Grass is Greener - Living in an Unequal world, Baltimore The John Hopkins University Press.

154. Stewart, C.T, (1951), The Size and Spacing of Cities, Geog. Rev., 48, 222 - 245.

155. Sundaram, K V , (1977), Urban and Regional Planning in India, New Delhi Vikas.

156 Sundaram, K V., (1983), Geography of under-development New Delhi Concept.

157 Tiwari, A.K. (1982), Spatial Aspects of Rural Development in Indian Desert, The Geographer, Vol 29, No. 2, 26 - 35.

158. Tiwari, P S., (1968), Functional Pattern of Towns in Madhya Pradesh, N.G.J.I. 14, 41 - 54

159. Trewartha, G.T , Chinese Cities Origin and Functions, A.A.A.G 42 69 - 93

160. Ullman E L., (1941), Theory of Location for Cities The American Jl. of Sociology, Vol. 46, 853 - 64

161. Ullman E.L., and Machael F D , (1960) The Minimum requirement approach to the Urban Economic base Reg. Sci Assn. Papers and Proceedings, pp. 175 194

162. Von, Thunen H. (1826), Deriso-lierte State in Bezichung Hug Landwirts Chaft and National Konomic, Rostock Translated by Warteburgh C.M. As Von Thumen's Isolated State, London · Oxford University Press.

163 Woodcock, R.G. and Bailey, M.J , (1978), Quantitative Geography, Macdonald and Evan · Plynouth.

164. Zelinsky, Wilbur (1973), The Cultural Geography of the United States, Englewood Cliffs . New Jersey·Prentice Hall.

165. Zipf, G.K. (1949), Human behaviour and Principle of least effort New York Addison - Wesley Press.

परिशिष्ठ 1 भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धिदर तथा मृत्युदर

1911-20	18 1	48 6	19 4	20 0
1921-30	16 4	36 3	26 9	26 6
1931-40	45 2	31 2	32 1	31 4
1941-50	[illegible]	27 4	32 4	31 7
1951-60	41 7	22 8	41 9	40 6
1961-70	41 2	19 0	46 4	44 7
1971-80	37 2	15 0	50 9	50 0
1981-86	33 2	12 2	55 6	56 4

परिशिष्ट 2 प्रतापगढ़ जनपद मे लिंग अनुपात

वर्ष	जनपद प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	1045	937	972
1951	1059	910	946
1961	1062	909	941
1971	1016	879	930
1981	1016	886	935

स्रोत प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961,

भारतीय जनगणना 1961, 1971, 1981

परिशिष्ट 3 प्रतापगढ जनपद मे विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या मे लिग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर)

विकासखन्ड के नाम	1961	1971	1981
सदर	1094	999	986
लक्ष्मणपुर	1122	1071	1045
मानधाता	1040	1067	1031
स0 चन्द्रिका	1212	1061	1036
सांगीपुर	1120	1013	1004
कुन्डा	1045	940	985
कालाकाकर	965	968	980
बाबागंज	1036	1032	1013
बिहार	1051	1019	988
रामपुरखास	1056	1018	1004
पट्टी	1068	1021	1045
गौरा	1088	1050	1035
शिवगढ	1096	1062	1040
मगरौरा	1057	1035	1023
आसपुरदेवसरा	1038	933	1027

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हेन्ड बुक, 1961-81

परिशिष्ठ 4 प्रतापगढ जनपद मे व्यावसायिक वर्गो मे कार्यरत जनसख्या का प्रतिशत

वर्ग	1961	1971	1981	
कृषक	69 3	61 6	55 65	प्राथमिक व्यवसाय
कृषक मजदूर	17 8	26 0	28 84	" "
उत्खन्न मछली पालन पशुपालन, वृक्षारोपण।	0 14	0 9	-	" "
पारिवारिक उद्योग	5 4	3 4	2 9	द्वितीयक व्यवसाय
गैर पारिवारिक उद्योग	0 5	1 0	-	" "
व्यापार तथा वाणिज्य	2 1	2 4	-	" "
परिवहन एव सेवाए	0 64	0 4	-	तृतीयक व्यवसाय
अन्य सेवाये	4 0	5 0	13 6	" "

स्रोत प्रतापगढ डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्ड बुक 1961-81

परिशिष्ठ 5 प्रतापगढ जनपद मे उद्योगों की सख्या

वर्ष	1979-80	1984-85
वृहत उद्योग	4	6
दैनिक कार्यरत व्यक्ति	126	830
लघु उद्योग	185	347
दैनिक कार्यरत व्यक्ति	659	1397

जिला साख्कीय पत्रिका 1980, 1987